हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

09 मार्च, 2021 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 09 मार्च, 2021(प्रथम बैठक)

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अनुपस्थिति की अनुमति

ध्यानाकर्षण सूचना–

भिवानी जिले में पानी की भारी कमी से संबंधित

वक्तव्य–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्मदिन पर बधाई

हरियाणा विधान सभा के एक सदस्य की अयोग्यता से सम्बन्धित सूचना

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं/लड़कियों को बधाई

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्बन्धित सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

निजी सदस्य विधेयक के मामले को उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

सरकारी संकल्प–

(i) कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने से संबंधित प्रस्ताव

(ii) हरियाणा, लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने से संबंधित प्रस्ताव

बैठक का समय बढ़ाना

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)–

(iii) हरियाणा, खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापिस लेने से संबंधित प्रस्ताव

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य–

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक–

1. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2021
2. दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2021

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)–

3. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021
4. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 09 मार्च, 2021 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है ।

Total Fund for SC Category under Component Plan

***869. Shri Ishwar Singh:** Will the Welfare of SCs and BCs Minister be pleased to state-

(a) the total amount allocated for the scheduled caste category under the component plan in the last 2 years in State together with the method of allocation thereof;

(b) whether it is a fact that the graph for not spending the component plan fund completely for the development of scheduled castes is increasing continuously; and

(c) whether the Tribal Sub Plan and Special Component Plan have been prepared by the State together with the details thereof?

सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : श्रीमान् जी,

(क) राज्य में गत् दो वर्षों में अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0) के तहत 14977.47 करोड़ रू0 की राशि वर्ष 2018–19 में और वर्ष 2019–20 में 7610. 18 करोड़ रू0 की राशि आंवटित की गई थी । योजना विभाग अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं की पहचान और आबंटन के लिये जिम्मेदार है, जोकि नीति आयोग के अनुसार योजनाओं और राशि के चयन के लिये विस्तृत मापदंडों के अनुसार किया जाता है जो एस0सी0एस0पी0 के अंतर्गत आते हैं। योजना विभाग एस0सी0एस0पी0 कार्यान्वन से सम्बंधित सभी विभागों को राशि आबंटित करता है । अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग योजनाओं के कार्यान्वन की निगरानी करने वाला नोडल विभाग है ।

(ख) नहीं श्रीमान् जी।

(ग) अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0) नीति आयोग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार, कार्यान्वन और निगरानी की जा रही है। जनजाति उप योजना राज्य द्वारा नहीं तैयार की जाती क्योंकि हरियाणा के लिये कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है।

श्री ईश्वर सिंह : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया कि यह फंड अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आया है । वर्ष 1975 में सैंटर गवर्नमैंट द्वारा आदिवासियों के लिए एक कंपोनैंट प्लान तैयार किया गया था । उसको 'ट्राइबल सब प्लान' कहा जाता है । माननीय मंत्री जी ने 'ट्राइबल सब प्लान' को तो अपने जवाब में टच ही नहीं किया । उसके 4 साल के बाद वर्ष 1979 में 'स्पैशल कंपोनैंट प्लान' बनाया गया । उसमें कहा गया कि यह पैसा सिर्फ एस.सी. कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए ही दिया जाएगा । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह डिटेल नहीं दी कि यदि किसी ढ़ाणी की, किसी मोहल्ले की या किसी कोलोनी की 33 प्रतिशत आबादी एस.सी. कैटेगरी के लोगों की है तो यह पैसा सिर्फ वहां के लिए दिया जाएगा । मेरा सवाल यह है कि यह प्रावधान तो कर दिया कि बजट में यह धनराशि आबंटित की जाएगी परंतु आज भी स्थिति ऐसी है कि हमने जब इसकी डिटेल मंगवाई तो पता लगा कि पैसा ठीक हिसाब से नहीं बंट रहा है । अध्यक्ष महोदय, पैसे के आबंटन करने में कई टैक्नीकल चीजें हैं । यह पैसा एस.सी. कैटेगरी के व्यक्तियों की बस्तियों के अन्दर सड़क, पार्क, स्कूल, तकनीकी शिक्षा विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र में दवाइयां देने आदि वैलफेयर के कामों के लिए दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, 'स्पैशल कंपोनैंट प्लान' के तहत दिये जाने वाले पैसे का 40 परसैंट पैसा तो आज भी आबंटित नहीं हो रहा है । (विघ्न) मेरा सवाल यह है कि सरकार ने बजट में इसका प्रावधान तो कर दिया लेकिन यह पैसा जिस परपज के लिए आबंटित हुआ था उस पैसे से वह परपज पूरा नहीं हुआ । यह बहुत बड़ा विषय है । इसके तहत केवल 60 परसैंट पैसा ही बांटकर बाकी का 40 परसैंट पैसा आबंटित नहीं किया गया है । इसके अलावा जो पैसा आबंटित होता है उसका भी ठीक तरह से प्रयोग नहीं किया जाता । माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग–ख के जवाब में कहा कि नहीं, श्रीमान जी । ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । मेरा कहना है कि जो पैसा आबंटित होता है वह सारा पैसा पुल बनाने, सड़कें–गलियां बनाने, नहर बनाने आदि में लगा दिया जाता है । विभागीय अधिकारी यह कहते हैं कि उन पैसों से जो पुल बनाया गया है उसके ऊपर से एस.सी. कैटेगरी के लोग भी निकलते हैं और जो नहरें बनायी गयी हैं उनका पानी भी एस.सी. कैटेगरी के लोग पीते हैं। यह जो एस.सी. कम्पोनैंट प्लान के लिए बजट अलॉट किया गया था, उसको दूसरे कार्यों में लगाया गया है। इसकी डिटेल दी जाए। दूसरी बात यह है कि बाकी 40 प्रतिशत पैसा अभी तक आबंटित क्यों नहीं किया गया है ?

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पिछले 5 सालों का रिकार्ड है। उसके अनुसार वर्ष 2015–16 के अन्दर बजट में जो प्रावधान किया था उसमें 4398.96 करोड़ रुपये में से 3,389 करोड़ रुपये रिलीज हुए थे और यह पूरा बजट खर्च हो गया था। वर्ष 2016–17 में 5898.97 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था और उसमें से 4892.51 करोड़ रिलीज हुए थे और यह भी पूरा बजट खर्च हो गया था। वर्ष 2017–18 में 7019.98 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था और उसमें से 5945.01 करोड़ रुपये रिलीज किये गये थे और यह भी पूरा बजट खर्च हो गया। वर्ष 2018–19 में 7,367 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था और उसमें से 5,980 करोड़ रुपये रिलीज हुए थे और यह भी पूरा बजट खर्च हो गया था। वर्ष 2019–20 में 7610.18 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था और उसमें से 6626.75 करोड़ रुपये रिलीज हुए थे और यह पूरा बजट खर्च हो गया था। इस प्रकार जो बजट अलॉट हुआ था उसमें पूरे पैसे खर्च किये गये हैं और यह दूसरी स्कीम्ज में डायवर्ट नहीं होता। ये कॉमन यूटीलिटीज हैं, इसलिए इनको अलग–अलग नहीं किया जा सकता। इसमें सभी के लिए परसैंटेज के हिसाब से बजट डाला जाता है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, विभाग के पास जो पैसा आता है, वह तो पूरा खर्च करना ही होता है। इसमें जो पैसा अलॉट नहीं हुआ था, वह पैसा कहां पर है ? इसके कारण जो परपज था, वह पूरा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने हर साल के बजट के बारे में बता दिया है कि जितना पैसा आया था, वह खर्च कर दिया है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब फाईनेंस मिनिस्टर ही दे सकते हैं कि जो 40 प्रतिशत पैसा एस.सी. कैटेगरी के लिए आया था, वह अलॉट क्यों नहीं हुआ ? विभाग तो जो उसके पास पैसा आएगा, उसको ही खर्च करेगा। इसमें जो बाकी पैसा रह गया है, उसको आबंटित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि जितना बजट में प्रावधान किया गया था, वह सारा का सारा बजट खर्च किया जा चुका है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो बजट का प्रावधान किया गया था, उसमें से सारा पैसा खर्च नहीं हुआ है। विभाग ने तो सिर्फ जो पैसा अलॉट हुआ था, उसको ही खर्च किया है। इन्होंने जो प्रावधान किया था उसमें से 40 प्रतिशत पैसा बच गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल का पूरा बजट खर्च नहीं हुआ है।

इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि यह 40 प्रतिशत पैसा क्यों बचा हुआ है ?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर यह बताएं कि जो 40 प्रतिशत पैसा आबंटित नहीं किया गया था, क्या वह खर्च हो गया है, ताकि हम उसको चैक कर सकें। माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी से जो सवाल पूछा है उसका पूरा जवाब दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, माननीय मंत्री जी ने उसका रिप्लाई दे दिया है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का अधूरा रिप्लाई दिया है।

डॉ0 बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, यह जो 40 प्रतिशत बजट कम पैसा रिलीज हुआ है उसके लिए अगली बार ध्यान रखा जाएगा और पूरा पैसा रिलीज किया जाएगा।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो पैसा रिलीज हुआ है, उसको खर्च किया जाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि पूरा पैसा क्यों रिलीज नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि वह आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने जो इशू रेज किया है, उसके लिए उन्होंने एश्योर किया है कि वह आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसको एश्योर कैसे कर सकते हैं? जो पैसा आएगा, वह तो फाईनैंस डिपार्टमैंट द्वारा ही दिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, डॉ0 बनवारी लाल जी विभाग के माननीय मंत्री हैं और इस काम को यही करेंगे और कौन करेगा ? आपने सवाल माननीय मंत्री जी से पूछा है, इसलिए ये उसका जवाब दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में इन्टरवीन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने विषय उठाया है कि जो पैसा अलॉट हुआ था, उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा खर्च नहीं हुआ है ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दे दिया है। अब विषय यह है कि वह पैसा अलॉट क्यों नहीं हुआ ? यह बजट से जुड़ा हुआ विषय है। चूंकि पिछले साल का बजट एलोकेट कर दिया था। यह पिछले साल का विषय था कि वह बजट एलोकेट क्यों नहीं हुआ ? अगली बार जब बजट पर चर्चा होगी तो इस विषय पर

चर्चा कर लेंगे क्योंकि यह विषय उस समय का है। उस समय जब माननीय सदस्य इस विषय को उठाएंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

.....

To Renovate the Building of PHC

***912. Shri Jagdish Nayar :** Will the Health Minister be Pleased to state whether it is a fact that the Building of Primary Health Centre of Hasanpur in Hodal Constituency is in bad condition; if so, the time by which it is likely to be renovated

Health Minister (Shri Anil Vij): Yes Sir, the proposal of renovation of Primary Health Care Centre of Hasanpur is under process and no time limit can be given at this stage.

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हसनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत खराब हो चुकी है, उसको कब तक बनवा दिया जायेगा क्योंकि बहुत दिनों से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडहर पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों को इलाज करवाने के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको काफी असुविधा होती है। पहले उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की कोई कमी नहीं होती थी लेकिन आज वहां पर एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर स्टाफ की भी व्यवस्था की जाये और इस भवन को तोड़कर वहां पर दूसरा भवन बनाने का काम किया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को बनाने के लिए ड्राइंग अप्रूव कर ली गई है और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को इसके लिए ऐस्टीमेट भी बनाने के लिए भेज दिया गया है। इस प्रोसैस के पूरा होने में एक–दो महीने का समय लग जायेगा। उसके बाद हम जल्दी ही हसनपुर की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा करवा देंगे।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र के दौरान मैंने पिपली में ट्रॉमा सैंटर बनाने का मुद्दा उठाया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था।

इस कार्य के लिए उन्होंने मेरी ड्यूटी भी लगाई थी कि अगर ट्रॉमा सैंटर के लिए पंचायत से जमीन दिलवा देंगे तो वहां पर ट्रॉमा सैंटर बना दिया जायेगा और मैंने पंचायती जमीन दिलवाने के लिए संबंधित पंचायत को एक रैजोल्यूशन पहले ही सौंप दिया था लेकिन बावजूद इसके इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने इस महान सदन में कल भी इस बारे में बताया था कि हम जो एश्यौरैंस देते हैं, वह एश्यौरैंसिज एश्यौरैंस कमेटी में चले जाते हैं। उसके बाद संबंधित डिपार्टमैंट द्वारा उस एश्यौरैंस पर कार्रवाई करने का काम किया जाता है। अगर इस महान सदन में माननीय सदस्य इसके लिए अलग से क्वैश्चन लगायेंगे तो मैं उनको इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा।

———————

To Install 33 K.V. Power House

***936. Shri Shamsher Singh Gogi**: Will the Power Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement has been made by the Government to construct 33 K.V. Power House in Assandh City; if so, the details of the progress report thereof togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी, जीवन चानन रोड, असंध में नया 33 के.वी., सब–स्टेशन निर्मित करने का कार्य 20.03.2020 से प्रगति पर है तथा अब तक इसका 60 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया है । इस सब–स्टेशन को पूर्ण करने की संभावित तिथि मई, 2021 है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि असंध शहर में 33 के.वी. बिजली घर का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि रिप्लाई में लिखा हुआ है कि इस सब–स्टेशन को पूर्ण करने की संभावित तिथि मई 2021 है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह काम मई 2021 में पूरा हो जायेगा क्योंकि अभी तक आधा काम भी नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को विभाग की तरफ से पूरी जानकारी नहीं दी गई है और इनको गुमराह करने का भी काम किया गया है। चाहे तो आप अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से पूछ सकते है कि असंध में सब–स्टेशन बनाने का काम कब शुरू हुआ था। अगर यह काम पिछले मार्च 2020 में शुरू हुआ होता तो

फिर मुझे इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि असंध शहर में सब–स्टेशन बनाने का काम कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है और वहां पर अभी तक सिर्फ इस सब–स्टेशन की बिल्डिंग ही खड़ी हो पाई है, बाकी सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस सब–स्टेशन से पूरे शहर को बिजली सप्लाई होनी है। मेरी इसके अलावा रिक्वैस्ट है कि आजकल जो लोड बढ़ाने का काम बिजली विभाग कर रहा है। मैं उस बारे में सम्पलीमैंटरी पूछना चाहता हूं। किसानों से जो फार्म साइन करवाया जाता है, कुछेक किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण वे बिना समझे ही उस फार्म पर साइन कर देते हैं और उसके बाद फ्लैट रेट सिस्टम की जगह उनको मीटर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। जिन किसानों के पास ट्यूबवैल के कनैक्शन हैं उनके बिजली बिल के फ्लैट रेट सिस्टम को हटाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है आप इसको चैक करने का काम करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गड़बड़ी होने की आशंका है, जिससे आने वाले समय में किसानों को बहुत तकलीफ होगी।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगा कि असंध शहर में सब–स्टेशन का निर्माण कार्य देरी से क्यों शुरू हुआ उसके क्या कारण थे? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारे सामने लैंड डिस्प्यूट का मामला सामने आया था, अब हमने इसको सैटल कर दिया है और इस सब–स्टेशन का दोबारा काम होना शुरू भी हो गया है। इस काम को एक century infrapower pvt. Ltd jaipur की कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इस सब–स्टेशन का काम 60 परसैंट कम्प्लीट हो चुका है। इसका कार्य दिनांक 20.03.2020 को अलॉट हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आपको भी इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि पिछले मार्च–अप्रैल के महीने में देश और प्रदेश में कोविड–19 वैश्विक महामारी आ गई थी जिसके कारण इस काम को बंद कर दिया गया था इसलिए कम्पनी को इस काम के लिए 6 महीने का और टाइम दिया गया था।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय मंत्री जी की बात को मान लिया है कि सब–स्टेशन के निर्माण कार्य में देरी हुई है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके निर्माण कार्य को जल्दी ये जल्दी पूरा करवाया जाये। माननीय मंत्री जी ने अपनी बात में यह भी कहा है कि इसका निर्माण कार्य मई, 2021 तक पूरा हो जायेगा। अगर इसका निर्माण कार्य मई, 2021 तक पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से दूसरी रिक्वैस्ट

यह है कि जो फ्लैट रेट सिस्टम का मामला है, वह बहुत सीरियस मामला है इसलिए इस पर भी ध्यान देने का काम किया जाये।

———————————

To Drain Out Dirty Water

***801. Shri Indu Raj Narwal**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the steps taken by the Government to drain out the dirty water in villages Kathura, Baroda, Butana, Gangana, Shamri, Chidana, Mudlana, Ghadwal, Bhawar and Rindhana of Baroda Assembly Constituency?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान् जी, बडौदा विधानसभा क्षेत्र के पाँच गावों बुटाना, गंगाना, शामरी, मुण्डलाना व चिड़ाना के कार्य पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं तथा कार्य प्रगति पर हैं। शेष पाँच गांवों कथूरा, बरोदा, घड़वाल, भांवर तथा रिंधाना हेतु प्राक्कलन बनवाए जा चुके हैं तथा कार्य अगले वित्तीय वर्ष में लिया जाना प्रस्तावित है।

श्री इन्दू राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्का बरोदा में कई बड़े गांव हैं और इन गांवों में गंदे पानी की निकासी के लिए सरकार द्वारा क्या कोई बजट का प्रावधान किया गया है? मुझे इस बारे में बताया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री इन्दु राज जी को बधाई देता हूं कि वे इस महान सदन में नये सदस्य चुनकर आये हैं और इनका पहली बार सवाल भी लगा है। इनके हल्के में गांव बुटाना, गंगाना, शामड़ी, चिडाना, मुडलाना में गंदे पानी की निकासी के लिए ऑलरेडी प्रोजैक्ट ''रिवर यमुना एक्शन प्लान'' और ''स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण'' योजना के दूसरे फेज–वन के तहत काम चल रहा है। इसकी लागत 2.80 करोड़ रुपये है। गांव भावड़ और रिंधाना में ''रिवर यमुना एक्शन प्लान'' और ''एन.जी.टी.'' के तहत गंदे पानी की निकासी के कार्यों पर 1.85 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। जो पांच गांव कथूरा, बरोदा, घड़वाल, भावड़ और रिंधाना में एडीशनल कार्यों के लिए 3.80 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट बना दिया गया है और इनके कार्य भी जल्द ही शुरू करवा दिये जायेंगे।

श्री इन्दु राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि इन गांवों में गंदे पानी की निकासी के कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक बार पंचायती कार्यों के लिए प्रतिबंध लगाया गया था जो कि कल शुरू किया गया है। हम इन कार्यों को करने के लिए ई–टेंडर भी करवायेंगे और इन कार्यों को शीघ्र ही पूरा करवाने का काम किया जायेगा। हमारी पार्टी का भी बरोदा विधान सभा क्षेत्र से काफी लगाव रहा है और इस क्षेत्र में विकास कार्यों की कभी कमी नहीं रहने दी जायेगी।

.....

To Start Construction Work of Highway

***863. Shri Rao Dan Singh**:

Dr. Abhe Singh Yadav: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the reasons for which the construction work of State-Highway of Mandola to Narnaul has been delayed; and

(b) the steps taken by the Government for speedy construction of abovesaid highway?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) Four laning of this road was part of work awarded to M/s IVRCL on 23.01.2012 on DBFOT basis. However, work was terminated and BG encashed on 31.01.2014. Subsequently, road was declared as National Highway vide notification dt. 09.04.2015 and four laning project formulated and submitted to MoRT&H for approval. In the meantime, the road was entrusted to NHAI vide notification dated 01.09.2017 and NHAI did not take up four laning of this road on account of construction of parallel Ismailabad-Narnaul Greenfield Highway. The road stretch is no more a National Highway after Govt. of India notification dated 18.06.2020 and works are being taken up through State funds.

(b) Work for patchwork of the road falling in Mahendergarh District and Charkhi Dadri district is in progress and likely to be completed by 14.06.2021 and 15.05.2021 respectively. Four laning of the road falling in Mahendergarh district is under consideration of Government. Work of widening from 7 to 10 meter of the road falling in Charkhi Dadri district has been administratively approved on 01.03.2021 and tenders are being invited.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह क्वैश्चन राव दान सिंह और डॉ. अभय सिंह यादव का ब्रैकिटेड क्वैश्चन है।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा एवं कहना चाहूंगा कि मैंने यह प्रश्न पिछली बार भी इस महान सदन में पूछा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में इसी सदन के अंदर आश्वासन दिया गया था कि इस रोड को नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जायेगा अगर नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रोड को नहीं बनायेगा तो हरियाणा सरकार द्वारा इस सड़क पर फोर लेनिंग करने का काम किया जायेगा। इस सड़क को बनाने बारे कहा जा रहा है कि 152–डी ग्रीन रोड बना रहे हैं। अब इस रोड के बारे में एन.एच.ए.आई. ने कहा है कि हम दूसरा पैरेलल रोड नहीं बना सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि उस रोड की दूरी इससे 8 किलोमीटर पर है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा निवदेन है कि सरकार महेन्द्रगढ़ के रोड को भी बाई पास करने काम कर दे। महेन्द्रगढ़ में झज्जर से नारनौल रेल आ रही है उसको भी बाई पास करने का काम कर दे। महेन्द्रगढ़ नैशनल हाइवे को डिनोटिफाई करके स्टेट हाईवे बनाने का काम कर दे। महेन्द्रगढ़ में आई.एम.टी. है, उसको हटाकर के आई. आई.टी. बनाने का काम कर दे। इस बारे में मेरा यही कहना है कि आखिर महेन्द्रगढ़ की जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो इनकी बार–बार इतनी उपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी का क्षेत्र भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उस क्षेत्र के बारे में सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 7 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ा करने का प्रस्ताव दिनांक 01.03.2021 को पारित कर दिया गया। एक तरफ तो सरकार यह मान रही है कि इसको फोर लेनिंग बनाने के लिए प्रस्तावित है और दूसरी तरह यह कहा जा

रहा है कि 7 मीटर से 10 मीटर इसको बनाने जा रहे हैं। वहां पर इतना हैवी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से वहां पर सैंकड़ों मौतें हो चुकी हैं। अगर सरकार को मेरी बात का यकीन नहीं है तो पिछले वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देख सकती है। इसकी वजह से लोगों की गाड़ियां का एक्सीडेंट्स होना, पैट्रोल और डीजल की बर्बादी होना और उनके समय का भी दुरुपयोग होने का उनको नुकसान उठना पड़ रहा है। हैवी ट्रैफिक और धूल उड़ने की वजह से बहुत से लोगों को तो टी.बी. की भी बीमारी हो गई होगी लेकिन बावजूद इसके सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि इस कार्य को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाये न कि इसको टालने के लिए लिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि माननीय सदस्य को मुझ से ज्यादा इस बात ज्ञान है लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में एन.एच. 148 (बी) और 709 (ई) बनने लगा है क्योंकि यह पहले नैशनल हाईवे था। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखित तौर पर दिया है कि इसको डिनोटिफाई किया जाये और इस पैच को पिछले साल के छठे महीने में नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिनोटिफाई कर दिया है लेकिन इसकी अभी हैंडिंग ओवर नहीं हुई है। हमारी सरकार ने बावजूद इसके इस पूरे टुकड़े पर एक स्पैशल पैकेज के तौर पर पैचवर्क का कार्य शुरू किया है। जो अगले महीने के अंत तक कम्पलीट हो जायेगा। जहां दादरी से महेन्द्रगढ़ सड़क के पैचवर्क की बात है उसके लिए हमारी सरकार ने 17.70 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं और इसको for the time being State fund से बना लिया जाये अभी फिलहाल इसको फोर लेनिंग करके 7 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ा किया जाये। माननीय सदस्य की जो सोच है सरकार उसके प्रति कायम है और मैं इनको ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन देता हूं कि जैसे ही इसकी हैंडिंग ओवर होगी हमारी सरकार स्टेट फंड से इस पूरे पैच वर्क को फोर लेनिंग बनाने का काम करेगी।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने दादरी महेन्द्रगढ़ सड़क के पैचवर्क के बारे इस महान सदन को बताया है और राव दान सिंह जी के सड़क के साथ–साथ और भी कई दर्द बाहर निकलकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़क की बात है तो वास्तव में आज के दिन सड़क की बहुत ही खराब हालत है और महेन्द्रगढ़ शहर के सड़क का जो हिस्सा है। उस

सड़क के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और सारा दिन उस सड़क पर ट्रैफिक चलता है जिसके कारण काफी रेत उड़ती रहती है। उन दुकानदारों की बहुत हिम्मत है कि वे सारा दिन दुकानों में बैठे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को टुकड़ों में न बनायें। सरकार अगर भिवानी जिले से महेन्द्रगढ़ बॉर्डर तक सड़क के 10 मीटर टुकड़े के पैचवर्क का कार्य कर रही है तो मैं समझता हूं कि 10 मीटर के सड़क के टुकड़े पर पैसे खर्च करने के बजाए डायरेक्टली फोर लेन का काम करवाया जाये तो बेहतर रहेगा। मैं समझता हूं कि सड़क के पैचवर्क का काम करवाने से दो–चार महीने तक तो सड़क चलने लायक हो जायेगी परन्तु उससे काम नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार फिलहाल इस 10 मीटर के टुकड़े को चौड़ा करने का काम तो कर रही है लेकिन इसके तुरन्त बाद ही फोर लेनिंग बनाने का काम शुरू कर देगी। जो कि मैं समझता हूं कि इस प्रकार से तो सरकारी पैसे की बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जायेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस को चौड़ा न करके फोर लेनिंग का काम शुरू करवाया जाये तो बेहतर होगा। मेरा इस संबंध में सरकार से यही निवेदन है कि इसको डायरेक्टली फोर लेन बनाने का प्रपोजल बनायें। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि इस कार्य को पूरा बनाया जाये, इसको पार्टस में न बनाये इससे प्रदेश की जनता में गलत मैसेज जायेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जिले की बाउंड्री पर सड़क बना दी और दूसरे जिले की बाउंड्री पर सड़क नहीं बनाई। मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश की जनता में अच्छा संदेश नहीं जायेगा। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी प्रपोजल बनाकर फोर लेन का काम यथाशीघ्र शुरू करवाने का काम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह जी ने जो बात रखी है वह बिल्कुल सही है कि यह काम पैचिज में न किया जाए। दादरी से महेन्द्रगढ़ के बीच का कार्य चल रहा है उसके अन्दर पिछली सरकार को इमीडियेटली स्टैप लेना पड़ा क्योंकि माइनिंग सैक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस सड़क का इस्तेमाल करता है। निरन्तर एक्सीडैंट्स भी हुए हैं और आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी किसी सदस्य ने यह बात उठाई थी। इसको हमें इमीडियेटली टेकअप करना पड़ा। जैसे ही यह हैंडओवर होगा पूरे फेज में हम इस प्रोजैक्ट को स्टेट फंड से डिवैल्प करेंगे।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कल उन्होंने 4–5 जगहों के बाईपास का जिक्र किया था कि वे निर्माणाधीन हैं और किसी का 70 प्रतिशत, किसी का 80 प्रतिशत तथा किसी का 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। मेरा एक निवेदन है कि जब आप दादरी–महेन्द्रगढ़ रोड को फोरलेन बना रहे हैं तो महेन्द्रगढ़ के बाईपास को भी कंसीडर करें क्योंकि शहर बढ़ रहा है और सड़क के दोनों और रिहायशी मकान बन गये हैं। जमीन पहले ही एक्वायर हो चुकी है इसलिए सरकार को केवल टैंडर ही करना है। सरकार को ज्यादा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर सरकार इस काम को करना चाहेगी तो बहुत जल्द यह काम हो जायेगा।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

————————

Shortage of Doctors

***1029. Shri Devender Singh Babli:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Civil Hospital of Tohana is facing shortage of Doctors for the last many years; and

b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint specialist doctors in the abovesaid hospital togetherwith the time by which the vacant posts of the doctors are likely to be filled up?

Health Minister (Shri Anil Vij) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी मैंने हाउस में यह प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री जी ने मुझे यहां सदन में आश्वस्त किया था कि जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर किया जायेगा। मंत्री जी ने वहां पर डॉक्टर भेजे भी थे। लेकिन वहां पर डॉक्टरों के रहने के लिए जो रिहायशी मकान बने हुए हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उसी के कारण वहां पर कोई डॉक्टर रुकता नहीं है। जो डॉक्टर टोहाना में भेजे गये थे वे अपनी ट्रांसफर करवा कर चले गये इसलिए मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाये क्योंकि यही मेन कारण है जिसकी वजह से वहां पर डॉक्टर टिक नहीं पाते। इसी कारण से हमारे टोहाना को जो सरकारी हॉस्पिटल और डॉक्टरों की सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यह है कि आपने पिछले विधान सभा सत्र में मुझे आश्वस्त किया था कि हमारे टोहाना में जो 50 बैड का हॉस्पिटल है उसको 100 बैड के हॉस्पिटल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव था और इस बारे में मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह काम बहुत जल्द हो जायेगा। लेकिन वह फाइल वहीं की वहीं है। न ही तो वहां पर काम शुरू हुआ और न ही डॉक्टरों की कमी दूर हुई। टोहाना की जनता इस समस्या से जूझ रही है। वह जनता आज से नहीं जूझ रही है बल्कि इस समस्या से जूझते हुए जनता को 2 से 3 दशक हो गये हैं। इस बारे में मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक तो डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाये तथा जो 50 बैड का हॉस्पिटल टोहाना में उपलब्ध है उसको अपग्रेड करके 100 बैड का हॉस्पिटल समयबद्ध तरीके से बनाया जाये ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास डॉक्टरों की 4156 सैंक्शंड पोस्ट्स हैं जिसमें से 1056 वैकेंट हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि 200 डॉक्टर तो हमें 60:40 की रेशो में अपना क्लेम कायम रखने के लिए चण्डीगढ़ को देने पड़ते हैं। लगभग 200 डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं और जब हम भर्ती करते हैं तो रिजर्व केटेगरी के लगभग 200 डॉक्टर शॉर्ट रह जाते हैं वे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हम जो चण्डीगढ़ की ऑब्लीगेशन बीयर कर रहे हैं उस बारे में वित्त विभाग को लिखा है कि हमारी रेगुलर पोस्ट्स को स्ट्रैन्थन करने के लिए हमें चण्डीगढ़ के लिए अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जायें। उसको हमारी रेगुलर पोस्टों में मत लें क्योंकि हमें वहां पर अपनी पोलिटीकली स्ट्रैंथ रखनी पड़ती है और अगर वह हम रेगुलर स्ट्रैंथ में से निकालकर देते हैं तो किसी न किसी अस्पताल में, किसी पी.एच.सी. में, किसी सब डिवीजनल होस्पिटल में कोई न कोई कमी होती हैं। हमारे पास जो 400–500 डॉक्टर्ज की कमी है हम उनको जल्दी ही भरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज की बात की है वह सच में ही बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हमने निर्णय लिया है कि हम स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज का अलग कैडर क्रियेट करेंगे क्योंकि अभी तक स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज का अलग कैडर नहीं है। अब

तक जो भर्ती होती है वह एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्ज की ही होती है। उनमें जो स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज आ जाते हैं उनको स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज बना दिया जाता है। हम चाहते हैं कि स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज की भर्ती अलग हो। उसमें जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हम भर्ती करें और उनको जो वेतनमान है वह भी हम लाभप्रद रखना चाहते हैं ताकि वे डॉक्टर्ज आएं और छोड़कर न जाएं। स्पीकर सर, ये सब कमी होने के बावजूद भी हैल्थ डिपार्टमैंट ने काफी प्रोग्रैस की है। किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की का अंदाजा उसके हैल्थ इंडीकेटर से लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, जरा अपनी रिप्लाई शॉर्ट में दें। जरा आप उनको एश्योरैंस दे दें क्योंकि बाकी प्रश्न रह जातें हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं बताउंगा लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल तो बतानी पड़ती है। जब हमारी सरकार आई तब जो एम.एम.आर. है वह 127 थी। अब वह घट कर 91 हो चुकी है। यानि 28 प्रतिशत कम हुई है। एन.एम. आर. 26 थी वह अब 22 रह गई है। यानि उसमें माइनस 15.38 प्रतिशत की कमी आई है। जो आई.एम.आर. है वह 41 था वह घट कर अब 30 हो गया है। यानि इसमें 26 प्रतिशत की इम्प्रूवमैंट है। जो सैक्स रेशो है वह 868 थी जो अब बढ़कर 918 हो गई है। यानि इसमें 5.45 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, बात ये है कि ये लोग अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, अच्छी बात सुनाना नहीं चाहते, अच्छी बात बोलना नहीं चाहते और अच्छी बात देखना नहीं चाहते।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे टोहाना में जो डॉक्टर्ज व स्टाफ की कमी है उसके बारे में वे मुझे आश्वासन दें कि वे कितने समय में उस कमी को पूरा कर देंगे। पिछली बार भी भर्तियों की बात की गई थी जिसमें पिछली बार भी आपने आश्वस्त किया था कि नई भर्तियां हो रही हैं और आपके टोहाना में जल्द से जल्द स्टाफ पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस होस्पीटल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके आए थे उस होस्पीटल का काम कब से शुरू किया जाएगा। मंत्री जी, मैं बार–बार आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे टोहाना में डॉक्टर्ज की कमी को कब तक पूरा करेंगे और उस होस्पीटल की नींव कब रखने

आएंगे ताकि मैं आपके स्वागत की तैयारी करूं। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी बी.जे.पी. की सरकार की घोषणा को पूरा कीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) यह सारा हैल्थ डिपार्ट यहां डिस्कस नहीं होना है। यहां केवल पर्टिकुलर प्रश्न डिस्कस होगा। (शोर एवं व्यवधान) आगे जब नम्बर आएगा तभी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जितने मैडिकल कालेजिज हैं उनमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं और वहां से पास होकर निकलते हैं आप उनसे लिखवाया करें कि पांच साल उनको सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी या रूरल एरियॉज में जाना ही पड़ेगा। जब 10 लाख रूपये का बॉंड भरवाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कम से कम यह तो जरूर निश्चित होना चाहिए कि इन डॉक्टर्ज की सेवाओं का लाभ हरियाणा के लोगों को मिले।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं बहन किरण जी को बताना चाहूंगा कि इस बार जो बॉंड भरवाया गया है उसमें लिखवाया गया है कि डाक्टर बनने के बाद, डॉक्टर्ज को सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी।

.....

Completion of Roads

***785. Shri Rakesh Daultabad :** Will the Chief Minister be pleased to state the sector wise and location wise details of incomplete 24 meter roads in sector 58 to 115 of Gurugram togetherwith the time by which these are likely to be constructed/ completed alongwith the details thereof ?

@मुख्यमंत्री (मनोहर लाल) : सर, उत्तर विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

गुरूग्राम के अंतिम विकास योजना, 2031 के अनुसार सैक्टर – 58 से 115 में कुल 299 किलोमीटर लंबाई की 24 मीटर आंतरिक सडकें प्रस्तावित हैं। उपरोक्त में से कुल 95.5 कि.मी लंबाई की 24 मीटर सडके लाईसेंस कॉलोनी के अंतर्गत आती है।

.....

@ Reply given by the Agriculture and Farmar's Welfare Minister

उपरोक्त 95.5 कि.मी लंबाई में से औसतन कुल 28.7 किलोमीटर लम्बाई की सडकों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि शेष 68.8 मीटर लाइसेंस कॉलोनी में आने वाली 24 मीटर आंतरित सडकें अनिर्मित हैं। इनके निर्माण की निश्चित अवधि बता पाना संभव नहीं है क्योंकि कोलोनाईजरों द्वारा विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में आने वाली 24 मीटर सडकों के निर्माण के लिए सभी कोलोनाईजर लाईसेंस के नियम व शर्तों के अनुसार तथा कॉलोनी के कम्पलिशन सर्टीफीकेट प्राप्त करने से पहले इनके निर्माण हेतु बाध्य है। परंतु इन लाईसंसेड कॉलोनियों के बाहर के क्षेत्रों में प्रस्तावित 24 मीटर सडकों का निर्माण संबधित सरकारी विभाग अथवा नगर निगमों द्वारा भुमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अनुसार भुमि अर्जित करके ही किया जा सकता है। अतः इन क्षेत्रों में अनिर्मित 24 मीटर सडकों के निर्माण की निश्चित समयावधी बता पाना कठिन होगा।

सैक्टर 58 से 115, गुरूग्राम में 24 मीटर सडकों के निर्माण का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	सैक्टर संख्या	कुल 24 मीटर सडकों की लंबाई (कि.मी.)	लाइसेंस कॉलोनी में पडने वाली कुल 24 मीटर सडको की लंबाई (कि.मी.)	लाइसेंस कॉलोनी में पडने वाली कुल 24 मीटर निर्मित सडको की लंबाई (कि.मी.)	लाइसेंस कॉलोनी में पडने वाली कुल 24 मीटर अनिर्मित सडको की लंबाई (कि.मी.)
1	58 से 67ए	52.1	24.3	8.3	16.0
2	68 से 80	82.7	24.8	7.6	17.2
3	81 से 95 बी	86.4	24.9	8.1	16.8
4	99 से 115	78.3	21.5	4.7	16.8
	कुल	**299.50**	**95.5**	**28.7**	**66.8**

श्री राकेश दोलताबादः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़कर सुनाया है, उस उत्तर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी यह उत्तर तैयार किया है वह इतने महत्वपूर्ण विषय पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के कुल 90 विधायकों में से 15 विधायक गुरूग्राम में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है उसके संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर 95.5 कि.मी. लंबाई की सड़कों में से औसतन कुल 28.7 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण ही किया गया है और शेष 66.8 कि.मी. लंबाई की

सड़कों के निर्माण बाबत अर्थात 70 परसेंट इलाके के लिए माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखकर ही दे दिया है कि therefore, the definite time for construction of above mentioned incomplete 24 meters wide roads can not be provided. इस उत्तर को किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। हमारे यहां पर इंफ्रॉस्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जी.एम.डी.ए., हुडा तथा म्युनिसिपल कारपोरेशन स्टेकहोल्डर्ज की भूमिका निभाते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां 24 मीटर चौड़ी सडकों के निर्माण को इ.डी.सी. का हिस्सा बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिल्डर्ज ने लोगों की नाक में दम कर रखा था लेकिन 5 फरवरी, 2020 को अर्बन एरिया एक्ट के सैक्शन 19 को एम्पॉवर करते हुए प्रावधान किया गया कि जो बिल्डर्ज होम बायर्ज को समय पर बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं करेंगे, उन बिल्डर्ज के प्रोजैक्ट्स को या तो दूसरे बिल्डर्ज को दे दिया जायेगा या फिर सरकार उन प्रोजैक्ट को हैंड ओवर कर लेगी, का आज बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है और इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। अर्बन एरिया एक्ट के सैक्शन–19 के एम्पावर होने के बाद 16 केसिज सामने आये जिसमें से 2 केसिज डिसाइड हो चुके हैं और तीसरा केस चूंकि सी.एम. ग्रीवेंसिज सैल में आ गया था इसलिए वह भी सोल्व होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि जो बिल्डर्ज समय पर प्रोजैक्ट्स को हैंड ओवर नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कंसंर्ड डी.सीज. को पॉवर्ज दी जाये। स्थानीय उपायुक्त महोदय को बिल्डर्ज के पास जाकर कॉलोनी से संबंधित इशूज को हैंडल करना चाहिए तथा उनकी जो डैडलाइन है उनको देखना चाहिए। अगर एक कोलोनाईजर द्वारा निश्चित अवधि के दौरान प्रोजैक्ट पूरा नहीं करता है तो दूसरे कोलोनाईजर को प्रोजैक्ट टेक ओवर करने की अनुमति होनी चाहिए नहीं तो उस प्रोजैक्ट को गवर्नमैंट को टेक ओवर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी छोटा सा मकान बनाने में अपनी पूरी जिन्दगी की कमाई लगा देता है। उन कॉलोनियों में जाने के लिए 24 मीटर सड़क का जो रास्ता होता है, जिसमें न तो बिजली की तार जा सकती है, न ही पानी और सीवरेज के पाइप जा सकते हैं और न ही कोई अपनी गाड़ी वगैरह ले जा सकता है। फिर हमें गुरूग्राम जैसे बढ़िया शहर में रहने का क्या फायदा हुआ, जब हमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यह हमारे लिये बहुत बड़ा इशू है, जिसका सरकार के पास कोई

सॉल्यूशन नहीं है। पूरे हरियाणा को अकेला गुरूग्राम 50 प्रतिशत के करीब रेवेन्यू देता है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्य भाई की समस्या जायज है लेकिन इनको एक जानकारी यह नहीं है कि 18–24 मीटर आंतरिक सड़कें ई.डी.सी. का हिस्सा नहीं होती है। जो सड़कें ई.डी.सी. का हिस्सा होती हैं वे सब बन चुकी हैं। छोटी सडकें कौलोनाईजर ही बनाते हैं। बाकी की सड़कें भूमि अधिग्रहण करके जी.एम.डी.ए. या फिर टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग जिस क्षेत्र के अधीन आती है, सड़क बनाने का दायित्व उनका होता है।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, यह बात ठीक है कि सड़क बनाने का दायित्व संबंधित विभाग का होता है। यदि संबंधित विभाग सड़क नहीं बनाता है तो सड़क बनाने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, हम सड़क बनाने के लिए जल्दी ही कोई नीति बनाकर तरीका निकालेंगे।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए गंभीर नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वयं मंत्री जी कह रहे हैं कि यह ई.डी.सी. का हिस्सा नहीं है। फिर ये सड़कें कौन सा विभाग बनायेगा? कोई भी विभाग सड़क निर्माण के बारे में कोई भी निश्चित डैडलाइन नहीं दे पायेगा। उन कॉलोनियों में हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और अपनी गाड़ियों को बाहर ही पार्क करके आते हैं। उन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवरेज आदि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, कॉलोनी को लाईसैंस देते समय जो ई.डी.सी. चार्ज किया जाता है वह मास्टर सीवरेज प्लान, मास्टर रेन वॉटर आदि के लिये होता है। अंदर की सड़कें कोलोनाईजर को बनानी पड़ती है। पिछले दिनों कुछ कोलोनाईजरों ने अंदर की सड़कें बना भी दी हैं लेकिन बहुत सारे कोलोनाईजर डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं। जिन्होंने सड़कें नहीं बनाई हैं, हम उन कोलोनाईजर के रिस्क एण्ड कॉस्ट पर जी.एम.डी.ए. या जिसकी जो अथॉरिटी है वे 24 मीटर की सड़कें बनायेंगे। स्पीकर सर, बाहर की सड़कों के निर्माण के लिए भी जल्दी ही कोई नीति लेकर आयेंगे।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, जिन कॉलोनियों को कम्पलिशन सर्टिफिकेट मिल चुके हैं और उनमें सड़कें नहीं बनी है, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, यदि किसी कॉलोनी को कम्पलिशन सर्टिफिकेट मिल गया हो और बिल्डर ने सड़कें नहीं बनाई तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, हम उसकी जांच करवायेंगे।

श्री अध्यक्षः राकेश जी, आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो जांच करवाई जायेगी।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, यदि किसी भी कोलोनाईजर ने कम्पलिशन सर्टिफिकेट दे दिया और सड़कें नहीं बनाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री सत्य प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने नक्शे बनाये लेकिन उसमें उन्होंने अंदर जाने के लिए कहीं से भी रास्ते नहीं छोड़े । उन्होंने न तो गांव के बीच से रास्ता छोड़ा और न ही उन्होंने गांव की साइड से रास्ता छोड़ा था । वहां पर 24 मीटर का रास्ता नहीं है। विभाग द्वारा उनको आने–जाने का कोई तो ऑप्शन देना चाहिए। यह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की जिम्मेवारी है । अप्रूव्ड कॉलोनी में जो व्यक्ति रह रहा है उसको आने–जाने का रास्ता तो मिलना ही चाहिए । उन कॉलोनीज के लिए लोगों ने पेमेंट की है, फी सब्मिट की है, कॉलोनीज अप्रूव्ड हैं और इसके लिए सरकार द्वारा लाइसैंस और ओ.सी. (ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट) जारी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस 24 मीटर रास्ते वाले विषय को जितनी जल्दी हो सके हल करवायें अदरवाइज लोग वहां से पलायन करेंगे और कोलोनियां खाली हो जाएगी ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की नीति है कि यदि किसी लाइसैंसी की जमीन को 4 करम का रास्ता नहीं लगता है तो उस लाइसैंसी को लाइसैंस नहीं दिया जाता है । ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कॉलोनी में आने–जाने का रास्ता नहीं है । लाइसैंसी को 24 मीटर रोड बाद में

बनानी होती है । कॉलोनी में 4 करम के रास्ते की समस्या हो सकती है लेकिन जिस कॉलोनी में 4 करम का रास्ता एग्जिस्ट करता है केवल उसी लाइसैंसी को लाइसैंस दिया जाता है ।

श्री सत्य प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में जो सरकार थी उसने जब लाइसैंस बांटे थे तो उस समय किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए आज के दिन यह समस्या पैदा हुई है । (शोर एवं व्यवधान) वर्ष 2012 के बने हुए नक्शों को चाहे कोई भी निकलवाकर देख ले उसमें 24 मीटर का कहीं पर भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : धर्म सिंह जी, इस प्रश्न पर 4 सप्लीमैंट्रीज पूछी जा चुकी हैं । इस पर इससे ज्यादा सप्लीमैंट्रीज नहीं पूछी जा सकती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय बगैर सड़क बनाए ही दुनिया भर के लाइसैंसिज दे दिए गए । सड़क बनाए बगैर ही पैरा डायवर्ट कर दिया गया । अब हमारी सरकार को इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय के खोदे हुए गड्ढे भरने पड़ रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : श्री धर्म सिंह छोक्कर जो भी कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड न किया जाए । (शोर एवं व्यवधान) धर्म सिंह जी, आपको जो भी कहना है वह आप हमें लिखकर दे देना ।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : धर्म सिंह जी, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये । आप हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

.....

Pollution of Underground Water

***891. Smt. Nirmal Rani :**

(a) Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the underground water in District Sonipat, Panipat and Karnal has been polluted due to the industrial waste water released through borewells by several industrial units;

(b) If so, the steps taken by the Government to check the above said problem together with the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान जी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) सतही जल की गुणवत्ता भारत सरकार का निगरानी कार्यक्रम (एन0डब्लू0एम0पी0) के तहत सोनीपत के 19 स्थानों, पानीपत में 21 स्थानों और करनाल में 14 स्थानों पर निगरानी कर रहा है, जिसमें नदियों/नालों/जल निकायों और भूजल शामिल है और इन सभी नमूनों के परिणाम निर्धारित सीमा के अनुरूप पाए गए है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.बी.) सोनीपत में 19 स्थानों तथा करनाल जिले में 14 स्थानों पर नदियों/ड्रेनों/जल निकायों तथा भूजल के जल सहित सतह जल की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है तथा इन सभी बिन्दुओं से एकत्रित नमूनों के परिणाम निर्धारित मानकों में हैं । इन नमूनों के अलावा राष्ट्रीय जल निगरानी प्रोग्राम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के अधीन भी नमूने एकत्रित किये गए हैं । इन जिलों के भूजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट भारतीय मानक ब्यूरों (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित पेयजल के मानकों को पूरा करने के रूप में पाई गई है । हमने 3 इकाइयों सोनीपत जिले के राई क्षेत्र में 2 इकाइयों और करनाल जिले के घरौंडा क्षेत्र में 1 इकाई का पता लगाया है । हमने उन तीनों इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको बंद कर दिया है । यमुना नदी में अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनट्रीटेड पानी छोड़ेगा तो उन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको बन्द कर दिया जाएगा । विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों में 3 जिलों में 2123 उद्योगों का निरीक्षण

@Reply given by the Education Minister

किया गया है जिनमें से 485 उद्योग पालन न करने वाले पाये गये थे तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है। विभाग ने 38 औद्योगिक इकाइयों के ऊपर जुर्माना किया गया है। लगभग 29.50 करोड़ रुपये की राशि डिफॉल्ट इकाइयों से प्राप्त की गयी है।

श्रीमती निर्मल रानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मैंने यह सवाल पिछले सैशन के दौरान भी पूछा था और आज फिर से उसी सवाल को पूछ रही हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इसको रोकने के लिए क्या स्टैप्स उठाए गये हैं ? जब इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया तो उसके लिए आसपास के गांवों के लोगों ने अपनी जमीनें दी थी।

श्री अध्यक्षः निर्मल जी, माननीय मंत्री जी ने डिटेल बतायी हैं कि प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कितने चालान किये गये हैं, कितना जुर्माना किया है और क्या कार्रवाई की गयी है ?

श्रीमती निर्मल रानी: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में आसपास के गांवों में पॉल्यूटिड पानी आ रहा है जिससे कैंसर होने के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। वहां पर आसपास के गांवों ललेड़ी, बड़ी और राजलूगढ़ी हैं। इस सभी गांवों में पानी पाल्यूटिड हो चुका है जिसकी वजह से वहां पर मौतें हो रही हैं। हम हैल्थ इज वैल्थ की बात करते हैं, परन्तु हैल्थ ही नहीं होगी तो उस वैल्थ का क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: निर्मल जी, आपकी चिन्ता यह है कि फैक्ट्रीज का गंदा पानी निकलने से पीने का पानी पॉल्यूटिड हो रहा है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मापने के तरीके के अनुसार चैक किया तो वह पानी ठीक पाया गया। अगर माननीय सदस्या की जानकारी में कहीं भी कोई बोरवैल करके जमीन में अनट्रीटेड पानी छोड़ता है तो उसके बारे में बता दें। मैं यह बात सभी माननीय सदस्यों के लिए कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी है तो उसके बारे में बता दें। मैं इस सदन में आश्वासन देता हूं कि अगर कोई इस प्रकार की बात सामने आती है तो उसकी जानकारी दे दें। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी उद्योगपति अनट्रीटेड पानी छोड़ रहा है तो उसकी जानकारी दे दें। हम संबंधित एरिया में अधिकारियों को मौके पर भेजकर चैक करवाएंगे। अगर कोई कमी पायी जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

.....

To Establish State University in District Nuh

***761. Shri Mamman Khan:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the districtwise details of State/Central Universities established in State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish State University in District Nuh; if so, the time by which it is likely to be established?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है ।

(ख) श्रीमान जी, जिला नूंह में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । उक्त विश्वविद्यालय के लिए भूमि की तलाश और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद इसकी व्यवहार्यता की जांच कर रहा है । व्यवहार्यता का पता चलने के बाद ही समय प्रदान करना संभव होगा ।

वक्तव्य

(क) वर्तमान में 21 राजकीय विश्वविद्यालय और 01 केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में स्थापित है। जिलावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक नं0	जिला	विश्वविद्यालय का नाम
1.	महेन्द्रगढ़	केन्द्रीय विश्वविद्यालय गांव जांट पाली जिला महेन्द्रगढ़
2.	भिवानी	चौ0 बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
3.	गुरूग्राम	गुरूग्राम विश्वविद्यालय, गुरूग्राम
4.	जीन्द	चौ0 रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द
5.	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
6.		श्रीकृष्णा आयूष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
7.	कैथल	महर्षि बाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय, मुन्दड़ी, कैथल
8.	रेवाड़ी	इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी
9.	रोहतक	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
10.		पं0 बी0डी0 शर्मा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतक
11.		पं0 लखमीचन्द विश्वविद्यालय, प्रर्दशन एवं दृश्य कला, रोहतक

12.	सिरसा	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा
13.	सोनीपत	भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुरकलां, (सोनीपत)
14.		डा0 बी0आर0 अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत
15.		दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत)।
16.	हिसार	गुरू जम्भेश्वर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)।
17.		चौ0 चरन सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
18.		लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हिसार
19.	फरीदाबाद	जे0 सी0 बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद
20.	पलवल	श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल
21.	करनाल	पं0 दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, करनाल।
22.		महाराना प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अंजन्थली, करनाल

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नूंह में यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में पूछा है। इससे पहले 1 फरवरी, 2019 को माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछे गये सवाल पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना करने पर विचार करेगी। इसी आश्वासन को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 14.12.2020 को यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बारे में स्वीकृति दे दी थी। दिनांक 31.12.2020 को उपायुक्त नूंह को यूनिवर्सिटी के लिए भूमि की उपलब्धता तथा फिजिब्लिटी रिपोर्ट भेजने के बारे में लिखा गया था, परन्तु अभी तक वह रिपोर्ट अपेक्षित है। दिनांक 9.2.2021 को उच्च हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद् के आदेश पर एक कमेटी बनायी गयी थी, जोकि फिजिब्लिटी रिपोर्ट देगी और वह रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने में कम से कम 4–5 साल का समय लगता है।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि दिल्ली से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर बसे मेवात जिले के बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की समस्या आजादी से 74 साल पहले भी ऐसी ही बनी हुई थी और आज भी ऐसी बनी हुई है। पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था। देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन मेवात बदहाली से आज

तक आजाद नहीं हुआ है। आज 74 साल बाद भी मेवात का युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विश्वविद्यालय बनने के इन्तजार में बैठा हुआ है। प्रान्त के बाकी जिलों में कई–कई विश्वविद्यालय खोले गये हैं, परन्तु मेवात जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जबकि मेवात भी हरियाणा प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अब्दुल कलाम जी ने सन् 1957 में मेवात–गुरूग्राम का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय से लेकर आज तक वहां पर एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है। मेवात में कम से कम 550 गांव लगते हैं और वहां की जनसंख्या तकरीबन 12 लाख है। यह पूरा मेव डोमिनेटिड एरिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी मेवात जिले को पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ माना गया था। न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट में भी लिखा है कि मेवात क्षेत्र न केवल भारत में ही सबसे वंचित समुदाय है बल्कि बिहार के दलितों की तुलना में भी अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेवात में कुल साक्षरता दर 56 फीसदी है जबकि हरियाणा उच्च शिक्षा का ग्रौस एनरोलमैंट रेशो 28.7 फीसदी है।

श्री अध्यक्ष : मामन जी, आप सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछे। यह क्वैश्चन ऑवर है। आप भाषण न करें। अपना स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

श्री मामन खान : स्पीकर सर, मैं स्पैसिफिक क्वैश्चन ही पूछने जा रहा हूं। सर, मेवात की जो साक्षरता दर (जी.ई.आर.) है वह केवल मात्र 7 फीसदी है। वहां पर जो 12वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 93 परसैंट बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मुझे शिक्षा मंत्री जी बतायें कि प्रदेश के कौन से जिले में 93 परसैंट बच्चे हायर एजूकेशन के बाद ड्रॉप आउट होते हैं?

श्री अध्यक्ष : मामन खान जी, मेरे बार–बार कहने के बाद भी आप अपना स्पैसिफिक क्वैश्चन नहीं बता पाये हैं। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि आप अपना क्वैश्चन तो बता दें।

श्री मामन खान : स्पीकर सर, मेरा क्वैश्चन तो यही है कि जो आजादी के 74 साल बाद तक मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं दी गई। मेरी यह मांग है कि मेवात में जल्दी से जल्दी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाये।

श्री कंवर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मामन खान जी ने जो प्रश्न पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया है कि मेवात में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सरकार के स्तर पर कार्यवाही की शुरूआत हो चुकी है। मामन खान जी ने यह भी कहा कि

पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र मेवात में ही यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 6 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर यूनिवर्सिटी नहीं है जिनमें चरखी दादरी, फतेहाबाद, नूंह, पंचकूला, पानीपत और मेरा अपना जिला यमुना नगर शामिल हैं। दूसरी बात मामन खान जी ने यह भी कही है कि सरकार मेवात में शिक्षा के ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार मेवात में शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। हमारी सरकार का यह पूरा प्रयास है कि मेवात जिले के सभी बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षित हों। मामन खान जी ने जो यह आरोप लगाया कि शिक्षा के मामले में मेवात की सबसे बुरी हालत है। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि इसके लिए तो हमारी सरकार से पूर्व की सरकारें ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार तो पूरी ईमानदारी के साथ मेवात के साथ ही साथ पूरे हरियाणा प्रदेश को शिक्षित करने के काम में लगे हुए हैं। मामन खान जी हमारी सरकार के इसी कार्यकाल में यह देखेंगे कि मेवात में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में मेवात में एक बड़ा परिवर्तन करके दिखायेगी क्योंकि हमारी सरकार के लिए मेवात बेहद महत्वपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मामन खानः स्पीकर सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि हॉयर स्टेट एजूकेशन काउंसिल मेवात में यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए जगह का निरीक्षण कर रही है। मेरा यह कहना है कि मेवात में यूनिवर्सिटी की स्थापना के हमारे पास काफी जमीन अवेलेबल है। झिमरावट में 26 एकड़ जमीन हमारे पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से अगोन में 300 एकड़ जमीन हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे ही नागल मुबारिकबार में 350 एकड़ जमीन हमारे पास उपलब्ध है। मैं इन सभी जगहों के सम्बंधित पंचायतों से रेज्योल्यूशंज भी लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : मामान खान जी, आप जमीन के जो भी कागज लेकर आये हैं उन्हें आप मंत्री जी को दे दें।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, मैंने मेवात में यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के सम्बन्ध में दोनों बातें कही हैं कि हम यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी जमीन भी देख रहे हैं जो फिजीबल भी हो। जमीन के साथ ही साथ उसकी फिजीबिलिटी भी चैक होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी खोलना कोई आसान या छोटा काम नहीं है। मेरा यही कहना है कि एक यूनिवर्सिटी के लिए अगर सरकार 400 से 500 करोड़ रूपये खर्च करने

जा रही है तो जिस स्थान पर यूनिवर्सिटी खोली जायेगी उसकी फिजीबिलिटी भी होनी चाहिए। हमने मेवात में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री मामन खान : स्पीकर सर, हमें अपने मेवात के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मामन खान जी, आपकी बात पूरी हो गई है। अब आप बैठ जायें।

.....

To Convert Municipal Council into Municipal Corporation

***818 Shri Chiranjeev Rao:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert Municipal Council, Rewari into Municipal Corporation; and

(b) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) :नहीं, श्रीमान जी।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि रेवाड़ी शहर सन् 1995 के अंदर नगर परिषद् बन गया था। इस प्रकार से रेवाड़ी को नगर परिषद् बने 26 साल का समय हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी की जनसंख्या डेढ़ लाख थी जोकि आज बढ़कर चार लाख हो गई है। इसके अंदर जितनी भी हमारी कॉलोनियां हैं और आसा पास की जो ढ़ाणियां हैं उनकी जनसंख्या को अभी रेवाड़ी में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार से गांवों के अंदर जो ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज बनी हैं उनकी जनसंख्या भी अभी रेवाड़ी के अंदर शामिल नहीं हुई है। अगर इन सभी की जनसंख्या भी रेवाड़ी में शामिल हो जाये तो उसके बाद रेवाड़ी की जनसंख्या 6 से 7 लाख के आसपास हो जायेगी। इसी प्रकार से रेवाड़ी के करीब दो किलोमीटर के डायामीटर के अंदर कालूवास, गोकलगढ़, ढ़ालियावास, पदियावास, कालाका, मांडिया, रामपुरा जैसे लगभग 10 गांव हैं अगर इन सभी गांवों को भी रेवाड़ी के साथ जोड़ दिया जाये तो रेवाड़ी नगर पालिका की जनसंख्या 7 से 8 लाख हो जायेगी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी पिछले दिनों मानेसर को नगर निगम बनाया है जहां पर न पहले कभी नगर पालिका थी और न ही नगर परिषद् थी। इसके बावजूद भी मानेसर को सीधा

नगर निगम बना दिया इसके विपरीत रेवाड़ी जहां पर सन् 1995 के अंदर नगर परिषद् थी उसके अभी तक सरकार ने नगर निगम नहीं बनाया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्थानीय निकाय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि रेवाड़ी नगर पालिका को जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अधिनियम के तहत अगर तीन लाख की पॉपुलेशन हो तभी नगर निगम बनाया जा सकता है। वर्ष 2011 के सैंसस के मुताबिक रेवाड़ी की जनसंख्या 1,43,021 है और जो वर्ष 2018 में नगर काउंसिल के चुनाव हुए उनके मुताबिक रेवाड़ी की जनसंख्या 1,86,601 है। सर, जब तक तीन लाख की पापूलेशन न हो हम नगर निगम नहीं बना सकते।

श्री चिरंजीव राव : स्पीकर सर, खुद अभी मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2011 की सैंसस के अनुसार रेवाड़ी की जनसंख्या 1,43,021 थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लगभग 10 साल के अंदर रेवाड़ी शहर की जनसंख्या में केवल मात्र 40 हजार का ही इजाफा हुआ होगा?

श्री अध्यक्ष : चिरंजीव जी, जो आंकड़े ऑन रिकार्ड हैं मंत्री जी ने आपको वही आंकड़े बताये हैं। वे गलत नहीं बोल रहे हैं।

श्री चिरंजीव राव : स्पीकर सर, मैंने इसमें एक और बात जोड़ी है कि रेवाड़ी के दो किलोमीटर के डॉयमीटर के अंदर 10 गांव हैं अगर उनकी जनसंख्या को भी रेवाड़ी शहर के अंदर शामिल कर लिया जाये तो रेवाड़ी की जनसंख्या लगभग 6 से 7 लाख हो जायेगी। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट है कि जिस प्रकार से मानेसर को नगर निगम बनाया गया है उसी प्रकार से रेवाड़ी को भी जल्दी से जल्दी नगर निगम बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है चिरंजीव जी, मंत्री जी रेवाड़ी को भी नगर निगम बनाने के बारे में भी विचार करेंगे। अभी आप कृपा करके बैठ जायें।

.....

To Start Bus Service

***952. Shri Nayan Pal Rawat**: Will the Transport Minister be pleased to state–

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the Bus Service on following routes in Prithla Assembly Constituency:–

(i) from Palwal to Amarpur, Mohna, Chhainsa;

(ii) from Ateli to Ballabhgarh;

(iii) from Ballabhgarh to Samaypur, Karnera, Sikrona, Bhanakpur, Mahola and Sehrala;

(iv) from Prithla to Palwal;

(v) from Ballabhgarh to Fatehpur, Jawan and Mohna;

(vi) from Ballabhgarh to Panhera Khurd and Hirapur;

(vii) from Nariyala to Mohna; and

(b) the number of Bus Services presently available for the rural areas of Prithla Assembly Constituency?

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचन्द शर्मा) : (क) श्रीमान जी, उक्त मार्गों पर बल्लभगढ़ से पन्हेड़ा खुर्द और हीरापुर व नरियाला से मोहना मार्ग को छोड़कर बस सेवा पहले से ही संचालित है।

(ख) वर्तमान में 18 परिवहन समिति और 19 राज्य परिवहन की बसों (फरीदाबाद आगार की 17 बसें व पलवल आगार की 02 बसें) का पृथला निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन करवाया जा रहा है।

श्री नयन पाल रावत : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

.....

To Upgrade Tehsil as Sub-Division

***960. Shri Sita Ram:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Ateli Tehsil as Sub-Division; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :नहीं, श्रीमान् जी

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप–मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अटेली तहसील को उप–मण्डल का दर्जा दिया जाये। इसकी दो बार उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ से फिजिबिलिटी हो कर आ गई है। उप–मण्डल बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, डॉ. बनवारी लाल जी तथा श्री कंवरपाल जी से अनुरोध है कि अटेली तहसील को उप–मण्डल का दर्जा दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक तहसील को सब–डिवीजन बनाने की बात है तो इस बारे में कई प्रस्ताव पूरे प्रदेश से राजस्व विभाग के पास प्राप्त हुए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है। इससे संबंधित सभी विषयों के बारे में कमेटी विचार–विमर्श भी करेगी। क्योंकि कई मापदंड हैं कि गांवों की संख्या कितनी है, सब–तहसील कितनी हैं तथा पटवारखाने कितने हैं? कितने हैक्टेयर एरिया है, कितनी जनसंख्या है और जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर है, इन तमाम विषयों को देखा जाता है। कमेटी गम्भीरता से इसके ऊपर विचार करेगी और आने वाले दिनों में बैठक करेगी क्योंकि 1.4.2021 से फिर लैंड बाउंड्री सील होंगी। हमारा प्रयास होगा कि उससे पहले जो भी फाइनल निर्णय होगा क्योंकि सेंसस का काम 1.4.2021 से शुरू हो जायेगा इसलिए उससे पहले सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी फिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं। अटेली तहसील में 53 गांव शामिल हैं और 1,30,000 की आबादी है। इस तहसील में 25545 हेक्टेयर भूमि है और फिजिबिलिटी के हिसाब से सभी मापदंड पूरे करती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अटेली तहसील को उप–मण्डल का दर्जा दिया जाए।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर यह तहसील मापदंड पूरे करती होगी तो सरकार इस पर अवश्य ही गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

———

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Construct One Way Ramp

***1005. Shri Subhash Sudha** : Will Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct one way ramp from Sector 2-3 Mod on G.T. Road to O.P. Jindal Chowk, Kurukshetra, if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी।

.....

The Present Status of Construction of Road

***902. Dr. Kamal Gupta:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the present status of construction of road from Sector-1-4 to Mahabir Colony in Hisar togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान् जी, इस कार्य को करने के लिए रु. 476.83 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वन विभाग से अनापत्ति पत्र की आवश्यकता है। वन विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के बाद कार्य को शुरू किया जाएगा।

.....

To Open a Tegional Centre

***849. Shri Laxman Singh Yadav:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Regional Centre (with science faculty) of Indra Gandhi University, Mirpur in village Gurawara; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

.....

To Construct 200 Beds Hospital

***931. Shri Dura Ram :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the 200 beds Hospital is likely to be constructed in Fatehabad City?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 200 बिस्तरिये अस्पताल के निर्माण के लिए 14.75 एकड भूमि सैक्टर–9 फतेहाबाद मे उपलब्ध करवाई है। 200 बिस्तरिये अस्पताल की ड्राईग्स को अनुमोदित कर दिया गया है। सभी आवश्यक स्वीकृतिया मिलने के उपरान्त 200 बिस्तरिये अस्पताल के नये भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

.....

To carpet the Road

***796. Shri Mewa Singh**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to carpet the road from G.T. road to Barara via Babain in Ladwa Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be carpeted?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हां, श्रीमान जी। कुल 28.50 कि.मी. लंबाई में से 10.50 कि.मी. सड़क भाग पर बिटुमिनस कंक्रीट करना प्रस्तावित है।

.....

Number of Sanctioned Post of Doctors

***798. Shri Aseem Goel:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the number of posts of doctors sanctioned in Civil/General Hospital, Ambala City;

(b) the number of doctors presently posted in Civil/General Hospital Ambala City; and

(c) whether it is a fact that some of the doctors mentioned in at (b) above have been sent on deputation outside Ambala City; if so, the details thereof?

गृह मन्त्री (श्री अनिल विज) : (क) श्रीमान जी, जिला नागरिक हस्पताल, अम्बाला शहर में चिकित्सा अधिकारियों के 55 पद स्वीकृत हैं।

(ख) 46 चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हैं।

(ग) 7 चिकित्सा अधिकारी जिला नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन चिकित्सा अधिकारियों के ब्यौरे बारे एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

कथन

चिकित्सा अधिकारियों का ब्यौरा जो जिला नागरिक हस्पताल, अम्बाला शहर से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं

क्र0सं0	चिकित्सा अधिकारी का नाम	कार्यालय/संस्थान जहां प्रतिनियुक्त हैं
1	डॉ0 माला चन्द्रा	जिला नागरिक अस्पताल, पंचकुला
2	डॉ0 विशाल सिंगला	कार्यालय महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा
3	डॉ0 शशांक शेखर	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान
4	डॉ0 मोनिका	जिला नागरिक अस्पताल, पंचकुला
5	डॉ0 पूजा सिंह	नागरिक अस्पताल, अम्बाला छावनी
6	डॉ0 दीपिका गर्ग	जिला नागरिक अस्पताल, पंचकुला
7	डॉ0 राजीव कुमार	खाद्य एवं औषधि प्रशासन

Compensation to the Farmers

***855. Smt. Kiran Choudhary:** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that no compensation has been granted to the farmers in whose land electricity line has been laid down for the construction of 30KV power grid in Nimriwali village of Bhiwani by the Power-Grid;

(b) if so, the details thereof together with the time by which the compensation is likely to be given to effected farmers of villages Haluwas Majra, Devsar, Devsar Malawas, Ghirana Kalan, Ghirana Majra, Parhlad Garh, NawakiDhani, Rajgarh, Nimri Wali, Nand Gaon, DhanaNarsan, DhanaLadanpur, Goripur and Kitlana?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.–भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा प्रभावित किसानों को 41.86 लाख रूपये का फसली

मुआवजा अदा किया गया है। प्रभावित किसानों/भू–मालिको को फसली मुआवजा संबंधित पटवारी (राजस्व) तथा गांव के सरपंच द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित दावे की प्राप्ति के बाद पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा साधारणतः 15 से 20 दिनों के अंदर अदा किया जा रहा है।

.....

To Develop Sectors for Small Scale Industries

***1045. Shri Parmaod Kumar Vij**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to develop sectors for Small Scale Industries in State especially in Panipat; if so, the details thereof;

(b) If not, the steps taken by the Government to prevent setting up of unauthorized industrial sectors in State;

(c) The steps taken by the government to develop Small Scale Industry in the State;

(d) Whether there is also any proposal under consideration of the Government to set up said industry on unplanned land in industrial sectors in State; if so the details thereof; and

(e) If not, whether there is any proposal under consideration of Government to provide land to industrialist for the development of said industry in State ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(क) महोदय, इस संदर्भ में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । हालांकि, औद्योगिक संपदा पानीपत में 416 औद्योगिक भूखंडों को चिन्हित किया गया है । इसमें से 450 वर्गमीटर के 126 भूखंड लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं ।

(ख) महोदय, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों/नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर आने वाले अनाधिकृत उद्योगों की स्थापना को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक तथा सुधारात्मक कार्रवाई निरंतर आधार पर की जाती है ।

(ग) महोदय, सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है । तदानुसार, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति–2020 के तहत विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त लघु उद्योग सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सुविधा, उन्हें बढ़ावा देने एवं उनके विकास हेतु सरकार द्वारा एक अलग सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) निदेशादय की स्थापना की गई है ।

(घ) महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड) महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Road

186. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the toll road from Ballabhgarh to Sohna is in bad condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to exempt the vehicles from toll tax till the said road will be made functional for transportation?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) और (ख) सड़क अच्छी स्थिति में है, कि. मी. 4.00 से कि.मी. 6.00 तक यानी घौंची नाले से सरूरपुर तक के एक भाग को छोड़कर, जहां मरम्मत की आवश्यकता है।

.....

Change in the alignment of Road

304. Dr. Krishan lal Middha: Will the Deputy Chief Minister be pleased be state-

(a) whether it is a fact that the road from village Sotha to Kheri Jalab is not constructed according to the rules;

(b) whether it is also a fact that the change has been made according to the demarcation in the alignment of road constructed from water works in village Sotha to Bhanbhori road; and

(c) if so, the action taken by the Government against the delinquent officers?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(क) नहीं, सर। खेडी जालब से सोथा तक सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(ख) सड़क की सिंचाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सड़क का निर्माण मार्ग रेखा के सीमांकन के अनुसार किया गया है।

(ग) इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

.....

Extent of Amount Utilized

297. Shri Jaiveer Singh

Shri Shishpal Singh Keharwala: Will the Chief Minister be pleased to state the extent of amount utilized out of the total allocated budget for Scheduled Castes/Scheduled Tribes to purchase materials, services and construction works during the year 2018-19, 2019-20 and 2020-21 togetherwith the provision made by the Government to give preference to the first generation entrepreneurs relating to Schedule Castes/ Tribes in above said purchases and construction works ?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : हरियाणा में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं हैं। अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी) बज़ट में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का कुल आंबटित बज़ट होता है जिसका सामूहिक उद्धेश्य अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का कल्याण है। अनुसूचित जाति उप योजना हेतु राशि की गणना करते समय नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रख कर राशि बाँटने की प्रतिशता तय करते हुए प्रत्येक स्कीम में राशि आबंटित की जाती है। तदानुसार, विभिन्न विभागों की अनुसूचित जाति उप योजना स्कीमों के अन्तर्गत राशि का कुल आबंटित बजट वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 में निम्न प्रकार से है।

वर्ष	एस.सी.एस.पी बज़ट का आबंटन (रूपये करोड़)
2018-19	7367.29
2019-20	7610.18
2020-21	9165.73

एस.सी.एस.पी की कुल स्कीमों में से कुछ स्कीमों जिनमें सामान की खरीदारी, सेवाओं तथा निर्माण कार्य किये जाते हैं, उनको चिन्हित किया गया है। इन स्कीमों में कुल आबंटित बज़ट तथा उपयोग की गई राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

वर्ष	सामान की खरीद, सेवाओं तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एस.सी.एस.पी. स्कीमें	
	आबंटित बज़ट (रूपये करोड़)	उपयोग की गई राशि (रूपये करोड़)
2018-19	2287.71	1861.38
2019-20	1847.96	1354.58
2020-21	2193.01	1185.85 (03.03.2021 तक)

एस.सी.एस.पी. के अतंर्गत आबंटित बजट में से सामान खरीदने, सेवाओं तथा निर्माण कार्यों से संबंधित आँकड़े प्रत्येक विभाग से माँगे जा रहे हैं तथा अलग से उपलब्ध करवा दिये जाएंगे। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को उपरोक्त खरीदारी तथा निर्माण कार्यो में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। "Entrepreneurs Development Programme for Scheduled Castes Beneficiaries" स्कीम के अन्तर्गत राशि के आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	स्कीम का नाम	आबंटित बज़ट (रूपये करोड़)	व्यय (रूपये करोड़)
2018-19	Entrepreneurs Development Programme for Scheduled Castes Beneficiaries	0.60	0.42
2019-20		0.44	0.39
2020-21		0.44	0.05 (03.03.2021 तक)

To Construct the Field Passages

211. **Shri Jagbir Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct following field passages falling under the Gohana Assembly Constituency-

(i) from phirni to field of Hari Singh S/o Ramdhari to field of Rattan S/o Kundan in village Luhari Tibba;

(ii) from field of Dinesh S/o Suraj Ram to field of Ramehar S/o Ratan Singh in Village Barauta;

(iii) from Mehmoodpur road to Hatcherywala road in village Gangesar;

(iv) from field of Jaikishan S/o Nihalu to field of Mahender S/o Kapoor Singh in village Khandrai; and

(v) from PWD (B&R) road to field of Suresh S/o Hawa Singh in Village Bhatgoan?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): नहीं, श्री मान जी, जिला प्रशासन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

.....

To Open a Para Medical College

197. Shri Subhash Gangoli: Will the Medical Education Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Para Medical College in Safidon City; if so, the time by which it is likely to be opened.

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नही, श्रीमान जी।

.....

Interest on Agricultural Loan of Farmers

361. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the interest on the Agricultural Loan of farmers amounting up to Rs. 3 Lakh taken from the Nationalised Banks will be paid by the Government for which an announcement was made by the Finance Minister in the last Budget Session 2020-21;

(b) if so, the number of the farmers have been provided the benefits of the said scheme so far togetherwith the details of total payment made by the Government to the Nationalised Banks under this head; and

(c) the number of farmers who have taken the agriculture loan of Rs. 3 lakh from Nationalised Banks in the year 2020-21 in State?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमानजी, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए 3 लाख रूपये की राशि तक के किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Budget Released to Mewat Development Board

199. Shri Mamman Khan: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the details of budget released by the Government for development works in various fields under Mewat Development Board from financial year 2014-15 to 2020-21?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैंट

मेवात विकास बोर्ड के अन्तर्गत हरियाणा सरकार द्वारा मेवात विकास अभिकरण, नूहॅ को वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2020–21 (31.01.2021 तक) मु0 17925.00 लाख रू0 विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यो हेतु जारी किये गये हैः–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	वित्तीय वर्ष	मेवात क्षेत्र के समेकित विकास हेतु योजना	मेवात क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के हेतु योजना	कुल
1	2014-15	2160.00	240.00	2400.00
2	2015-16	2615.00	285.00	2900.00
3	2016-17	2840.00	310.00	3150.00
4	2017-18	3110.00	340.00	3450.00
5	2018-19	1620.00	180.00	1800.00
6	2019-20	1890.00	135.00	2025.00
7	2020-21 (तक 31.01.2021)	2000.00	200.00	2200.00
	कुल	**16235.00**	**1690.00**	**17925.00**

- एमडीए के पास दिनांक 01.04.2014 को 476.22 लाख रू0 की राशि अनुपयोग शेष थी।
- एमडीए के पास वर्ष 2014–15 से 2020–21 के दौरान कुल 18401.22 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध थी।
- एमडीए द्वारा 18401.22 लाख रू0 मे से 18354.85 लाख रू0 की राशि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए जारी की जा चुकी है।

विभिन्न योजनाओं/मदों के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियों के लिए वर्ष 2014–15 से 2020–21 (31.12.2020 तक) जारी की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	मद का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	शिक्षा	1253.30	1648.06	2024.70	2199.90	2381.86	2317.40	1865.00	13690.22
2	गैर कृषि उद्यम	24.98	35.79	65.41	125.98	104.28	76.80	25.22	458.46
3	परियोजना प्रबन्धन	85.00	97.00	115.00	130.00	100.00	170.00	178.50	875.50
4	सामुदायिक कार्य	589.16	165.70	955.34	157.81	174.80	17.32	4.90	2065.03
5	कृषि	30.50	3.32	82.33	0.00	4.60	100.30	70.00	291.05
6	स्वास्थ्य	4.39	46.46	51.01	66.83	52.41	69.82	132.26	423.18
7	सामुदायिक विकास	46.38	48.67	59.21	61.44	57.22	52.33	43.98	369.23
8	खेल	0.17	0.83	6.82	0.84	4.49	13.16	8.55	34.86
9	पशुपालन	25.00	30.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	135.20
10	सांस्कृतिक विकास	0.45	2.07	0.99	7.06	0.85	0.70	0.00	12.12
	कुल	**2059.33**	**2077.90**	**3441.01**	**2749.86**	**2880.51**	**2817.83**	**2328.41**	**18354.85**

- एमडीए के पास दिनांक 31.01.2021 को 46.37 लाख रू0 शेष है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए 1944.18 लाख रूपये (सामान्य वर्ग 1838.18 लाख रू0 तथा अनुसूचित वर्ग 106.00 लाख रू0) की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.02.2021 को जारी की गई है। इस राशि की निकासी के क्रम में प्रक्रिया चल रही है।

.....

Details of Group Housing Projects

203. Shri Rakesh Daultabad: will the Chief Minister be pleased to state to the details of group housing residential colony licenses (including its expiry date) and occupation certificates issued by the Town and Country Planning Department to Ms Vatika Ltd. or Vatika Land Base Pvt. Ltd. from the year 2005 to 2020 in various sectors of Gurugram District together with the current status of each project alongwith the action taken or likely to be taken by the Government against the developer for delay in delivery of its projects?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्री मान, यह ब्यान विधानसभा पटल पर रखा है।

ब्यान

हां, जिला गुरूग्राम में वर्ष 2005 से 2020 के बीच ग्राम एंव नगर आयोजना विभाग द्वारा मैसर्स वाटिका लिमिटिड और वाटिका लैंड बैस प्राइवेट लिमिटिड को ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी हेतु दस लाइसेंस जारी किए है। उपरोक्त लाइसेंस में दिए गए इन लाइसेंसों की समाप्ति तिथि और कब्जा प्रमाण पत्र (ओक्युपेशन सर्टिफिकेट) की स्थिति निम्नानुसार है।

कम सं0	कम्पनी का नाम	लाइसेंस नं0	लाइसेंस दिनांक	क्षेत्र (एकड में)	सैक्टर नं0	लाइसेंस समाप्ति की तारीख	ओसी/सीसी जारी करने की तारीख
1	वाटिका लिमिटिड	22 OF 2011	24-03-2011	11.22	82A	23.03.2017	जारी नही
2		41 OF 2013	06-06-2013	14.3	89A	05.06.2017	जारी नही
3.		42 OF 2013	06-06-2013	10.1	88A	05.06.2017	जारी नही
4.		46 OF 2013	08-06-2013	14.03	88A	07.06.2019	जारी नही
5.		66 OF 2013	20-07-2013	10.04	88B	19.07.2017	जारी नही
6.	वाटिका लिमिटिड	87 OF 2013	11-10-2013	11.13	89A	10.10.2017	जारी नही
7.		90 OF 2013	26-10-2013	12.21	88B	25.10.2017	जारी नही
8.		91 OF 2013	26-10-2013	18.8	88B	25.10.2017	जारी नही
9.	वाटिका लैंड बैस प्राइवेट लिमिटिड	84 OF 2008	11-04-2008	11.8	83	10.04.2020	24.10.2016
10.		83 OF 2009	07-12-2009	7.35	83	06.12.2019	जारी नही

उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त परियोजनाएं विकासशील चरण में हैं, केवल लाइसेंस नंबर 42 of 2013 दिनांक 06.06.2013 और 90 of 2013 दिनांक 26.10. 2013 सैक्टर नंबर 88बी, गुरुग्राम इन लाइसेंस में बिल्डिग प्लान को मंजूरी नही ंली गई है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास व विनियमन, 1976 का नियम 13, जब लाइसेंसी अपने प्रोजक्ट को लाइसेंस के खत्म, होने से पहले पूरा न कर पाने की स्थिति में, उस परियोजना को पूरा करने के लिए लाइसेंसी को अपने लाइसेंस का

नवीनीकरण का अवसर प्रदान करता है। यदि परियोजना को निष्पादित करने वाले उपनिवेशक के प्रदर्शन को संतोषजनक नही पाया जाता है, तो उन लाइसेंसो का नवीनीकरण नहीं किया जाता और विभाग ऐसे लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया करता है।

इसके अतिरिक्त, फलैट/प्लॉट के पोजेशन मे देरी बिल्डर–क्रेता के बीच द्वी–पक्षीय समझोते के अधीन है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वर्ष 2003 के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ओदशों के अनुसार डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और अन्य बनाम निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा और अन्य के शीर्षक से सिविल अपील नं0 550 में बिल्डर क्रेता समझौता में विभाग हस्तक्षेप नही कर सकता। हालाँकि, यदि डेवलपर बिल्डर क्रेता अनुसार परियोजना को विकसित नही करता है, तो आवंटी के पास उचित कानूनी मंच जैसे सिविल/उपभोक्ता न्यायालयों की तरह या हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) के पास जाने का विकल्प है। हरियाणा सरकार ने क्रेताओ कि शिकायतों के तेजी से निष्पादन हेतु राज्य में दो अथोरिटी बनाई है जिसमे से एक गुरुग्राम में भी है।

.....

To Construct Four Lane Road

225. Shri Mewa Singh: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to Construct four lane road from Ladwa to Shahbad; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हां, श्रीमान जी। प्रस्ताव विचाराधीन है। व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रक्रियाधीन है। इसलिए, समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

.....

Status of CM Announcement No. 25284

206. Shri Varun Chaudhary : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the Assembly Constituency wise status of Chief Minister announcement No. 25284 (Rs. five crore grants for develoomen works in every constituency)?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

d+d21

~~A statement as referred to in reply to the Un-starred AQ No.206~~

~~CM ANNOUNCEMENT 25284~~

Statement of **ASSEMBLY CONSTITUENCIES-WISE FUNDS SANCTIONED**

Constituency	S. NO.	Dev. & Panchayats	S. NO.	Urban Local Bodies	S. NO.	National Health Mission	TotaL Number Consty.	TOTAL SANCTIONED FUNDS
ADAMPUR	1	69,39,000						69,39,000
AMBALA CANTT.			1	4,96,56,000				4,96,56,000
AMBALA CITY	2	4,19,61,000						4,19,61,000
ASSANDH	3	1,20,59,000						1,20,59,000
ATELI	4	4,87,67,000						4,87,67,000
BADHKHAL			2	97,57,000				97,57,000
BADSHAHPUR	5	4,57,29,000						4,57,29,000
BALLABHGARH			3	4,36,33,000				4,36,33,000
BARWALA	6	5,04,18,000						5,04,18,000
BAWAL	7	5,07,77,000						5,07,77,000
BAWANI KHERA	8	5,03,14,000						5,03,14,000
BHIWANI	9	2,92,13,000						2,92,13,000
DABWALI	10	2,21,50,500						2,21,50,500
FATEHABAD	11	4,91,58,500						4,91,58,500
FEROZEPUR JHIRKA	12	4,64,95,000						4,64,95,000
GANNAUR	13	4,31,87,500						4,31,87,500
GHAROUNDA	14	3,81,42,000						3,81,42,000
GUHLA	15	4,28,72,000						4,28,72,000
GURUGRAM					1	5,00,00,000		5,00,00,000
HANSI	16	4,16,48,000						4,16,48,000
HATHIN	17	5,03,70,500						5,03,70,500
HISAR			4	5,00,00,000				5,00,00,000
HODAL	18	4,23,39,000						4,23,39,000
INDRI	19	4,29,00,000						4,29,00,000
JAGADHRI	20	2,46,71,000						2,46,71,000
JIND	21	94,53,000	5	3,80,56,000				4,75,09,000
JULANA	22	3,91,00,000						3,91,00,000
KAITHAL	23	4,44,56,000						4,44,56,000
KALANWALI	24	84,29,350						84,29,350
KALAYAT	25	4,85,78,000						4,85,78,000
KARNAL			6	4,00,00,000				4,00,00,000
KOSLI	26	4,34,01,000						4,34,01,000
LADWA	27	1,45,81,000						1,45,81,000
LOHARU	28	5,00,79,000						5,00,79,000
MAHENDRAGARH	29	24,03,000						24,03,000
MEHAM	30	4,85,86,000						4,85,86,000
MULLANA	31	75,76,000						75,76,000
NALWA	32	4,52,13,500						4,52,13,500
NANGAL CHAUDHARY	33	4,84,38,000						4,84,38,000
NARAINGARH	34	1,07,00,000						1,07,00,000
NARNAUL	35	4,39,47,000						4,39,47,000
NARWANA	36	3,38,19,000						3,38,19,000
NILOKHERI	37	3,67,86,000						3,67,86,000
NUH	38	38,50,000						38,50,000
PALWAL	39	4,64,02,000						4,64,02,000

Constituency	S. NO.	Dev. & Panchayats	S. NO.	Urban Local Bodies	S. NO.	National Health Mission	TotaL Number Consty.	TOTAL SANCTIONED FUNDS
PANIPAT CITY			7	3,31,00,000				3,31,00,000
PANIPAT RURAL	40	4,08,97,000						4,08,97,000
PATAUDI	41	1,49,16,000						1,49,16,000
PEHOWA	42	3,04,88,000						3,04,88,000
PRITHLA	43	3,62,93,000						3,62,93,000
PUNDRI	44	5,37,19,000						5,37,19,000
RAI	45	98,64,000						98,64,000
RANIA	46	1,95,38,700						1,95,38,700
RATIA	47	3,42,72,000						3,42,72,000
SAFIDON	48	4,09,95,100						4,09,95,100
SAMALKHA	49	3,10,01,000						3,10,01,000
SHAHBAD	50	4,15,29,000						4,15,29,000
SIRSA	51	1,32,44,000						1,32,44,000
SOHNA	52	3,58,62,000						3,58,62,000
SONIPAT			8	4,33,62,000				4,33,62,000
THANESAR			9	5,00,00,000				5,00,00,000
TIGAON	53	4,23,80,000						4,23,80,000
TOHANA	54	3,37,29,000						3,37,29,000
TOSHAM	55	3,35,65,000						3,35,65,000
UCHANA KALAN	56	3,41,71,000						3,41,71,000
UKLANA	57	4,94,05,000						4,94,05,000
YAMUNANAGAR	58	2,09,62,000						2,09,62,000
TOTAL	**58**	**1,98,27,39,650**	**9**	**35,75,64,000**	**1**	**5,00,00,000**	**68**	**2,39,03,03,650**

Note: **The actual number of Constituencies, for which funds have been sanctioned, is 67 as 1 Constituency i.e. Jind appears in the list of both the departments — Dev. & Panchayats Department & Urban Local Bodies Department.**

To Supply Electricity to Dhanies

301. Shri Shishpal Singh : Will the Power Minister be pleased to state the steps taken by the Government to supply electricity to Dhanies situated outside the villages in the State?

रणजीत सिंह, बिजली मंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी, राज्य में गांवों के बाहर स्थित ढाणियों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक नीति पहले से ही मौजूद है।

सेल्ज परिपत्र संख्या डी–13/2017 के द्वारा जारी किए गए निर्णय/नीति के अनुसार, जहां कहीं भी सम्भव है, वहां ढाणियों को पी.ए.टी. सुविधा प्रदान करके ए.पी. फीडरों पर कनैक्शन जारी किए जाएंगे। जहां यह सम्भव नहीं है, तो वहां इसे नजदीकी आर.डी.एस. फीडर से बिजली आपूर्ति दी जानी है। 150 मीटर तक सर्विस कनैक्शन शुल्क दो किलोवाट तक 200 रूपये प्रति किलोवाट है। यदि लाइन की लंबाई 150 मीटर से अधिक है, तो 150 मीटर से ज्यादा लंबाई के लिए प्रति मीटर 175 रूपये शुल्क लिया जाएगा। दो किलोवाट से ज्यादा पर, 500/– रूपये प्रति किलोवाट सर्विस कनैक्शन शुल्क और लाइन का खर्चा लिया जाएगा।

गांवों के लाल डोरा के एक किलोमीटर के भीतर आने वाले कनैक्शनों को डिस्कॉम द्वारा नजदीकी ए.पी./आर.डी.एस. फीडर से जारी किया जाएगा।

2018 के दौरान किए सर्वेक्षण के अनुसार 5074 घरों वाली (एक किलोमीटर के भीतर 1948+एक किलोमीटर से बाहर 3126) कुल 3872 ढाणियां (एक किलोमीटर के भीतर 1397+एक किलोमीटर से बाहर 2475) ढाणियां अविद्युतीकृत पाई गई थी। डिस्कॉम द्वारा 1948 आवेदकों में से 1037 आवेदकों को कनैक्शन जारी कर दिया गया है, जो इसप्रकार है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 = 655

वित्तीय वर्ष 2019–20 = 129

वित्तीय वर्ष 2020–21 = 253

To Set-up Judicial Court

235. Shri Ram Kumar Gautam : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up judicial court at Narnaund Town; if so, the time by which it is likely to be set up?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Inauguration by Ex-MLA

268. Shri Bishan Lal Saini: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any candidate who lost in State Assembly elections can also lay dawn or inaugurate the foundation stone engraving his name on it; if so the details thereof; and

(b) whether it is a fact that an Ex-MLA has inaugurated/lay down the foundation stone of community centre engraving his name on it in village Damla and Khurdi in Radaur Assembly constituency; if so, the

details thereof togetherwith the action taken by the Government in the matter?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी, उत्तर दो भागों में विभक्त है –

(क) इस संबंध में कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं है जो विधानसभा चुनाव में हारे हुये किसी उम्मीदवार को इस पर अपने नाम पर आधारशिला उत्कीर्णन करवाकर शिलान्यास या उद्घाटन करने से प्रतिबंधित करता हो।

(ख) गांव खुर्दी में सामुदायिक केन्द्र का उद्घाटन और गांव दामला में ग्राम ज्ञान केन्द्र का शिलान्यास श्री कर्ण देव कम्बोज पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता तथा श्री शशी दुरेजा, अध्यक्ष पंचायत समिति जगाधरी की उपस्थिति में श्री नायब सिंह सैनी, माननीय संसद सदस्य कुरूक्षेत्र द्वारा किया गया है।

.....

To Open a Government College

281. Shri Ishwar Singh: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the students of village Siwan and nearby rural area have to travel many kilometers for getting higher education in college; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open any Government College in Siwan togetherwith the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। (ख) 'क' के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

To Open a Government Girls School

286. Shri Deepak Mangla: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no Government Girls School in 12 Villages in Khadar area of Palwal Consituency; and

(b) if so, wheather there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls School in abovesaid area togetherwith the time by which the said school is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) श्रीमान जी, लड़के तथा लड़कियां सरकारी सह शैक्षिक स्कलों में इक्ट्ठे पढ़ रहे है। पलवल निर्वाचन क्षेत्र के खादर क्षेत्र के 12 गावों में स्थित राजकीय विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

मद नं0	गावों का नाम	रा0प्रा0पा0	रा0मा0वि0	रा0उ0वि0	रा0व0मा0वि0	विषेश कथन
1.	बागपुर	..	..	..	रा0व0मा0वि0 (1123)	कक्षा 1 से 12 तक संयुक्त विद्यालय
2.	भूड	रा0प्रा0पा0 (11559)	..	..	..	रा0प्रा0पा0 भूड (11559) गांव भुड और जेबाबाद खेड़ली का संयुक्त विद्यालय है। दोनो गांव के बीच की दूरी केवल लगभग 500 मीटर है।
3.	जेबाबाद खेड़ली	..	..	..	..	
4.	नंगलिया	रा0प्रा0पा0 (11531)	..	..	..	रा0प्रा0पा0 नंगलिया (11531) गांव नंगलिया और झुप्पा का संयुक्त
5.	झुप्पा	..	..	..	..	

						विद्यालय है। दोनो गांव के बीच की दूरी केवल लगभग 400 मीटर है।
6.	माला सिंह फार्म	रा0प्रा0पा0 (11560)	..	..	..	
7.	पहरूका	रा0प्रा0पा0 (11561)	..	..	..	
8.	षेखपुर	रा0प्रा0पा0 (11580)	..	..	..	
9.	राजूपुर	..	रा0मा0वि0 (1078)	..	..	कक्षा 1 से 8 तक संयुक्त विद्यालय
10.	दोस्तपुर	रा0प्रा0पा0	..	..	..	
11.	भोलडा	रा0प्रा0पा0 (11562)	..	..	..	
12.	सोलडा	..	..	..	रा0व0मा0वि0 (1166)	कक्षा 1 से 12 तक संयुक्त विद्यालय

(ख) नहीं, श्रीमान्।

.....

To Lay Down the New Sewerage Line

272. Shri Sanjay Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down New Sewerage Line in Sohna City; if so, the time by which the problem of water logging is likely to be solved?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी। सोहना शहर के सभी शेष अधीकृत क्षेत्र में पहले ही सीवरेज लाईन बिछाई जा रही है। सोहना शहर में जल भराव की कोई समस्या नहीं है।

.....

To Re-construct Bridges

350. Shri Sita Ram Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct survey for demarcation of dilapidated bridges constructed on the minors and distributaries in Ateli Assembly constituency; if so, the time by which the said dilapidated bridges are likely to be reconstructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हॉ श्रीमान जी, पुलों के सीमांकन के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा हो चुका है और अटेली क्षेत्र के पुलों के मरम्मत के अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत चैनलों के पुनर्वास कार्यों में प्रस्तावित किया गया (अटेली निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस तरह के 5 चैनलों को सम्मिलित किया गया है) और यदि किसी पुल की मामूली मरम्मत शेष रह जाएगी, जोकि आवश्यक होगी, तो वह जून, 2021 के अंत तक कर दी जाएगी।

.....

To Open a Medical College

334. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Medical Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Medical College in Dadri District; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

गृह मन्त्री (श्री अनिल विज) : नहीं, महोदय जी।

.....

To Declare Agni Suraksha Diwas

314. Shri Amit Sihag: Will the Urban Chief Minister be pleased to state Whether there is any proposal under consideration of the Government to declare 23rd December as Agni Suraksha Diwas in the memory of 442 lives lost in the fire tragedy of Dabwali in 1995 together with Whether

there is also any proposal under consideration of the Government to declare the Agnikand Site as State Memorial?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी। यद्यपि, इस स्मारक को राज्य स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव निरीक्षणाधीन है।

.....

To Decrease the Life Span of Permanent Water Courses

323. Shri Ram Niwas: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to decrease the life span of permanent watercourses from 20 years to 15 years as these get obsolete in 20 years?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान जी। स्थायी जलमार्गों के जीवन काल को 20 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, पुराने जल मार्गों के पुनर्वास/रीमॉडेलिंग का काम MICADA जल मार्ग नीति के अनुसार किया जा सकता है।

Details of Hospitals

187. Shri Neeraj Sharma: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) Wheather the QRG Hospital, Sector-16, Faridabad fulfills all rules and regulations as per Government norms, and

(b) Whether the compliance certificate and occupation certificate have been issued by the Government to the said Hospital togetherwith the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) और (ख) हां, श्रीमान जी।

.....

To Take over the Teaching Staff

305. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the teaching staff of all the Government Aided colleges of State;

(b) if so, time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized togetherwith the number of employees likely to be effected by the said takeover?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) प्रस्ताव में प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है जैसे की प्रबन्धन की सहमति, कर्मचारियों की सहमति, राजकीय महाविद्यालयों में कर्मचारियों की आवश्यकता, कानूनी प्रक्रिया, विभिन्न सेवा शर्ते आदि। अतः समय निर्धारित नही किया जा सकता। सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लगभग 1979 शिक्षण व 1148 गैर शिक्षण कर्मचारी कार्यरत है, जो उक्त अधिग्रहण से प्रभावित होंगे।

.....

To Construct the Field Passages

212. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct following field passages falling under the Gohana Assembly Constituency:-

(i) from field of Rishi S/o Mahender to field of Jai Bhagwan S/o Amar Singh Lambardar in Village Chitana;

(ii) from field of Jagbir S/o Dharam Dass to Mukhtyar S/o Sarup Singh in village Kilorad;

(iii) from road to the field of Surender Gulia S/o Balbir in Village Dubeta;

(iv) from field of Manohar S/o Jage Ram to field of Ashok Pandit S/o Tek Chand in Village Rollad-Latifpur;

(v) from Government High school to field of Ishwar S/o Ramkla in Village Mehlana; and

(vi) from field of Gulab S/o Manphool to field of Lilu Daroga in Bhatgoan?

उप मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं, श्री मान जी, जिला प्रशासन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

.....

Details Regarding Construction of Car Parking

366. Shri Bharat Bushan Batra: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the following details regarding Construction of car parking-cum-commercial complex at Urban Estate Rohtak and Old Police station & Bhiwani stand on PP mode at Rohtak for which allotment of work vide CM Announcement code 12631 & 12632 was made in 2016-

(a) the officers/authority who made the proposal alongwith complete notes of file from Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak up to ACS, Urban Local Bodies Department;

(b) The proceedings of the meeting of the Committee of Secretaries on infrastructure and noting vide which final approval of Hon'ble Chief Minister was given; and

(c) the criteria adopted by Commissioner, Municipal Corporation, Rohtak and Deputy Commissioner, Rohtak to assess the market value of land of the project i.e. fixing the commercial rate i.e. 70,000/- per sq meter for prime location andRs.25,000/- per sq meter for non prime location and Bhiwani stand and rate fixed at Urban Estate (HSVP) Rohtak ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : माननीय सदस्य कृपया हरियाणा विधानसभा की प्रक्रियाओं के नियमों के उप–खड़ 12 खड़ 46 का उल्लेख करें, जो निम्नानुसार हैः

"46. किसी प्रश्न के ग्राहय होने के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थातः–

> (12) उसमें ऐसी जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उन दस्तावेजों में, जिन तक जनता की साधारण पंहुच हो, या निर्देश की सामान्य कृतियों में पाई जाने वाली हो"

इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रश्न के माध्यम से मांगी गई सभी सूचनाओं का आम जनता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत मूल्यांकन किया जा सकता है, जो प्रशन पूछा गया है वह अस्वीकार्य है और तदानुसार उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

.....

To Construct Four Lane Road

226. Shri Mewa Singh: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Pipli G.T. road to Yamuna Nagar; if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हां, श्रीमान जी। प्रस्ताव विचाराधीन है। व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रक्रियाधीन है इसलिए इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

To Change Cadre of Sanskrit Teachers

236. Shri Ram Kumar Gautam : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to change the Cadre of Sanskrit Teachers from District to State on the pattern of TGTs in State. If so, the time by which the cadre of said teachers is likely to be changed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान।

.....

To Construct Community Centre

287. Shri Deepak Mangla: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no community centre for marriage in Sallagarh area of Palwal city; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a community centre in abovesaid area; if so, the time by which it is likely to be constructed?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Upgrade Hospital and to Increase Staff Strength

273. Shri Sanjay Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade and to increase staff strength in Civil Hospital of Sohna; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Repair of Roads

351. Shri Sita Ram Yadav: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads in Ateli Assembly Constituency;

(i) from Ateli Kanina road to Garhi Ruthal upto Khariwara;

(ii) from Ateli to Kanina upto Mahendragarh Chowk;

(iii) from Partal Bus Stand at the Ateli Kanina road to Manpura via Dhana;

(iv) from Rewari Mahendergarh road, Kanina to Karira;

(v) from Bhojawas Chowk to Bohka; and

(b) If so, the time by which the estimates of above said roads are likely to be sanctioned?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हां, सर।

(ख) इस समय कोई समय सीमा नही दी जा सकती।

.....

To Give the Status of Education Block

335. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to give the status of Education Department Block to JhojhuKalan, and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नही है।
(ख) अतः इस प्रश्न का औचित्य नही है।

Construction of Bye-Pass

324. Shri Ram Niwas : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Bye-pass in Narwana city has been approved by the Government in Budget 2020-21; if so, the time by which construction of said Bye-pass is likely to be started togetherwith the estimated cost thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान् जी, बजट 2020–21 में घोषणा की गई थी कि नरवाना शहर के बाई–पास को स्वीकृत के लिए माननीय केन्द्रिय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मुलाकात की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री के अर्द्धसरकारी पत्र दिनांक 20.12.2019 द्वारा जींदसे पंजाब सीमा तक सड़क की चारमार्गी परियोजना में नरवाना बाई–पास के निर्माण के लिए माननीय केन्द्रिय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध किया था। जवाब में माननीय केन्द्रिय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अर्द्धसरकारी पत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा सूचित किया कि नरवाना बाई–पास का निर्माण उपरोक्त परियोजना के दायरे में नहीं है और नरवाना शहर में भीड़–भाड़ का समाधान सर्विस रोड़ के निर्माण के बाद हो जाएगा।

.....

Action taken on QRG Hospital

188. Shri Neeraj Sharma : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) Wheather it is a fact that Rs.10,000/- have been charged from the corona infected patients by the Q.R.G Hospital, Sector-16, Faridabad at the time of admission; and

(b) if so, the action taken by the Government in the said matter?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) और (ख) हां, श्रीमान जी, क्यू.आर.जी. अस्पताल, सैक्टर–16, फरीदाबाद द्वारा कोरोना बीमारी से ग्रस्त रोगियों से सरकार के आदेश दिनांक 25.06.2020 के द्वारा निर्धारित शुल्क लिया गया है।

.....

To Construct Purchase Centre

306. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the purchase centre in village Manoharpur-Bohatwala of Jind Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) :

(क) मनोहरपुर गांव में क्रय केन्द्र के निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा गांव बोहतवाला में क्रय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) क्रय केन्द्र मनोहरपुर का निर्माण कार्य वितीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

.....

To construct the Field Pasaages

213. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct following field passages falling under the Gohana Assembly Constituency:-

(i) from field of Karam S/o Bhuppan to field of Kartar S/o Chandarbhan in Village Bhatana-Jafrabad;

(ii) from main road to forest in village Majri;

(iii) from Molar wale Talab to field of Madud in Village Karewari;

(iv) from field of Mansingh to field of Raghbir Pandit in village Salarpur Majra;

(v) from field of Satbir S/o Ramdiya to field of Jagpal Thekedar S/o Badluram in Village Rollad-Latifpur?

उप मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं, श्री मान जी, जिला प्रशासन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

.....

To Construct 50 Beds Hospital

227. Shri Mewa Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct 50 Beds Hospital in Ladwa Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Construct Fire Brigade Building

288. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the building of fire brigade of Palwal is constructed in the crowded area of the city and the building is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct fire brigade building outside the city togetherwith; if the time by which it is likely to be constructed?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नगर परिषद, पलवल द्वारा गांव अगवानपुर की खाली भूमि पर अग्निशमन भवन का निर्माण करने के लिए दिनांक 29.01.2021 को प्रस्ताव संख्या 11/194 पारित किया है, जोकि नगर परिषद, पलवल की सीमा में है। उक्त भूमि एन.एच–44 राजमार्ग पर स्थित है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का प्रस्ताव नगर परिषद के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

.....

To Set Up Bio Gas Plant

352. Shri Sita Ram Yadav: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up bio gas plants in Gaushalas situated at Kanina and Bhojawas under the gobar-dhan scheme in State on the pattern of Sabar Katha of Gujrat; if so, the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान् जी, सहकारिता विभाग हरियाणा से अनुरोध किया गया था कि वह हरियाणा के किसी भी स्थान पर बनास बायो–गैस

प्लांट बनासकांठा (गुजरात) की तर्ज पर एक बायोगैस प्लांट स्थापित करे। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि बनासकांठा मॉडल की तर्ज पर बायो–गैस प्लांट स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

.....

To Start P.G. Classes

336. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start P.G. Classes in Government College for women situated in village Badhra ; and

(b) if so, the time by which the said P.G. classes are likely to be started?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी, राजकीय महिला महाविद्यालय, बाढ़डा मे पैरा–स्नातक की कक्षाएं आरम्भ करने बारे कोई भी मांग प्राप्त नहीं हुई है।

.....

To Construct the Field Passages

214. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct following field passages falling under the Gohana Assembly Constituency-

(i) from Drain No. 6 to Panghat Kui in village Mahipur;

(ii) from field of Rambhaj S/o Balwan to Tubewell of Krishan S/o Hari Ram in village Machhri;

(iii) from main fields passage to field of Subhash S/o Chandgi in Village Majri;

(iv) from village to Chitana Chowk and from field of Bhagat Singh to Railway line in village Khijarpur Jaat Majra?

(v) From field of Chatar Singh S/o Nand Lal to field of Rajpal S/o Balbir in village Bhatgoan?

उप मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं, श्री मान जी, जिला प्रशासन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

.....

अनुपस्थिति की अनुमति

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जयवीर सिंह विधायक ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि पैर में चोट लगने के कारण वे चलने में सक्षम नहीं हैं इसलिए आज दिनांक 9 मार्च, 2021 को सदन में उपस्थित नहीं होंगे।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भिवानी जिले में पानी की भारी कमी से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा भिवानी जिले में पानी की भारी कमी से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–2 प्राप्त हुई हैं। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। अब श्रीमती किरण चौधरी विधायक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरा ध्यानाकर्षण नोटिस स्वीकार किया है। आज मैं बहुत सारे अखबारों की कटिंग साथ लेकर आई हूं। सभी अखबार चीख–चीख कर लोगों की आवाज उठाते हुए कह रहे हैं कि "हे सरकार कुछ तो करो इस बार, फसलों को पानी की दरकार, अन्नदाता पर सूखे की मार"। सर्दी में गर्मी के हालात बने हुए हैं। भिवानी को जितना पानी मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 365 गांव ऐसे हैं जो सारे के सारे यह कह रहे हैं जहां पर पूरी तरह से नहरी पानी नहीं मिल रहा है। 65 गांव में संकट इतना अधिक है कि सिंचाई के लिए तो दूर पीने के लिए भी पानी का टोटा पड़ा हुआ है। किसान कमेटियां बना रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भिवानी में पानी के हालात क्या हो रहे हैं ? जो नहरी पानी हमें मिलना चाहिए, वह हमें पूरा नहीं मिल रहा है, पता नहीं हमारे हिस्से का पानी काट कर कहां भेज देते हैं। यह हालात आपके सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी वजह से हमारी रबी की फसलें पानी से वंचित हो गई हैं। हमारे जलघर के जो टैंक्स हैं, वे खाली रह गये हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप अपना लिखित नोटिस पढ़िए। जब उसका जवाब सरकार की तरफ से आ जायेगा तब आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले में पानी की भयंकर किल्लत बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती है कि भिवानी जिले को काफी समय से पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी से रबी की फसलें सिंचाई से वंचित रह रही है। जलघरों के टैंकरों में भी पानी नहीं पंहुच रहा। जिसके कारण 1.70 लाख हैक्टेयर के करीब खेती को सिंचाई न मिलने के कारण किसानों की करोड़ों की फसलें खराब होने के कारण उन पर भयंकर आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुई फीडर, सुंदर ब्रांच नहर, गुजरानी माईनर में 2300 क्यूसिक पानी की डिमांड भेज रहे हैं और वास्तव में 1150 क्यूसिक पानी ही मिल रहा है। जोकि डिमांड का 50 प्रतिशत ही है। पानी की कमी के कारण किसान डीजल के माध्यम से ट्यूबवैल चलाकर करोड़ों का नुकसान सह रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सिंचाई विभाग की नहरों में पानी ना आने से कैरू, बीरण, रिवासा, कुसुम्भी, ढाणी माहू, बजीणा, बापोड़ा, सिवानी, जुई, बहल, तोशाम व अनेकों गांव की नहरों पर टेल तक भी पानी नहीं पंहुच रहा और भयंकर किल्लत का सामना कर रहे हैं। पूरे जिले में जलघरों के टैंकर भी सूख गए हैं और पीने का पानी भी बंद कर दिया गया है। जिससे गांव के रहने वाले गरीब आदमियों को पीने का पानी भी काफी कीमत चुकाकर लेना पड़ रहा है। पशुओं के लिए भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अभी तो ये सर्दी का मौसम है आगे जब मौसम गर्म होगा तो भयंकर सूखे की स्थिति बन जाएगी जो अत्यंत विकराल रूप ले लेगी। इसलिए समय रहते स्थिति का समाधान किया जाए और राज्य में पानी की उपलब्धतता की क्षेत्रवाईज आवंटन की स्थिति सदन के पटल पर स्पष्ट की जाए कि किस जिले को कितना पानी समय–समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। क्योंकि भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिले में पानी की अत्यंत कमी है और इसको डिमांड के अनुसार 30/40 प्रतिशत ही पानी उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार पूर्ण विवरण देते हुए राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को समानता के आधार पर पानी उपलब्ध करवाए।

वक्तव्य–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

श्री अध्यक्षः अब संबंधित मंत्री अपना जवाब देंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : श्रीमान जी,

- हरियाणा को दो स्त्रोतों नामतः भाखड़ा जलाश्य और यमुना नदी से आपूर्ति प्रदान होती है।
- 2020 के मानसून में भाखड़ा जलाश्य अपनी अधिकतम क्षमता 1680 फुट में से 1659.61 फीट तक ही भर पाया जो कि उसकी भराव क्षमता का 83 प्रतिशत है।
- भाखड़ा बांध में पिछले तीन वर्षो से जलाश्य का स्तर नीचे सारणीबद्व हैः–

अनुक्रमांक	वर्ष	जलाश्य स्तर (फुटों में) 3 मार्च को	पिछले वर्ष के सम्बंध में रिक्तिकरण/भरण (फुटों में)
1.	2019	1629.87	
2.	2020	1607.42	–22.45
3.	2021	1566.12	–41.30

- सतलुज और रावी ब्यास पानी के लिए 21.09.2020 को हरियाणा का अधतन हिस्सा 14,80,300 क्यूसिक दिन का है जिसका उपयोग 20.05.2021 जलाश्य की रिक्तिकरण अवधि समाप्त होने तक किया जाता है।
- 7860 क्यूसिक के सामान्य हिस्से के मुकाबले औसत दैनिक हिस्सा 6117 क्यूसिक है।
- हरियाणा ने पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के मौजूदा चार समूहों को चलाकर रबी फसलों की बुवाई के लिए अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में औसत हिस्सेदारी से अधिक पानी प्रयोग किया है।
- संग्रहित पानी की विकट कमी के कारण, हरियाणा ने टेल बी एम एल सिस्टम को मौजूदा 16 दिनों के रोटेशन वाले दो समूहों से 8 दिनों के रोटेशन की अवधि वाले तीन समूहों पर प्रवर्तित किया है। इसी प्रकार पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में नवम्बर 2020 के अंत में पहले के चार समूहों के स्थान पर पांच समूहों पर प्रवर्तित कर दिया है।
- यमुना नदी से आने वाला प्रवाह भी लगभग 1000 क्यूसिक तक कम हो गया है।
- सर्दीयों के मौसम में अल्प वर्षा हुई है।
- सिंचाई के मुकाबले जलघर टैंक, ग्राम तालाबों को भरने के लिए प्राथमिकता दी गई।
- सरकार द्वारा अनुमोदित रोटेशनल प्रोग्राम के अनुसार ही चैनलों में पानी छोड़ा गया।
- सिंचाई के अलावा सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय विभाग, एच एस आई डी सी, थर्मल रिफाइनरी तथा उद्योगो को पीने के पानी की आपूर्ति करता है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली के लिए 1050 क्यूसिक की नियमित आपूर्ति की जा रही है।
- गुरूग्राम में पीने के लिए 420 क्यूसिक की नियमित आपूर्ति की जा रही है।
- हरियाणा के लिए सतलुज और रावी ब्यास के पानी का शेष हिस्सा 01.03.2021 को 337614 क्यूसिक दिन है जबकि औसत दैनिक हिस्सा 4168 क्यूसिक है।

2019–20 और 2020–21 के दौरान राज्य में पानी की कुल उपलब्धताः

2019–20				2020–21		
माह	भाखड़ा बांध से (क्यूसिक दिन में)	युमना से (क्यूसिक दिन में)	कुल (क्यूसिक दिन में)	भाखड़ा बांध से (क्यूसिक दिन में)	यमुना से (क्यूसिक दिन में)	कुल (क्यूसिक दिन में)
अक्तूबर	238366	239733	478099	255775	87281	343056
नवम्बर	250402	73943	324345	254832	56600	311432
दिसम्बर	259019	62392	321411	235825	46473	282298
जनवरी	267044	91126	358170	229632	43738	273370
फरवरी	259217	64612	323829	210623	25502	236125
कुल	**1274048**	**531806**	**1805854**	**1186687**	**259594**	**1446281**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 के दौरान यमुना में कुल उपलब्धता घटकर 50 प्रतिशत हो गई है।

2019–20 और 2020–21 के दौरान मूनक में पानी की कुल उपलब्धताः

2019-20				2020-21		
माह	भाखड़ा बांध से (क्यूसिक दिन में)	यमुना से (क्यूसिक दिन में)	कुल (क्यूसिक दिन में)	भाखड़ा बांध से (क्यूसिक दिन में)	यमुना बांध से (क्यूसिक दिन में)	कुल (क्यूसिक दिन में)
अक्तूबर	50233	211887	262120	73683	70297	143980
नवम्बर	46790	63336	110126	65990	37828	103818
दिसम्बर	63693	51725	115418	63733	26742	90475
जनवरी	65808	53233	119041	52658	26266	78924
फरवरी	59247	39280	98527	62192	18111	80303
कुल	**285771**	**419461**	**705232**	**318256**	**179244**	**497500**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 के दौरान मूनक में कुल उपलब्धता घटकर 29.45 प्रतिशत हो गई है।

जुई फीडर के कमान क्षेत्र मोहला हैड से गुजरानी माईनर यानि सुन्दर उपशाखा की बुर्जी संख्या 121361 जिसमें 2019–20 और 2020–21 के दौरान पानी की कुल उपलब्धता निम्न है

माह	पी0ओ0 ग्रुप	चालू दिन	पानी छोड़ा गया (क्यूसिक दिन में)	चालू दिन	पानी छोड़ा गया (क्यूसिक दिन में)	औसत प्रतिदिन (क्यूसिक में)	
		2019		**2020**		**2019**	**2020**
अक्तूबर	सुन्दर	8	18499	8	13374	2313	1672
	बुटाना	8	11846	10	3091	1481	309
नवम्बर	सुन्दर	8	15354	9	12516	1919	1391
	बुटाना	8	5322	10	2592	665	259
दिसम्बर	सुन्दर	8	12102	11	13812	1513	1256
	बुटाना	8	4784	5	2152	598	430
जनवरी	सुन्दर	8	16864	1	612	2108	612
	बुटाना	8	5813	5	3290	727	658
फरवरी	सुन्दर	6	8882	8	8850	1480	1106
	बुटाना	--	--	10	3359	--	336
कुल		**70**	**99466**	**77**	**63648**	**1421**	**827**

उपर से यह स्पष्ट है कि मुनक हेड पर पानी की कुल उपलब्धता का 13 प्रतिशत मोहला हेड के लिए वर्ष 2020–21 में अक्तूबर से फरवरी के बीच में जारी किया गया था जबकि वर्ष 2019–2020 में यह 14 प्रतिशत का था।

- भिवानी में सिंचाई अक्तूबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान कुल 183484 हेक्टेयर में से लगभग 156826 हेक्टेयर में हुई है जो कि 85.47 प्रतिशत है।
- भिवानी में सिंचाई अक्तूबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान कुल 183484 हेक्टेयर में से लगभग 155210 हेक्टेयर में हुई है जो कि 84.59 प्रतिशत है।
- उपर से यह देखा जा सकता है कि यमुना नदी की अन्तर्वाह में 50 प्रतिशत की कमी के बावजूद, चैनलों का इस तरह से प्रावधान किया है कि अधिकतम क्षेत्र कमांड के तहत आ जाए।
- इस आपूर्ति के साथ प्रत्येक बारी (P.O) में 308 जलघर टैंकों को भरा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः–

माह	2019–20 के दौरान भरण क्षमता			2020–21 के दौरान भरण क्षमता		
	<50%	<75%	>75%	<50%	<75%	>75%
अक्तूबर	0	74	234	0	80	228
नवम्बर	0	77	231	0	84	224
दिसम्बर	0	74	234	0	81	227
जनवरी	0	83	225	0	80	228
फरवरी	0	83	225	0	80	228

- चैनल का अधिकृत क्षमता ही उसकी स्वीकृत क्षमता होती है जिसे 2.40 क्यूसिक प्रति हजार एकड़ क्षेत्र के मापदण्ड पर गणन किया जाता है, इसके साथ नहर संचारण में विभिन्न जल प्रवाह क्षतियों तथा स्वीकृत जलघर टैंकों, तालाबों और भविष्य के विकास के लिए 10 प्रतिशत हिस्सा जोड़ा जाता है।
- पानी का इंडेंट आम तौर पर अनुप्रवाह (downstream) क्षेत्र की मांग को शामिल करके टेल से ऊर्ध्वप्रवाह (upstream) तक पंहुचने वाले सिस्टम के कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा की गई पानी की मांग/आवश्यकता होती है और डिस्ट्रीब्यूटिंग हैड के प्रभारी कार्यकारी अभियंता को समेकित इंडेंट दिया जाता है। पानी की उपलब्धता कम होने पर इंडेंट अधिकृत डिस्चार्ज होते है और पानी की उपलब्धता ज्यादा होने पर बारिश के मौसम में यह ज्यादा होता है।
- सुंदर समूह की बुर्जी संख्या 121361 पर मोहला हैड पर सुंदर ग्रुप का अधिकृत निष्कासन 1215 क्यूसिक है। अक्तूबर, 2020 से फरवरी 2021 की अवधि में सिवाए जनवरी एवं फरवरी के कुछ दिन छोड़ कर जिसमें यमुना नदी में पानी की कमी रही है, मोहला हैड पर पानी की आपूर्ति इस समूह की अधिकृत क्षमता, जोकि 1215 क्यूसिक है से अधिक रही है। इसके अलावा, 2300 क्यूसिक निष्कासन की मांग/इंडेट को केवल अतिरिक्त आपूर्ति के मामले में पूरा किया जा सकता है जो 2020–21 के दौरान उपलब्ध नही है।
- कैरू, बीरन, रिवासा, कुसुंभी, धानी महू, बजिना, बपोरा, सिवानी, जुई, बेहल और तौशाम गांवों के क्षेत्र सुंदर सब बांच्र की बुर्जी संख्या 121361 से पानी प्राप्त करते हैं, जो बुटाना शाखा से निकल के जो आगे हांसी शाखा जो मुनक हैड से निकलती है। यमुना नदी में पानी की कम उपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों की कुछ माईनर पर पानी आपूर्ति नहीं की जा सकी लेकिन अत्यंत कमी के बावजूद, चैनल इस तरह से चलाए गए कि इन क्षेत्रों में सभी जलघर टैंक लगभग भरे गए है परन्तु जुई और निगाना प्रणाली के पानी के टैंक को छोड़कर, जो उनकी क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक भरा गया। इसके इलावा, इन क्षेत्रो में जानवरों की प्यास बुझाने के लिए लगभग 234 गांव के तालाब भी भरे गए है।
- अनुमोदित रोटेशनल प्रोग्राम के अनुसार हरियाणा राज्य में सभी जिलों को समान आधार पर पानी की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, सिंचाई विभाग के प्रमुख चैनल एक से अधिक जिलों से होकर गुजरते हैं और चैनल के हेड पर डिस्चार्ज/गेज को मापा जाता है, जबकि चैनल का हिस्सा/अंतिम छोर विभिन्न जिलों/जिले में खत्म हो सकती है। इसलिए किसी विशेष जिले में वितरित किए जा रहे निर्वहन के स्टीक माप का आकलन

नही किया जा सकता है। फिर भी वर्ष 2019–2020 और 2020–2021 के दौरान विभिन्न जिलों में पानी का अस्थायी (Tentative) वितरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	2019-20	2020-21	वर्ष 2019–20 की तुलना में 2020–21 में वितरित पानी का प्रतिशत (%)
1	अम्बाला	6127	5270	86.01
2	कुरूक्षेत्र	12635	9219	72.96
3	रेवाडी	58096	51043	87.86
4	महेन्द्रगढ़	59510	49949	83.93
5	पानीपत	28877	13590	47.06
6	यमुनानगर	4873	3659	75.09
7	चरखीदादरी	50347	36334	72.17
8	भिवानी	136377	112567	82.54
9	गुड़गांव	63420	63420	100
9	फरीदाबाद, पलवल, नूंह	86431	60047	69.47
10	रोहतक	73091	53324	72.96
11	झज्जर	44381	23342	52.59
12	सोनीपत	47836	29964	62.64
13	जीन्द	77709	67990	87.49
14	फतेहाबाद	114032	117794	103.30
15	हिसार	26732	19381	72.50
16	सिरसा	335981	269192	80.12
17	करनाल	14299	5452	38.13
18	कैथल	51618	33498	64.90

यह बात सही है कि भिवानी जिले में पानी की कमी रही है। इस क्षेत्र के साथ पानी का भेदभाव होता रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के शासन काल के दौरान टेल तक पानी पहुँचाने की बात हुआ करती थी लेकिन मेरे क्षेत्र के लोहारू कैनाल, झुंपा कैनाल, धनकौरा कैनाल और सोरा कैनाल के हेड तक भी पानी नहीं पहुँचा था। हमेशा से ही पानी के नाम पर भेदभाव होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 25 सालों तक उन नहरों में कभी भी पानी नहीं पहुँचा था, अब कहीं जाकर उन माइनरों में पानी आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता आज पानी की कमी का राग अलाप रहे हैं। सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी भी पानी की डिमाण्ड ही नहीं की थी। हमारी सरकार ने पानी का समान बंटवारा किया है। हमारी सरकार यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण की मुस्तैदी से पैरवी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में तो 31 टेलों तक पानी नहीं पहुँचता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दक्षिण हरियाणा में पानी का बराबर बंटवारा किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने केवल तीन टेलों को छोड़कर सभी टेलों पर पानी पहुँचाने की कोशिश की है।

हांसी बुटाना चैनल बना तो दी लेकिन इसमें भी तकनीकी खामियां कांग्रेस पार्टी के शासन काल में छोड़ दी गईं अर्थात् इस नहर के निर्माण में बी.बी.एम.बी. (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) से कोई अनुमति नहीं ली गई। इस नहर को बनाने में 400–500 करोड़ रुपये खराब कर दिये हैं। हमारी सरकार दक्षिण हरियाणा को पानी देने की बराबर कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता अखबार की कटिंग दिखाते हैं लेकिन उन्हें धरातल की कोई जानकारी नहीं होती है। आज भिवानी क्षेत्र को बराबर पानी मिल रहा है। भिवानी की जनता इस बात की गवाह है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही लम्बा–चौड़ा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। माननीय मंत्री जी पानी को लेकर जो पुरानी सरकारों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि लोहारू के हर गांव के अंदर मैंने ही जलघर बनवाये थे और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने धन्यवाद भी किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एस.वाई.एल. के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। सरकार झूठ पर झूठ बोलती है और प्रदेश की जनता को गुमराह करती है।

श्री अध्यक्षः बहन किरण जी, आप दिल्ली विधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर भी रही हैं, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। आप केवल सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बी–चौड़ी बात की है, इसलिए I have to rebut him. (Interruption) I will have to rebut him everything that he has said. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप कॉलिंग अटैंशन मोशन पर सप्लीमैंट्री पूछ सकती हो।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब हम पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो हमको उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा । माननीय मंत्री जी ने हमारी सरकार को लिखित में धन्यवाद किया हुआ है । हमने माननीय मंत्री जी के हल्के के हर एक गांव में जलघर की व्यवस्था करवाई थी । इनको तो अब वहां पर कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है । आज माननीय मंत्री जी जिन कामों की बात कर रहे हैं वे सारे काम तो हमारी सरकार के समय करवाये गए थे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप सरकारों के कामों के कम्पैरीजन पर बात करने की बजाय सदन में अपना विषय रखिये ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सत्ता पक्ष का कोई सदस्य एस.वाई.एल. नहर की बात ही नहीं करता जबकि सरकार में आने से पहले इसी नहर के लिए झूठे उपवास करते थे । (विघ्न) आज सत्ता पक्ष का कोई भी माननीय मंत्री इस सदन में दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए एस.वाई.एल. नहर की बात ही नहीं करता । (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने एस.वाई.एल. नहर के लिए पूरे जोर–शोर से मांग की है जबकि विपक्ष यही कहता रहा कि पंजाब के साथ भाईचारा निभाओ । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ? जो किसानों की शहादत पर मखौल उड़ा सकते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ? (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार है । विपक्ष के माननीय सदस्य उनसे हरियाणा को एस.वाई.एल. नहर के द्वारा पानी देने की बात क्यों नहीं करते ? (विघ्न)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एस.वाई.एल. नहर के विषय पर बोलना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान) मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । माननीय सदस्य श्रीमती किरण चौधरी ने मेरा नाम लिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी का नाम नहीं लिया है । (Interruption) I did not take your name. (Interruption). I did not take your name. अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं और उसको जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है यह बहुत दुर्भाग्य की बात है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पीछे से पानी कम आ रहा है । यह बात ठीक है कि पानी कम आ रहा है लेकिन दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी से भिवानी के पानी को बहुत कम करके जे.एल.एन. ग्रुप को पानी की सप्लाई दी जा रही है । जो पानी सबको बराबर मिलना चाहिए उसको एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में ले जाने की कोशिश की जा रही है । अभी पूरा रिवाड़ी, मेवात, भिवानी और दादरी जिला त्राहि–त्राहि कर रहा है । इसके बाद माननीय मंत्री जी यहां पर कहते हैं कि 'we cannot give you any kind of measurement because the

precise measurement of discharge being delivered to any particular district cannot be assessed because it falls under various districts.' यह तो बिल्कुल ही गुमराह करने वाली बात है । हमको यह भी नहीं बताते है कि हमको कितना पानी मिल रहा है, कितने पानी पर हमारा हक है आदि । हमारे को इंडैंट के हिसाब से कहीं पर 50 परसैंट, कहीं पर 40 परसैंट, कहीं पर 30 परसैंट कम पानी दिया जा रहा है । हमारे दादरी–भिवानी जिलों के साथ पानी के मामले में बहुत ज्यादती हो रही है । मैं 9.02.2021 तक का सारा डाटा लेकर आई हूं । हमको हर जगह जो पानी मिलना चाहिए उसकी तो बात छोड़िये बल्कि हमको जो पानी मिल रहा है सरकार द्वारा वह भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है । इसका नतीजा यह है कि मेरे क्षेत्र के 65 गांवों से अधिक गांवों में पीने के पानी की किल्लत है । मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को गलत नहीं ठहरा रही हूं । पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट इसमें क्या करेगा जब पानी ही नहीं आएगा । जब पानी ही नहीं आएगा तो वह जलघर कैसे भरेंगे ? सरकार द्वारा पानी गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है । हमको कम से कम 2300 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए । इतनी ही मात्रा में पानी के लिए वहां के अधिकारियों ने सरकार के पास मांग भेजी हुई है लेकिन हमें केवल 1150 क्यूसिक पानी ही मिल पा रहा है । भिवानी में मिलने पाली को कम करने के लिए हमारे हिस्से का पानी जे.एल.एन. ग्रूप को दिया जा रहा है । आज हमारे क्षेत्र में पानी की सप्लाई की यह हालत है । मेरा कहना है कि भिवानी, मेवात, दादरी, रिवाड़ी जिले हरियाणा से बाहर तो नहीं हैं । इस बारे में सारे अखबार चीख–चीखकर कह रहे हैं । माननीय मंत्री जी चाहे अखबार की कटिंग को न मानें, लेकिन जो हमारे पास मोटे–मोटे शिकायतों के पोथे आते हैं उनमें लिखा होता है कि हमारे गांवों में पानी नहीं है, हाय हम क्या करें ? इसके लिए किसान भाई इकट्ठे बैठकर कमेटीज बना रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन किया जाए ? इस समय वहां पर यही हो रहा है। वर्तमान सरकार का इन सारी चीजों का ठीकरा पहले वाली सरकार के ऊपर फोड़ना गलत है क्योंकि प्रदेश में पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे पता है कि ये सारी चीजें कहां से चल रही हैं ? मैं उस बात को सदन में बताऊंगी तो हंगामा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारे साथ जो ज्यादती की जा रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिस्से का पानी लेना हमारा हक है। सरकार हमें लिखित में दे कि भिवानी जिले को कितना पानी दिया जाना

है? हमारा जितना इन्डैंट है, उससे कितना कम पानी आ रहा है ? हमें सुन्दर ब्रान्च/यमुना कैनाल से जितना पानी मिलना चाहिए, उसमें से हमें कितना पानी दिया जा रहा है? दूसरी अहम बात यह रखना चाहती हूं और उसको सरकार भी जानती है कि दक्षिण हरियाणा के लिए एस.वाई.एल. जीवन रेखा है और इस बात को सभी मानते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य इस बात को नहीं मानता है तो वह खड़े होकर बता दे।

श्री अध्यक्षः किरण जी, एस.वाई.एल. का इशू इसमें न रखें। आप सिर्फ भिवानी जिले के बारे में ही अपनी बात रखें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एस.वाई.एल. के पानी के संबंध में हमारे हक में फैसला दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह पानी मिलने से सबको फायदा होगा।

श्री अध्यक्षः किरण जी, एस.वाई.एल. का लम्बा इशू है, इसलिए आप इस पर डिस्कशन करेंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि इस एस.वाई.एल. के इशू को राजनीति की भेंट न चढ़ाएं। माननीय मंत्री जी केवल उपवास करके न दिखाएं क्योंकि आने वाला समय इसके गम्भीर परिणाम लेकर आएगा।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो दक्षिण हरियाणा के संबंध में बात की है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। डॉ0 अभय सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए। मैं इसी विषय पर बहुत महत्वपूर्ण इन्फार्मेशन देना चाहता हूं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ0 साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

चौधरी आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने भिवानी जिले के संबंध में सभी वॉटर वर्क्स का डाटा मंगवाया है। इसके अनुसार स्थिति यह है कि 229 कैनाल बेस्ड वॉटर वर्क्स हैं। उनमें से 185 पानी से पूरे भरे हुए हैं और 50 से 100 प्रतिशत पानी के भरे हुए 38 वॉटर वर्क्स हैं। इनमें 6 ऐसे वॉटर वर्क्स हैं जो आधे से कम पानी के भरे हुए हैं। इनका सर्टिफिकेट संबंधित गांवों के सरपंचों से लिखवाकर लाए हैं। माननीय सदस्या ने पिछले 1 साल में 2 बार ही तोशाम हल्के में जाकर दर्शन दिये हैं। इसलिए इनको वास्तविकता की जानकारी नहीं है। मैं सिवानी में रहता हूं। इनको वहां पर न जाने की वजह से गलतफहमी हो गयी है और किसी ने इनको गलत रिपोर्ट दी है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे हल्के के विषय में बात न करें। मैं भी माननीय मंत्री जी के हल्के की बात बताना शुरू कर सकती हूं। माननीय मंत्री जी मेरे ऊपर कटाक्ष न करें। ****

श्री अध्यक्षः किरण जी ने जो अनपार्लियामैंटरी शब्द यूज किये हैं, उनको सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपने हल्के में नहीं जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जब 10 साल तक मंत्री रही तो हमारे हिस्से का पानी कोई और ले जाता था, तब इन्होंने कोई आवाज नहीं उठायी। हमारे एरिया के लोगों को आज अपने हिस्से का पानी मिल रहा है। आज प्रदेश के सभी किसान खुश हैं क्योंकि हमारी सरकार ने भेदभाव की नीति को खत्म किया है। सभी के साथ बराबर का व्यवहार करके समान पानी का बंटवारा किया गया है और सभी को पानी मिल रहा है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी सच्चाई बता सकती हूं।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस तरह से बोलेंगी तो इनका गला बैठ जाएगा, इसलिए इनको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पिछले 25–30 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 20–25

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

नहरों में पानी दिखायी दिया है। किसान इस बात के गवाह हैं और उनकी फसलें भी इस बात की गवाह हैं। इनको कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में कुर्सी जाने का डर था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय माननीय सदस्या को कुर्सी जाने का डर था। माननीय सदस्या भिवानी जिले के आम किसानों को यह बता कर बहकाती रही कि मैं मोटी कलम लेकर आउंगी, परन्तुहुड्डा साहब ने पता नहीं उस मोटी कलम को कहां पर छुपा दिया है। उस कलम को दिखने नहीं दिया और छोटी कलम भी नहीं छोड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के समय में भिवानी जिले के साथ पानी के मामले में बहुत बड़ा भेदभाव हुआ था। हमारी सरकार ने उस भेदभाव को दूर करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि कोई मंत्री इस प्रकार से जवाब दे रहा है। आप उन्हें रोक भी रहे हैं। हमने यह तरीका इस हाउस में इससे पहले कभी नहीं देखा है। इस विधान सभा में मेरी नौवीं टर्म है लेकिन मैंने इस किस्म से कभी भी एक मिनिस्टर को जवाब देते हुए नहीं देखा है।

श्री जय प्रकाश दलाल: स्पीकर सर, अगर कोई सवाल पूछेगा तो मुझे फैक्टस के साथ जवाब देना ही पड़ेगा। इस मामले में भी मैंने फैक्ट्स के साथ सदन में जानकारी दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं। इन्होंने यह कहा कि हरियाणा में पानी की कमी है। इनकी यह बात सही है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा में पानी भाखड़ा नहर से आता है। भाखड़ा को बी.बी.एम.बी. कंट्रोल करता है। मंत्री जी को यह भी पता होना चाहिए कि बी.बी.एम.बी. को कौन कंट्रोल करता है। मैं इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जब से बी.बी.एम.बी. बना उसका चेयरमैन कभी भी हिमाचल प्रदेश का नहीं बना। उसमें जो पॉवर का मैम्बर रहा है वह पंजाब का रहा है और उसमें जो इरीगेशन का मैम्बर रहा वह हरियाणा का रहा। आज की

तारीख में बी.बी.एम.बी. में हरियाणा की साइड से का इरीगेशन का कोई भी मैम्बर नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में बी.बी.एम.बी. में हरियाणा के हितों की रक्षा कौन करेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय हुड्डा साहब को यह बताना चाहूंगा कि हम अपना हक लेने में पूरी तरह से सक्षम हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कृषि मंत्री जी यह कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय में भिवानी में पानी नहीं मिला। मैं इनको चैलेंज करता हूं भिवानी के किसी भी गांव में ये मेरे साथ चलें। वहां चलकर हम लोगों से सीधे–सीधे ही इसके बारे में पूछ लेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वे हुड्डा साहब का चैलेंज स्वीकार करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका व्यवहार बिलकुल भी ठीक नहीं है। जो आप बोल रही हैं यह पूरी तरह से गलत है और सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आप जो भी बोलें सोच समझकर ही बोलें। (विघ्न) जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं वह सदन की भाषा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मेरा आपको यही कहना है कि आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें। (शोर एवं व्यवधान) आपकी भाषा बिलकुल गलत है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी भाषा के ऊपर संयम रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय हुड्डा साहब को यह बताना चाहूंगा कि मेरे इलाके के अंदर झुंपा कैनाल है और मेरे इलाके के अंदर शोरा डिस्ट्रीब्यूट्री है जब तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही इनकी टेल की तो दूर की बात हैड पर भी पानी नहीं मिला। स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि जब तक मैडम किरण चौधरी मंत्री रही हमारे इलाके के अंदर लोहारू कैनाल, झुंपा कैनाल, दमकौरा कैनाल और शौरा डिस्ट्रीब्यूट्री में एक बूंद भी पानी नहीं आया क्योंकि इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। इन्होंने प्रदेश के किसानों की कभी भी चिंता नहीं की।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मंत्री जी, अब आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री बलराज कुण्डु : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : कुण्डु जी, आप कृपा करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) बलराज कुण्डु जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्रीमती शकुंतला खटक : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : शकुंतला जी, आप कृपा करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब न करें। आप एक सीनियर मैम्बर हैं इसलिए आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) शकुंतला खटक जी जो मेरी अनुमति के बगैर बोल रही हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री बलराज कुण्डु : स्पीकर सर, ***

श्रीमती शकुंतला खटक : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य मेरी परमिशन के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाये।

———

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार सदन में रखेंगे।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवादी हूं। हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख है–अनोभद्रा कृत्वो यंतु विश्ववतः अर्थात् हमारे लिए सभी से कल्याणकारी विचार आयें। इन सभी कल्याणकारी विचारों को माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार को लेकर अपने अभिभाषण में व्यक्त किया। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे प्रदेश के चहुंमुखी विकास की बात हो, चाहे प्रदेश को किसी भी नाते ऊपर ले जाने की बात हो इस लाइन को फोलो करते हुए हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर इस गठबन्धन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। कोविड–19 के घातक वायरस ने पूरे संसार को हिलाकर

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

रख दिया। इसके बावजूद भी सभी लोगों ने कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में अपना–अपना योगदान दिया। मैं सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के उन सभी लोगों का धन्यवादी हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए काम किया और दूसरों के कल्याण की कामना की। इसके अलावा मैं अनगिनत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी साथी, स्वच्छता कर्मचारी भाई, राजस्व अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और सारे स्वयंसेवकों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमें इस सदन में अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हमारे औषधीय उद्योग के जो लोग हैं हमें उनका भी आभार प्रकट करना चाहिए। आज हमारे लिए बड़े गर्व का समय है। हमको सन् 1947 के बाद की एक घटना को याद करना चाहिए जब हमारी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर जी पैंसिलीन की वैक्सीनेशन लेने के लिए कनाडा गई थी लेकिन आज उसी कनाडा को हम अपनी को–वैक्सीन की खेप को भेज चुके हैं। इस वैक्सीन को कोरोना के ईलाज के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने डिवैल्प किया है। इस वैक्सीन की कनाडा हमसे लगातार मांग कर रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस वैक्सीन के निर्माण में और वैक्सीन के विकास में सबसे आगे है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हमारे मेहनतकश साथी जम्मू–कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और चण्डीगढ़ के अंदर विभिन्न इण्डस्ट्रीज के अंदर काम करते थे जब ये कोविड–19 का माहौल चला और लॉक–डाउन लगा उसके बाद जब सभी ने अपने–अपने घर जाने का फैसला किया तो क्योंकि अम्बाला बॉर्डर के ऊपर स्थित है इसलिए वहां पर दूसरे राज्यों से एक अफवाह फैला दी गई कि अम्बाला कैंट से ट्रेने चल रही हैं। इसके बाद वे मेहनतकश साथी 300–400 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने की आस लिए हजारों की संख्या के अंदर अम्बाला के अंदर एकत्रित हो गये। जब मैंने इस सम्बन्ध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो उन्होंने स्पैशल ट्रेनों और बसों को अम्बाला से चलवाया और लगभग पूरे प्रदेश से 4,44,422 हमारे श्रमिक साथियों को 100 ट्रेनों में और लगभग 6500 बसों के माध्यम से उनके घर पहुंचाया गया। अध्यक्ष महोदय जी, जो पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था है उसके प्रति हमारी कमिटमैंट की बात हो हमारी सरकार उसके ऊपर भी 100 प्रतिशत खरी उतरी है। ट्रिपल पी अर्थात परिवार पहचान परिपत्र के नाते प्रत्येक परिवार को एक

यूनीक डिजिट का अपना एक कोड मिला और इसके तहत पेपरलैस और फेसलैस जो सेवा प्रदान करने का एक माध्यम हमारी सरकार ने चलाया इसी के कारण हम सभी लोगों को दलाली और दलालों से छुटकारा मिला। हमारे जो अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं जिन लोगों ने इसमें विशेष योगदान दिया मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं एक और बात मैं इस महान सदन में अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथीगण यहां पर बैठे हैं। हम दूसरी बार इस सदन में चुनकर आये हैं। यह हमें भी बार–बार सिखाया गया कि सामने लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाये, यदि प्रवेश किया जाये तो बड़ी स्पष्ट और सच बात कही जाये क्योंकि यहां पर न बोलने से या फिर गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो ये कृषि कानून हैं जिनके बारे में आज एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, मैं हमारे साथियों को कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2013–14 में यू.पी.ए. की सरकार थी उस समय 98 हजार करोड़ रुपये का बजट देश के किसानों की फसल खरीदने के लिए रखा गया था। आज वर्ष 2020–21 के बजट की बात की जाये तो हमारे जननायक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बजट को बढ़ा कर 2.47 लाख करोड़ रुपये करने का काम किया है जो कि 98 हजार करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। यह हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि न एम.एस.पी. खत्म होने जा रही है और न ही मंडियां खत्म होने जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, 9 फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद हमारी प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। गन्ने का सर्वाधिक मूल्य पूरे भारत में हमारी प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत के नाते फसल के चक्रीकरण की एक विधा को अपनाने वाले किसान साथी को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

श्री अध्यक्षः असीम जी, आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप जल्दी से वाइंडअप कीजिए।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात को समाप्ति की ओर लेकर जा रहा हूं। मैं इसी विषय से संबंधित बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से अगर मुआवजे की बात की जाये तो हमने 115 करोड़ रुपया तो केवल रबी की फसल के लिए मुआवजे के रूप में बांटा है जबकि पुरानी सरकारों के समय में 5–5 रुपये के चैक आते थे। अध्यक्ष महोदय, किसान साथियों को लेकर जो लोग बातें करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी अपनी सरकारों के समय आपने जो किसान

भाइयों की जमीनें हथियाने का काम किया था वे केस कोर्ट में चल रहे हैं, वे केस कहीं बंद नहीं हुए हैं। ये कांग्रेस के साथी तारीखें भुगत रहे हैं और इनके इंटरनैशनल प्रमुख रॉबर्ट वाड्रा भी इन केसिज में अपनी पेशियां भुगत रहे हैं। किसान भाइयों की जमीनों को हड़पने वाली कांग्रेस आज किसानों की बात कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं, क्या ये सभी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखी हुई हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के मुद्दे पर ही अपनी बात रख रहा हूं। 135–140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को राइट टू फूड मिला हुआ है। इस नाते से एम.एस.पी. कभी बंद नहीं हो सकता है। आज मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि किसी मंच पर आयें और इन कृषि कानूनों पर हम बहस के लिए तैयार हैं। हमारे कांग्रेस के साथी काला कानून, काला कानून कहते रहते हैं। कल हमारी बहन श्रीमती गीता भुक्कल ने कहा था कि बाबुओं को पंचायतों की पावर दे दी लेकिन हमारी सरकार ने दोबारा सरपंचों को 5–5 लाख तक के काम करवाने की पॉवर दे दी है। इनकी पार्टी के नेता, छोटे पप्पू गाली देकर बोलते हैं फिर ये कहेंगे कि जो हाउस का सदस्य नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने सरकार को बहन की गाली दी ताकि किसानों के बीच जा कर किसानों को उकसाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसी बिल्डिंग में पंजाब विधान सभा के इन्हीं के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि यदि हमें खरीद करनी है तो हरियाणा की खरीद पद्धति से हमें सीख लेनी चाहिए। मेरे कांग्रेस के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि ये कांग्रेसी सच्चे हैं या वे सच्चे हैं। इसी बिल्डिंग में इसी सत्र में उन्होंने यह बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि वे इस सदन की बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, हमारी महिला बहनों को स्थानीय चुनावों और पंचायत चुनावों में जो 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं कि मननीय साथी ने सरकार के खिलाफ धरना दिया था उसके

बारे में भी बताएं कि धरना क्यों दिया था? (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के साथियों में से किसने व्यवस्था के खिलाफ धरना दिया? मैंने सरकार के खिलाफ धरना नहीं दिया। आप बताईये कि आप में से किसने कभी व्यवस्था के खिलाफ धरना दिया? आप लोग तो उन किसानों के हत्यारे हो। (शोर एवं व्यवधान) आप उनकी जमीने खा गये। आप धरना दे ही नहीं सकते हैं। आप अपने मन के अन्दर का शीशा देखकर बताएं। आप लोग किसानों के हत्यारे हो। यू.पी.ए. के समय में कितनी हत्याएं होती थी। आप लोग कितने लोगों की जमीनें खा गये। आपके समय में 92 हजार एकड़ की सी.एल.यू. हुई है। वह कहां गई? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, आप सम–अप कीजिए।

श्री असीम गोयल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम–अप कर रहा हूं। आप इन कांग्रेस के सदस्यों को कहें कि ये मुझे डिस्टर्ब न करें।(शोर एवं व्यवधान) मै अपनी बात रख रहा हूं। अगर इनको कोई दिक्कत है तो ये बाद में बोल लें।(शोर एवं व्यवधान) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे गांव में एक मॉडल संस्कृति विद्यालय खोलने का काम किया है।(शोर एवं व्यवधान) बहन जी, आप उन काले कानूनों का नाम ही बता दीजिए। आप इनका नाम देखकर मत बताईये। आप उन तीनों कानूनों का नाम बताईये। उससे पता चल जाएगा कि आप किसानों के कितने हितेषी हैं। आप बिना पढ़े उन तीनों कानूनों का नाम बता दीजिए।(शोर एवं व्यवधान) ये केवल बोलना जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है थूको और भागो। ये किसानों के हिमायती बनते हैं, ये उन तीन कानूनों का नाम बता दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिना पढ़े उन तीनों कानूनों का नाम बता दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, आप वाइंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वाईंड अप कर दिया है लेकिन ये उन तीनों कानूनों का नाम बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे माफी मंगवाईये।(शोर एवं व्यवधान) **(इस समय कांग्रेस पार्टी के विधायक वैल में आ गये।)**

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिना पढ़े उन तीनों कानूनों का नाम बता दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे माफी मंगवाईये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अन–पार्लियामैंट्री शब्द नहीं बोला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाइये।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिना पढ़े उन तीनों कानूनों का नाम बता दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बतरा जी, मैंने यह कह दिया है कि अगर इन्होंने कोई अन–पार्लियामैंट्री शब्द कहा है तो वह रिकॉर्ड में नहीं आएगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे माफी मंगवाईये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, माफी तो इनको मांगनी चाहिए। ये किसानों को आत्म हत्या के लिए उकसाने वाले लोग हैं। उनकी जमीनें हड़पने वाले हैं। उनके नाम के ऊपर व्यापार करने वाले है। ये लोग किसानों के हत्यारे हैं। ये अपने दस साल के शासन काल की माफी मांगिए कि यू.पी.ए. के शासनकाल के दौरान कितने किसानों की हत्याएं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, आप वाइंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वाइंड अप कर दिया है लेकिन ये उन तीनों कानूनों का नाम बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शकुन्तला जी, आप वैल में ऐसे नहीं बैठ सकती आप अपनी सीट पर बैठिये। यह कोई अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिना पढ़े उन तीनों कानूनों का नाम बता दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : असीम जी, आप वाइंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वाइंड अप कर दिया है लेकिन ये उन तीनों कानूनों का नाम बता दें। (शोर एवं व्यवधान) मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कह दिया है कि अगर इन्होंने कोई अन–पार्लियामैंट्री शब्द कहा है, तो वह रिकॉर्ड में नहीं आएगा।(शोर एवं व्यवधान) अब किरण चौधरी जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब गवर्नर साहब का अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तो ऐसा आभास हो रहा था जैसे बागों में बहार है स्वदेश के विकास और जन कल्याण के अन्दर भी पूरी बहार है लेकिन ये जो सत्ता पक्ष का नैरेटिव है उसको मैं सिरे से नकारती हूं और मैं सरकार को उसकी असलियत का आईना दिखाना चाहती हूं इसलिए मुझे बिना व्यवधान के बोलने दीजिए। मैं अपने प्वॉयंट पूरे करूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का किसान, छोटा व्यापारी व उद्यमी पूरी तरह से त्रस्त है। रोजगार के लिए आस जुटा रहे बच्चों के हौंसले पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं। यह इस सरकार का असली चेहरा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के 14 से लेकर 18 पैरा के तहत किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है लेकिन आय दोगुनी की बात तो दूर रही आज देश के इस धरती पुत्र को धरने पर बैठे 100 दिन से उपर हो चुके हैं। हमारे कृषि मंत्री जी कभी उनको चीनी बोलते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी बोलते हैं और जब उनकी मौत होती है तो मौत के उपर मखौल उड़ाने का काम किया जाता है। मैं समझती हूँ इससे ज्यादा शर्म की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती है। आज सरकार अपनी स्वयं की पीठ थपथपाते हुए कह रही है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकार ने किसानों के उपर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी चार्ज करने का काम किया, उनके सामने खाईयां खोदी गई, उनके रास्ते में कीलें बिछाई गई और यू.पी. के अंदर तो सैनेटाइजाइर तक किसानों के उपर छिड़कने का काम किया गया। लॉक डाउन के दौरान यमुनानगर और गुड़गांव में प्रवासी मजदूरों पर किस तरह के अत्याचार किए गए, वह भी सब जानते हैं। आज हमारे किसान भाई तीन काले कृषि काननों के विरूद्ध धरने पर बैठे हैं लेकिन सरकार उनकी कोई सुध–बुध नहीं ले रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड करती हूँ कि जिन किसानों की मौत हुई है, उनको शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1–2 करोड़ रूपया दिया आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा के

हालात किस कदर खराब हो चुके हैं लेकिन सरकार द्वारा इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब इन विषयों पर सदन में चर्चा करने की बात आती है तो मुझे कह दिया जाता है कि आप फलां विषय पर राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखिए। बताओ राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कितनी बात कही जा सकती है? इस दौरान केवल चुनिंदा प्वॉयंट्स पर पर ही तो बोला जा सकता है और उसके बाद समय की बाधा खड़ी हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के बात करती है लेकिन हमारे यहां प्रहलादगढ के साथ लगते 20 गांवों में ट्रांसमिशन लाइन्ज लगाई गई थी जिसके लिए यहां के एक–दो किल्ले के मालिक किसान भाईयों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी लेकिन इन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। इस सरकार ने किसानों का जो बुरा हाल किया है, इसका खामियाजा इनको आने वाले दिनों में भुगताना पड़ेगा। जहां तक नकली शराब की बात है, नकली शराब पीने से 50 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। इस विषय पर पहले एस.इ.टी. गठित की और मोटे–मोटे पोथे बनाकर रिपोर्ट तैयार की गई लेकिन उसका नतीजा क्या रहा, इसका किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद एस. आई.टी. का गठन कर दिया गया लेकिन नतीजा जीरो रहा और छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जो बड़ी मछलियां हैं वह किनारे होकर निकल गई हैं। आज सरकार 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के नीचे दबी हुई है और अकेला 9500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान केवल मात्र तस्करी और अवैध शराब के कारण हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है कि जहां एक तरफ सरकार कर्जे में डूबी हुई है वहीं दूसरी तरफ राजस्व का नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई जहां–जहां से की जा सकती है, वह भरपाई वहां से क्यों नहीं की जा रही है? उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार की यह खामियां सबको नजर आने लगी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री घोटाला का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात लॉकडाउन जुमला साबित हुई है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता का उल्लेख किया गया है। जो आज गलत साबित हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एम.एस.पी. पर फसल खरीद का जिक्र है। उपाध्यक्ष महोदय, सारा हरियाणा जानता है कि सूरजमुखी, बाजरा, सरसों आदि फसलों में किसानों की कितनी किरकरी हुई है। मेरे ख्याल से एम.एस.

पी. केवल इनके ही चुने हुए व्यक्तियों को मिली होगी, बाकियों को नहीं मिली है। सरकार द्वारा 'मेरा पानी मेरी विरासत' व 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' योजनाओं के संबंध में भी बड़ी–बड़ी बातें कही जाती है लेकिन इसमें भी किसानों को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः बहन किरण जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। समय के अभाव के कारण बाकी सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप वाइंड–अप कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में बड़ी–बड़ी बातें कही जाती है। सच्चाई यह है कि 34 हजार के करीब अध्यापकों के पद रिक्त पड़ हुए हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य के लगभग 750 पद रिक्त पड़े हुए हैं। संस्कृत मॉडल स्कूल की हकीकत भी सभी को पता है कि किस प्रकार चल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डिजिटल के नाम पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र बंट चुके हैं। गांव के बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार को इन सब बातों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रोजगार का भी जिक्र किया गया है। असली बात यह है कि यह केवल दिखावा मात्र ही है। प्रत्येक जिले से 10 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण देना, यह बात भी दिखावा मात्र है। हरियाणा डोमिसाईल की अवधि भी 5 साल कर दी गई है। सरकार ने एस.डी.ओ. की भर्ती में हरियाणा से बाहर के स्टेट के लड़कों को लगाकर, हमारे स्टेट के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन से पूछना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा में काबिलियत बच्चे नहीं है जो सरकार बाहर के बच्चों की नियुक्ति कर रही है। बेरोजगारी के नाम पर पूरे हरियाणा के अंदर त्राहि–त्राहि मची हुई है। हमारी प्रदेश के बच्चों की भर्ती नहीं होती बल्कि दूसरे प्रदेशों के बच्चों की भर्ती होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे प्रदेश की क्या हालत हो रही है। स्पोर्ट्स कोटे में बच्चे रोते–फिरते रहते हैं। यही हालत हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही वाइंड–अप कर रही हूँ।

श्री उपाध्यक्षः बहन किरण जी, आपने ही आपकी पार्टी के सदस्यों के नाम बोलने के लिये दिये हुए हैं, इसलिए उन्हें भी बोलने का समय देना है। प्लीज आप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, बहन किरण जी ने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की बात कही है। कृपया करके बहन किरण जी वह स्थान भी हमें बता दें जहां पर लाठी चार्ज हुआ है। (विघ्न) चोट के कारण अस्पताल का मैडिकल सर्टिफिकेट किसी के पास तो होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन किरण चौधरी को लाठी चार्ज कैसे होता है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। श्री कुलदीप बिश्नोई जो इस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उन पर और उनके समर्थकों पर लाठी चार्ज हुआ था और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों को तोड़ा गया था, इसको कहते हैं लाठी चार्ज। इसी तरह से श्री राकेश कम्बोज पर लाठी चार्ज हुआ था।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री किसानों की मौत पर मखौल बनाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि सरकार किसान की आमदनी दोगुनी कैसे करेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का किसान पर इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा कि वह उसकी मौत पर उसका मखौल उड़ाती है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या हमसे पूछे कि हम किसान की आमदनी दोगुनी कैसे करेंगे और हम उनको इसका जवाब देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे किसानों के विषय पर बात करनी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या बात है ? Deputy Speaker Sir, please protect me. This is not right.

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के विषय पर कुछ कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या मतलब हुआ ? Let me speak. (Interruptions) Let me speak. This is not right. Deputy Speaker Sir, please protect me. (Interruptions) What is this? (Interruptions) I am wrapping up.

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कैसे करूंगी ? (शोर एवं व्यवधान) मेरे बोलने के समय के 5 मिनट तो माननीय मंत्री जी ने ही ले लिये । उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे सम अप करने का समय दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आपने जो प्वॉयंट आउट किया था उसे माननीय मंत्री जी ने क्लीयर किया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के समय में सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं । आप मुझे बोलने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान) आज गैस सिलैंडर के दाम 800 रुपये प्रति सिलैंडर से ऊपर और पैट्रोल के दाम 100 रूपये प्रति लीटर से ऊपर है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं । सरकार इससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है । मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार जनता की जेब क्यों काट रही है ? सरकार को जनता पर लगाए गए टैक्स को कम करना चाहिए ताकि इस सरकार का अगले चुनाव में बुरा हाल न हो । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, अब आप बैठ जाइये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रैप अप कर रही हूं । I am wrapping up.

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, अब आपका समय पूरा हो गया है । अगर आप ऐसे ही बोलती रहेंगी तो अन्य सदस्यों को सदन में बोलने का समय कैसे मिलेगा ?

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे समय में अन्य माननीय सदस्यों को बोलने क्यों दे रहे हो ? (विघ्न) इन चीजों को सारी दुनिया देख रही है । Everyone is looking at the clock when I am speaking. They are saying that you see the clock, you see the time. I have seen that you have given more than 10-10 minutes to other Members. (Interruptions) मैं रैप अप कर रही हूं । अंत में मैं एक बात कहूंगी कि आर्थिक मन्दी, वित्तीय राजकोष में घाटा, सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज अच्छी बात नहीं है । आज प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं । बात चाहे किसानों की हो, बेरोजगारी की हो या कानून–व्यवस्था की हो या घोटाले की हो सरकार का सारा सिस्टम विफल हो चुका है । इस सरकार को अपना समर्थन देने वाले माननीय सदस्य श्री सोमबीर सांगवान ने भी 'किसान आन्दोलन' को सहमति दी है और कहा है कि सरकार किसानों के

साथ ठीक नहीं कर रही है । (विघ्न) मेरा कहना कि अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र में जाना है तो अभी भी वक्त है, मान जाओ । (शोर एवं व्यवधान) अंत में मुझे अधम गोंडवी जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं ।

तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है ।
तुम्हारी मेज़ चांदी की तुम्हारे जाम सोने के,
यहाँ जुम्मन के धर में आज भी फूटी रक़ाबी है ।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (एस.सी.) : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । सरकार ने कोविड–19 महामारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है । सरकार ने यह सराहनीय काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि वे ऐसा काम न करें जिसके कारण उनको अपने इलाके में जाने में दिक्कत आए।

श्री ईश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय माननीय सदस्य मेरी चिन्ता न करें।

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। ईश्वर जी, आप अपनी बात कन्टीन्यू रखें।

श्री ईश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कई चीजों के सुझाव भी साथ में दिये जाते हैं। सरकार ने कोविड–19 के दौरान बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। खासतौर से देहातों में जो प्रचार–प्रसार हुआ, यह उसी का परिणाम है कि आज हम इस महामारी से बचे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पहले फसलों की मंडियों में दुर्दशा होती थी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसान सुबह अपनी जीरी की फसल लेकर जाते हैं और दो घंटे में उसकी फसल बिक जाती है। उनको अपनी फसल का पूरा भाव मिल रहा है। किसी भी किसान को अपनी फसलों को बेचने के लिए रात के समय में मंडियों में रुकना नहीं पड़ा। इस बात को विपक्ष के माननीय सदस्य भी जानते हैं। यह बहुत सराहनीय काम हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, सरकार ने प्राईवेट सैक्टर की हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया है। क्या विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात को भी झूठ मानते हैं ?

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसके तहत किसी को नौकरी नहीं दी गयी है और इसमें एस.सी./बी.सी. कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी नहीं किया गया है।

श्री ईश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि मैं इसी बात पर आ रहा हूं। सरकार ने यह प्रॉविजन कर दिया है कि प्राईवेट सैक्टर में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी दी जाएंगी। इससे प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सैक्टर में नौकरियां मिल जाएंगी। सरकार ने यह बहुत अच्छी पहल की है। मेरा सुझाव है कि प्राईवेट सैक्टर में एस.सी. कैटेगरी के बच्चों के लिए रिवर्जेशन पॉलिसी लागू की जाए। सरकार ने यह अच्छा और सराहनीय काम किया है। इसमें यह प्रॉविजन भी अटैच किया जाए कि प्राइवेट सैक्टर में रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को नौकरी मिलें। इस बेरोजगारी की समस्या का इसके सिवा कोई दूसरा समाधान नहीं है। इसका दूसरा समाधान नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं कि सभी को सरकारी नौकरी मिल सके। इस बेरोजगारी को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि प्राईवेट सैक्टर की नौकरियों में बच्चों को भर्ती किया जाए और इसके लिए प्रदेश में बड़े–बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज और मिलों में प्रावधान किया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राईवेट सैक्टर के जितने भी उपक्रम हैं, वे हरियाणा के 75 प्रतिशत युवाओं को सर्विस देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ–साथ यह भी प्रावधान किया जाए कि इन नौकरियों में रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू हो। तीसरी बात यह है कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, यह बहुत अच्छा काम किया है, परन्तु इसको लागू करने में अनियमितताएं आ गयी हैं। इसमें जितना राशन आता था, वह गरीबों परिवारों को दिया जाता है, परन्तु इसमें खासतौर से डिपो होल्डर राशन देने के लिए गरीबों को ब्लैकमेल करते हैं। यह सत्य बात है और इसमें कोई दोराय नहीं हैं। वे गरीब आदमियों को लोभ– लालच देकर इस काम को अंजाम देते हैं। इसको लागू करने के पीछे यही कारण था कि गरीब परिवारों को अपलिफ्ट किया जाए। यह अच्छी स्कीम बनायी गयी थी। इससे उनको अपलिफ्ट होने में मद्द मिलेगी और इसके अलावा वे अलग से मजदूरी/दिहाड़ी करेंगे, परन्तु इसके विपरित काम हुआ हुआ है। इसमें मेरी एक सलाह है कि सरकार एक विशेष जांच कमेटी बनायी जाए। वे इसकी जांच करें कि जितने राशन के डिपो हैं उनमें जो चीजें आती हैं। उनका मिसयूज न हो और उनका संरक्षण हो

सके। डिप्टी स्पीकर सर, आपने कहा कि समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात प्वॉयंटवाईज रखूंगा। गवर्नर साहब के अभिभाषण में डिटेल में यह बात दर्शायी गयी है कि सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से बहुत सराहनीय काम किये हैं। सरकार ने शिक्षा देने के लिए 110 कॉलेजिज खोले हैं और ये उन एरियाज में खोले हैं, जहां पर 20 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज नहीं था। खासतौर से देहातों में विशेषकर लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जाना पड़ता था और वे इस कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर में बैठ जाती थी। यानी बारहवीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे लड़कियां आगे की पढ़ाई छोड़ देती थी। सरकार ने 110 कॉलेजिज खोलकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। पहले 20 किलोमीटर के एरिया में जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहे जाते थे, वे इससे आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आप अपनी बात को कन्कलूड कीजिए।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात रखनी शुरू ही की थी और इस महान सदन में मैंने अब तक दो प्वॉयंट्स पर ही अपनी बात रखी है और मुझे बोलते हुए भी 2 मिनट हुए हैं। मेरा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अलावा एक सुझाव भी है और वह यह है कि जैसे हमारे यहां के स्कूल्ज में ड्रॉप–ऑउट रेट बढ़ता जा रहा है। इसके मायने ये है कि जिन बच्चों के स्कूल में मार्च–अप्रैल के महीने में एडमिशन होते हैं और इस एडमिशन के अंदर भट्ठे वालों के बच्चे और दुकानदारों के बच्चों का नाम हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करके उसकी हाजिरी लगा दी जाती है ताकि संबंधित स्कूलों में टीचर्ज की पोस्ट खत्म न हों। आखिर में इसका नतीजा यह होता है कि जून और जुलाई के महीने में स्कूल्ज में ड्रॉप ऑउट रेट बढ़ जाता है। जिन बच्चों का मार्च–अप्रैल के महीने में एडमिशन हुआ था, उनका नाम उस रजिस्टर में से काट दिया जाता है। हमें यह बात बहुत ही छोटी सी लगती है परन्तु यह बात बहुत बड़ी और गंभीर है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक निकल रहे हैं। इसका यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चों की सीटों की संख्या घटते–घटते बिल्कुल ही घट गई है। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सीटें न के बराबर रह गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई प्राइमरी स्कूलों की हालत तो यह हो गई है कि प्राइमरी स्कूल भी तोड़ दिये गये हैं। मिडिल से प्राइमरी बनाया जा रहा है और प्राइमरी से तोड़कर देहात के दूसरे स्कूलों में उन बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है और यह हमारे प्रदेश के लिए अति गंभीर

समस्या बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि स्कूल्ज में ड्रॉप–ऑउट रेट कम करने का काम करें क्योंकि यह काफी बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ प्रावधान करने का भी काम किया जा सकता है। जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा तब तक धीरे–धीरे सरकारी स्कूल बंद होने शुरू हो जायेंगे और ऐसा भी नहीं है कि सरकारी स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसके अलावा सरकार ने एक स्टाइपैंड पॉलिसी भी बनाई हुई है। मैं इस महान सदन में अकेले अनुसूचित जाति के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें क्या–क्या बातें हैं जैसे हमारे प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बैंकों में पर्सनल खाते खुलवा दिये गये और सरकार की तरफ से जितना भी फंड रिलीज किया गया, वह सारा का सारा फंड कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के खातों में चला जाता है और जब वे कॉलेज से पढ़कर बाहर निकलते हैं तो अपने खातों में से पैसे निकाल लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वह पैसा कॉलेज के खाते में नहीं जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उस पैसे का मिसयूज करते हैं। सरकार ने पढ़ने वाले बच्चों को पैसा तो इसलिए दिया था कि उनको कॉलेज में अपनी जेब से फीस न भरनी पड़े। कॉलेज में उस बच्चे ने एक साल तक अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और उसने उन पैसों का दुरुपयोग भी कर दिया। इस संबंध में मेरा यही कहना है कि उस सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था को तो एक पैसा भी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज अब आप बैठ जायें।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा और समय दीजिए ताकि मैं अपनी पूरी बात रख सकूं। मैं इस महान सदन में आउट–सोर्सिंग के बारे में कहना चाहता हूं और यह हमारे प्रदेश के लिए गंभीर समस्या है। आउट–सोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो भर्तियां की जाती हैं और ठेकेदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक प्रदेश के युवाओं को रोजगार देता है। मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने ''हरियाणा एम्पलॉयमैंट एक्सचेंज'' के दफ्तर खोल रखे हैं, उनके क्या मायने रह गये? उनके मायने तो सारे के सारे खत्म कर दिये गये? ऐसे दफ्तर खुले हुए थे वे सब के सब बंद हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना

चाहता हूं कि जो ''हरियाणा एम्पलॉयमैंट एक्सचेंज'' के दफ्तर बना रखे हैं और उनमें जो अधिकारी/कर्मचारी काम करते हैं। इन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम तो ठेकदारों ने ले लिये हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ऐसे जो दफ्तर खुले हुए थे, वे सब के सब बंद हो गये हैं। यह पॉलिसी हमारे प्रदेश के बेरोजगार बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। इस पॉलिसी के तहत जिस व्यक्ति को नौकरी मिलती है उसको सरकार 5 साल तक पक्का नहीं करती है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने आउट–सोर्सिंग पॉलिसी को लागू करके हमारी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, उसको भी तहस–नहस करने का काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप प्लीज बैठ जायें।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे एक मिनट के लिए बोलने का मौका और दीजिए। मैं इस महान सदन में प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई दो बड़ी गंभीर समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी इस बात को लाइट मोड में न लें। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वर्ष 2008 में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सरकार की तरफ से 100–100 गज के प्लॉट दिये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज उस पॉलिसी को बने हुए लगभग 13 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उस पॉलिसी को हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से इम्पलीमैंट नहीं किया गया है। इस पॉलिसी के मुताबिक अभी तक एक प्लॉट भी किसी गरीब आदमी को नहीं मिला है और यह बात कांग्रेस पार्टी की सरकार पर भी लागू होती है और हमारी सरकार पर भी लागू होती है। मैं चाहता हूं कि उस पॉलिसी को लागू करने का काम किया जाये (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाये। माननीय सदस्य की बात पूरी होने दीजिए। (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं आंकड़ों के मुताबिक ही इस महान सदन में चर्चा कर रहा हूं। (विघ्न) अभी तक सिर्फ 54 परसैंट प्लॉट ही मिले हैं और 46 परसैंट दबंग

आदमियों ने अपने कब्जे वापिस ले लिये हैं या उन गरीब व्यक्तियों को पोजैशन ही नहीं मिला है। इस प्रकार से उसके भी मायने पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि वह 50 परसैंट अधूरा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि इससे बड़ी गंभीर समस्या और क्या होगी? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन 13 सालों में प्रदेश की आबादी नहीं बढ़ी है? आज हम जब प्रदेश के गांवों में जाते हैं तो लोगों द्वारा कहा जाता है कि हमें प्लॉट दिलवाया जाये। आज प्रदेश के गांवों में गरीबों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि उसको लिखकर बोलकर ब्यान नहीं किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यही मांग है कि सरकार को इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए और गरीब व्यक्तियों को 100–100 गज के प्लॉट्स देने के लिए दोबारा नीति बनानी चाहिए। यदि किसी पंचायत के पास जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन एक्वायर करने का काम किया जाये जैसे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा और एच.एस.वी.पी. हरियाणा जमीन ऐक्वायर करता है उसी तरह से जमीन ऐक्वायर करके गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 100–100 गज के प्लॉट देने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 05.03.2021 को इस महान सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा था और आज मैं उनके अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में जो बात कही, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। मैंने पिछले सत्र के दौरान एक कनैक्टिविटी की बात कही थी और आज भी इस सत्र में दोबारा इस बारे में कहना चाहता हूं कि इस सरकार में हरियाणा प्रदेश में कनैक्टिविटी का जितना विस्तार हुआ है, शायद किसी और सरकारों के समय में ऐसा विस्तार हुआ हो, चाहे वह प्रदेश का कोई भी शहर हो, चाहे कोई इन्स्टीच्यूशन हो, चाहे कोई भी जिला आदि हो। अगर किसी स्टेट का डिवैलपमैंट होता है तो कनैक्टिविटी के आधार पर ही होता है, किसी शहर की, किसी जिले की और किसी प्रांत की आपस में कनैक्टिविटी ठीक नहीं होगी तो उनका डिवैलपमैंट अच्छा नहीं होगा। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। हरियाणा स्टेट वर्ष 1966 में बना था तब से लेकर वर्ष 2014 तक प्रदेश की सड़कों

की जो हालत थी और वर्ष 2014 से लेकर आज तक जो सड़कों की हालत है, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि फर्क तो अपने आप नजर आता है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जायें। जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा तो आप अपनी बात रख लेना। (विघ्न)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब पहले हिसार से दिल्ली जाता था तो मुझे दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता था और आज मैं मात्र सवा दो घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं। मैं इस महान सदन में रोहतक बाई पास, महम बाई पास और बहादुरगढ़ बाई पास के बारे में बताना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, माननीय सदस्य की बात ठीक है इस बात में कोई झूठ नहीं है। (विघ्न) प्लीज आप बैठ जायें।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं हिसार से डबवाली जाता हूं। (विघ्न) अब हिसार से चण्डीगढ़ पहुंचने में मुझे 3 घंटे का समय लगता है जबकि पहले 5 घंटे लगते थे। (विघ्न) छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद होते हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसको छलनी और छाछ बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जायें। आप सदन की कार्यवाही को बीच में डिस्टर्ब न करें। (विघ्न)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि ''नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली''। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं रेल की कनैक्टिविटी की बात करूंगा। पहले दिल्ली से हिसार हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी। जब वह ट्रेन रेवाड़ी जाती थी तो रेवाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती थी। उसके बाद उस ट्रेन का इंजन कटता था, उसके बाद फिर इंजन पीछे लगता था और फिर वह ट्रेन हिसार पहुंचती थी। इस प्रकार उस ट्रेन को हिसार पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि उसके बाद वह गाड़ी भिवानी जाती है और भिवानी स्टेशन पर खड़ी होती है। भिवानी में ट्रेन का इंजन लगाया जाता है फिर वह ट्रेन हिसार पहुंचती है। यह बात मेरी समझ में नहीं

आई कि यह किस प्रकार की कनैक्टिविटी हुई। हमारी सरकार द्वारा रोहतक को वाया महम हांसी को जोड़ने का काम प्रगति से चलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के कार्य को कनैक्टिविटी का नाम दिया जाता है। (विघ्न) अभी तो मैं इस महान सदन में केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानूनों के बारे में अपनी बात रखूंगा इसलिए कांग्रेस पार्टी मेरी यह बात ध्यान से सुने। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के 74 साल बीतने के बाद और हरियाणा बनने के 50 साल बाद भी प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा इस महान सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने महम से हांसी और हिसार की कनेक्टिविटी की बात की है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि किसकी सरकार में इसके लिए जमीन एक्वायर हुई थी और जमीन की एक्विजीशन कब हुई थी? (विघ्न)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने 50 साल में हरियाणा प्रदेश को जोड़ने के लिए किसी एयरपोर्ट का निर्माण किया है? मुझे कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस बारे में बतायें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हिसार एयरपोर्ट के लिए एयरोड्रम लाइसैंस जारी किया है और हिसार से तीन फ्लाइट भी शुरू करवाने का काम किया। मैं उस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि हिसार से चण्डीगढ़ के लिए, देहरादून के लिए और धर्मशाला के लिए फ्लाइट चल चुकी हैं और आने वाले समय में हिसार से अमृतसर के लिए और जयपुर के लिए भी फ्लाइट चलाने का काम किया जायेगा। अभी कुछ समय पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 10 हजार फीट के रनवे का शिलान्यास किया है, यह काम किसने किया, यह काम हमारी सरकार ने किया। यह काम कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया क्योंकि इनकी काम करने की सोच ही नहीं थी। आज मैं नौकरियों की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार ने जितनी नौकरियां पिछले 50 साल में भी नहीं दी उतनी नौकरियां हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में बिना खर्ची–पर्ची के दी हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नौकरियां बिना सिफारिश और बिना पैसे के दी हैं। यह बात सर्वविदित है कि हमारे एच.सी. एस. की, हमारे मास्टरों की या पुलिस की सभी की नौकरियां बिना सिफारिश और बिना पैसे के दी हैं। कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। 20 किलोमीटर के दायरे

में महिला कॉलेज खोलने का काम किसने किया, हर जिले में महिला थाने खोलने का काम किसने किया, महिलाओं को निगम और पंचायत के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण किसने दिया, यह सभी काम भी हमारी सरकार ने ही किये हैं। पहली बार इस हाउस में हमारी महिला बहनों को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाने का काम किसने किया, यह काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। इसी प्रकार से ट्रांसफर पॉलिसी की अगर बात की जाये तो एक बटन से 40 हजार ट्रांसफर करने का काम किसने किया, यह काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। आजादी से 2014 तक कांग्रेस सरकार में क्या–क्या हुआ अब मैं उसके बारे में बताता हूं। इनकी सरकार में घोटाले होते थे मैं उनको गिनवाता हूं। 2 जी. घोटाला, 3 जी. घोटाला, 4 जी. घोटाला, कॉमनवैल्थ गेम्स घोटाला, पानी में पनडुब्बी घोटाला और हवा में हेलीकॉप्टर घोटाला, चारे का घोटाला तथा कोयला घोटाला भी हुआ था। वर्ष 1962 में चीन की सीमा पर 50 लाख हैक्टेयर भूमि चीन को युद्ध में किसने दी, वह कांग्रेस के शासनकाल में ही दी गई थी। संविधान की धारा 370 को हटने से यू.एन. ओ. में किसने अटकाया, यह भी कांग्रेस शासनकाल में हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं क्या यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हिस्सा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, जब आपकी बारी आये तो आप इस बारे में बोल सकती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के साथी लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं लेकिन 1984 में सिख भाइयों पर आक्रमण किसने किया, कांग्रेस ने ही करवाया था उसके लिए इनको शर्म आनी चाहिए। कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी किसके समय में होती थी, कांग्रेस के समय में ही होती थी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बहुत गलत काम किये हैं यह इनके लिए शर्म की बात है। दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चिरंजीव राव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी यह भी बता दें कि किसान आंदोलन में किसानों की हत्या कौन करवा रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, गलवान घाटी में 450 किलोमीटर लम्बी सड़क किसने बनाई, उड़ी हमले का बदला पाकिस्तान से किसने लिया, यह काम भी हमारी सरकार के समय में ही हुआ है। धारा 370 तोड़ने का काम किसने किया?

हमारी मुस्लिम बहनों के लिए तीन तलाक हटाने का काम किसने किया? गरीबों के लिए जन–धन योजना लाई गई। वर्ष 2014 तक ढाई करोड़ खाते थे और अब 34 करोड़ खाते हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) 500 वर्षों से चल रहे राम मंदिर का इशू किसने सोलव किया? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उनकी सारी बात सच्ची है। रिकॉर्ड से कैसे निकाल देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत हो गया।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो काला कानून कह रहे हैं जिस तरह से आदमी के लिए भगवद् गीता और रामायण हैं उसी तरह से मोदी जी ने हमारे जो भगवान स्वरूपी किसान हैं उनके लिए ये तीन सुनहरी कानून बनाए हैं। उनको ये काला कानून कहते हैं। आपकी आंखें काली हैं, आपका मन काला है। आपका दिल काला है। जो भोले–भाले किसानों को भड़का रहे हो। जिन्होंने आजादी से लेकर आज तक किसानों का शोषण किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका समय हो गया है अब आप वाइंडअप करें।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री जी 6 साल तक बैठे रहे कुछ नहीं बोले।(शोर एवं व्यवधान) आप लोगों ने 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर चलवाकर ऐसा प्रदर्शन किया। हमारे पुलिस के भाईयों के ऊपर ट्रैक्टर चलवाया। पूरे देश में तलवारें, भाले चले। क्या ये एक–एक, दो–दो रुपये के चैक देने वाले किसान हितैषी हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें कि ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र ने वोट की चोट से इनको बाहर बिठाया है। वह अब इनको दोबारा नहीं लाने वाले हैं। आपके पास ये 30 लोग ही आएंगे और कल को ये 30 लोग ही पूरे करने आपको मुश्किल हो जाएंगे। यह मेरा वायदा है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर साहब, धन्यवाद।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम–अप कर रहा हूं। मैं अपने हिसार हल्के की दो बातों के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डी.सी.एम. चौक से ऐयरपोर्ट चौक तक हमने जो 100 एकड़ जमीन आईडैंटिफाई की है। उसमें वहां 65

एकड़ पर अस्पताल बनाया जाए और 35 एकड़ में बस स्टैंड बनाया जाए। इन्हीं बातों के साथ समय का अभाव होने के कारण मैं बहुत सी बातें नहीं कर पाया। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि आज ये कौन से डॉक्टर से मिले थे। इसी तरह से एक को पेट में दर्द हो गया था। वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप कहां गये थे। क्या खा लिया। उसने कहा कुछ भी नहीं खिचड़ी खाई थी। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा बोल लिया तो वह कहने लगा कि बोलने ही नहीं दिया। डॉक्टर कहने लगे कि तेरे पेट में वह भाषण अटक रहा है उसको एक बार गा ले।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जब हर सरकार का बजट शुरू होता है तो राज्यपाल महोदय, अण्डर रूल आर्टिकल 175 (i) ऑफ दि कॉन्स्टीच्यूशन अपना अभिभाषण सदन में पढ़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी भी सरकार का विजनरी डॉक्यूमैंट होता है। यह प्रदेश की दशा और दिशा सरकार की नीयत और कारगुजारियां दर्शाने का काम करता है और जो काम भविष्य में किए जाने होते हैं उन सबकी जानकारी सदन के माध्यम से देश और प्रदेश के वासियों तक पहुंचती है। जहां तक दशा और दिशा की बात है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से साफ झलकता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार कहती है कि 15 लाख रुपये लोगों के खाते में आयेंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जायेंगे, सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम किया जायेगा, नोट बंदी करने से काला धन वापिस आयेगा तथा आतंकवाद खत्म होगा, इस तरह की तमाम प्रकार की कथनी सरकार द्वारा कही गई है। राज्यपाल अभिभाषण में सबसे पहला विषय कृषि एवं किसान कल्याण का है जिसके तहत हरियाणा राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाये गए निर्णायक कदमों के बारे में बताते हुए एम.एस.पी. की बात की गई और माइनर इरिगेशन पर सब्सिडी देने की बात की गई और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के विषय पर बात की गई। सरकार के मंत्री या सरकार के विधायक जब फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का काम किया जायेगा तो इस परिपेक्ष्य में मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार जो यह तीन कृषि कानून

लेकर आई है, क्या इनकी वजह से किसानों की आय दोगुनी होगी या जो मैंने अभी राज्यपाल अभिभाषण में वर्णित तीन कारण बतायें हैं उनकी वजह से होगी। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब अपना रिप्लाई दें तो इस बात को जरूर स्पष्ट कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों का विषय, बहुत गम्भीर विषय बन चुका है। पूरा प्रदेश और देश आज बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसान, मेहनतकश कमेरा वर्ग तथा गरीबी की गुरबत में जीने वाले लोग इस सदन की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि इस सदन में उनके बारे में क्या चर्चा हो रही है? आज किसान आंदोलन में दो फैक्टर आ गए हैं। एक फैक्टर यह है कि आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और दूसरा फैक्टर यह है कि कि आज किसान अपने बच्चे के समान समझने वाली फसल को उजाड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोहाना के विधायक श्री देवेन्द्र बबली की प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने बड़े बेबाकी से इस सदन में कहा कि सरकार के कामों की वजह से उनको गांव में घुसने से रोका जा रहा है, उनकी न्योता–निधार पर रोक लगा दी गई है, उनके खिलाफ बोर्ड लगा दिए गए हैं और उन्हें काले झंडे दिखाने का काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग सरकार में हिस्सेदार की भूमिका में हैं और बावजूद इसके इनके साथ प्रदेश के लोगों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इस बारे में मैं बात करूंगा कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही मई के महीने में कृषि कानूनों से संबंधित तीन कृषि कानून लाए गए, उसके फोरन बाद पंजाब में इनका विरोध हुआ जब किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी तो पंजाब के लोगों ने फैसला किया कि इस आंदोलन को दिल्ली में चलाया जाये। हमारी पार्टी के उस टाइम के एक्स–प्रेजीडेंट राहुल गांधी ने भी ट्रैक्टर यात्रा की थी लेकिन सरकार ने तानाशही दिखाई और उनको बार्डर पर बैठे किसान भाइयों के पास एक घंटा इंतजार करने के बावजूद भी नहीं जाने दिया गया। जब किसान आगे बढ़े तो उनके सामने हरियाणा में खाईयां खोदी गई, बेरिकेड लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोडे गए और नवम्बर महीने के सर्दी के सीजन में वाटर कैनन से उन पर पानी की बौछारें करते हुए लाठी चार्ज तक किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसान भाई नई दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर इकट्ठा होना चाहते थे। लेकिन उन्हें दिल्ली से बाहर टीकरी , गाजियाबाद, सिंधु आदि बॉर्डर्ज पर ही रोक दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उनके लिये

खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी न जाने किन–किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश का किसान हमारा अन्नदाता होता है और अन्नदाता भगवान होता है। (विघ्न) हरियाणा सरकार के मंत्री कहते हैं कि किसान कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर आंदोलन कर रहे हैं। दिनांक 26 जनवरी, 2021 को लगभग 2 लाख टैक्ट्ररों के साथ 20 लाख किसान भाई राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए दिल्ली के बाहर बॉर्डर्ज पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार की मीडिया उन्हें न दिखाते हुए केवल एक आदमी जो किसान भी नहीं था उसे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए दिखाया गया। जब इस घटना का किसान भाइयों को पता चला तो पूरा किसान आंदोलन डिमॉरलाइज हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हमारा किसान भाई कैसे कर सकता है। दिनांक 26 जनवरी, 2021 की घटना के बाद किसान डिमॉरलाईज हुए और किसान आंदोलन पिछड़ने लगा, सरकार ने अपने ही लोगों को किसान बताकर उनके ऊपर जानबूझकर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी व गिरफ्तारी करवाई। इस तरह की घटना वहां पर दिखाई गई। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर वे लोग हमारी ही पार्टी के लोग थे तो उन्हें छुड़वाने के लिये कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों गये थे। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होता है। लाल किला श्री नरेन्द्र मोदी जी का नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी का है। लाल किला देश का है। अगर उन लोगों ने लाल किले के मान बिन्दुओं का अपमान किया है तो क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने उसकी आलोचना की थी? (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उनकी आलोचना करती आ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 जनवरी, 2021 की घटना की कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की थी। इसकी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा व राज्य सभा में भी की थी। आज फिर हम विधान सभा में भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, जिन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का काम किया था। लाल किले का सम्मान करना हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, इसका अपमान कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब सही कह रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए लेकिन उन्हें छुड़वाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों गये? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, हम उस घटना की पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। उसी घटना से दुखी होकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य श्री राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले थे। उपाध्यक्ष महोदय, ये श्री राकेश टिकैत के आंखों के आंसू नहीं थे बल्कि हिन्दुस्तान के लाखों किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग के आंसू थे। इस तरह से हिन्दुस्तान के लाखों लोगों के आंसू अपमान के प्रतीक थे। उसके बाद किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो गया और धीर–धीरे शांतिपूर्वक तरीके से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। किसान आंदोलन आगे बढ़ने लगा तो सरकार ने उनके मार्ग में तरह–तरह की बाधाएं उत्पन्न कर दी। उनके मार्ग में कांटेदार कीले लगा दी, सीमेंट व कंकरीट की दीवारें खड़ी कर दी और बड़े–बड़े बैरिकेड्स लगा दिये। जहां पर हमारे किसान भाई शांतिपूर्वक धरना स्थलों पर बैठे हुए थे, वहां से बिजली और पानी के कनैक्शन कटवा दिये और वहां पर बने शौचालय उखाड़ दिये। उन किसान भाइयों के खिलाफ देशद्रोह के मुकद्दमे दर्ज कर दिये गये, जो पहले अंग्रेजों के शासन काल में भी दर्ज नहीं हुआ करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश को पता है कि किसानों के साथ किस प्रकार के अमानवीय कृत्य किये जा रहे हैं। किसानों के बारे में यह भी कहा गया है कि ये किसान नहीं है बल्कि ये आंदोलनजीवी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह फासिज्म (फासिस्टवाद) की भाषा है । जर्मनी में हिटलर ने यहूदी कैंप में बंद यहूदियों के बारे में कहा था कि ये कोक्रोचिज हैं और उन्होंने उनको गैस के चैम्बर में बंद करके मरवा दिया था । आज भारत में लोगों को पैरासाइट्स कहा जा रहा है । क्या आज हिन्दुस्तान भी जर्मनी के रास्ते पर जा रहा है ? क्या हिन्दुस्तान भी फासिज्म (फासिस्टवाद) की ओर जा रहा है ? माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से आंदोलन करने वालों के लिए 'आन्दोलनजीवी' शब्द का प्रयोग किया गया । (विघ्न) मैं इस लाइन पर आना चाहता हूं । आज किसान मजबूर क्यों है ? किसान अपनी फसल उजाड़ने के लिए मजबूर क्यों है ? सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्य किसानों से निवेदन करते हैं कि वे आत्महत्या न करें, वे अपने खेती को न उजाड़ें । प्रदेश के कृषि मंत्री जी का बयान आया कि किसान मर गये तो क्या हुआ वे तो अपने घरों में भी मरने ही थे । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो चुका है । अब आप बैठ जाइये। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलन में उन किसानों की बहन–बेटी भी वहां पर बैठी हुई थी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आपको बोलते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और आपके बोलने का समय समाप्त हो चुका है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे वाइंड अप करने के लिए समय दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप वाइंड अप कीजिए। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान रो रहा है। मैं सदन के माध्यम से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि एक लाइन का प्रस्ताव इस सदन से चला जाए । जब तन्त्र जनता के सामने झुकता है तो तन्त्र मजबूत होता है तब तन्त्र कमजोर नहीं होता है । लोकराज लोकलाज से चलता है । इससे प्रधानमंत्री का कद छोटा नहीं होगा बल्कि उनका कद और बड़ा हो जाएगा । इससे वे युगपुरूष कहलाएंगे । अतः उनको इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए और खुशी–खुशी किसानों को दिए हुए नोटिस और उन पर किये हुए केस वापस लिये जाने चाहिए तथा जो किसान जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आपके बोलने का समय समाप्त हो चुका है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश हमारी बात सुनना चाहता है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब, आपको बोलते हुए 13 मिनट्स हो चुके हैं। अतः अब आप बैठिये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक गीत के माध्यम से कहना चाहूंगा –

रहने दे अभी थोड़ा–सा भरम
ए जान–ए–वफा ये जुल्म ना कर
गैरो पे करम अपनो पे सितम
हम चाहने वाले हैं तेरे
यूं हमको जलाना ठीक नहीं
महफिल में तमाशा बन जाए
इस दर्जा सताना ठीक नहीं
इस दर्जा सताना ठीक नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है सरकार को उपर्युक्त सभी काम करने चाहिएं नहीं तो इस सरकार का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा । हम संविधान के लिए और जनता के हक के लिए लड़ेंगे । किसान के लिए अगर हमें गोली भी खानी पड़ी तो हम गोली भी खाएंगे । मैं कहना चाहूंगा कि 'किसान एकता जिन्दाबाद', 'जय जवान, जय किसान' ।

श्री लीला राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर यू.पी. का एक किसान नेता राकेश टिकैत बैठा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जोगी राम सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । राज्यपाल महोदय ने हमें सरकार के कार्यों की एक पूरी किताब थमाई है । अधिकतर माननीय सदस्य इस पर बहुत कम बोलते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सैक्टर की नौकरियों में 75 परसैंट आरक्षण दिया है । इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय श्री दुष्यन्त चौटाला का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं । हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के हक में रोजगार देने के लिए प्राईवेट सैक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियां देने का प्रावधान किया है। यह प्रदेश के युवाओं के हित में है। मैं इसके लिए डिप्टी सी.एम. साहब का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं क्योंकि इसमें इनका विशेष योगदान है । डिप्टी स्पीकर सर, आज इस देश और प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वह किसान आंदोलन का मुद्दा है। किसान आंदोलन का मुद्दा पूरे देश के अन्दर है। यह मुद्दा हरियाणा प्रदेश की सरकार की वजह से नहीं है लेकिन इसका प्रभाव हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इस देश के किसी भी कोने में फसलों का इतना एम.एस.पी. नहीं दिया जा रहा है जितना हमारे यहां पर दिया जा रहा है। कहीं पर मक्का का समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है और कहीं पर बाजरा का समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य सबसे अधिक दिया जा रहा है तो फिर क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश में यह आंदोलन हो रहा है ? मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि इस देश का किसान ही आंदोलनरत नहीं है। इस देश का हर नागरिक चिंतित और विचलित है कि इस देश के साथ क्या होने जा रहा है ? किसान और किसानी के साथ क्या होने जा रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हमें जनता

चण्डीगढ़ और दिल्ली में सिर्फ सरकार बनाने के लिए या विपक्ष में बैठने के लिए नहीं चुनती है। सरकार तो जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होते हैं उसकी बन जाती है। जनता हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुनकर भेजती है और वह हमें यहां अपना वकील बनाकर भेजती है, परन्तु हम उनको भूल जाते हैं। कोई माननीय विधायक अपने आपको सरकार का हिस्सा मान लेता है और कोई अपने आपको विपक्ष का हिस्सा मान लेता है। सही और सच्ची बात कहने की कोई कोशिश नहीं करता। सरकार में बैठे हुए माननीय विधायक सरकार की बड़ाई करते हैं और विपक्ष में बैठे हुए माननीय विधायक सरकार ने चाहे कितना ही अच्छा काम किया हो, परन्तु उसकी बड़ाई करने की कोशिश नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हो सकता है केन्द्र सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर कानून बनाती है, और वह पूरे देश की चिन्ता करती है। भारत सरकार की जिम्मेवारी पूरे देश की है। हरियाणा सरकार पूरे देश की चिन्ता कर सकती है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी सिर्फ हरियाणा प्रदेश की है। मैं हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज सबसे ज्यादा आंदोलित है, सबसे ज्यादा विचलित है और सबसे ज्यादा भययुक्त है। हम जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, इसमें हमारा फर्ज बनता है कि इस बात पर विचार किया जाए। जब हरियाणा सरकार बाजरा, मक्का, जौ और कपास के लिए एम.एस.पी. का कानून बना सकती है तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं और जीरी पर एम.एस.पी. क्यों नहीं बना सकती ? केन्द्र सरकार अपना कानून बनाए। मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि एम.एस.पी. के लिए हरियाणा सरकार अपना खुद का कानून बनाए। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए यह कानून लाने के लिए आपको कौन रोकता है ? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यदि सरकार यह कानून ले आए तो इस प्रदेश का किसान अपने आप ढोल बजाता हुआ अपने–अपने घरों को आनं का काम करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा तकलीफ में भी हूं क्योंकि परसों एक किसान स्वर्गीय श्री राजबीर जो 47 साल का था, वह मेरे गांव का नागरिक था। किसान आंदोलन में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मुझे इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि आज गांव के अंदर किसानों की क्या हालत है? मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि इस महान सदन में नो कॉफीडेंस प्रस्ताव लाने का कोई

औचित्य नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नो कॉंफीडेंस प्रस्ताव लाने से क्या हो जायेगा? क्या ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जायेगी? मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूंगा कि इस महान सदन में नो कॉंफीडेंस प्रस्ताव के स्थान पर हरियाणा प्रदेश के किसानों को घर भेजने वाला कानून क्यों नहीं लेकर आते हो? कांग्रेस पार्टी इस कानून को क्यों नहीं लेकर आ रही है? उस कानून के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से मक्का, गेहूं और गन्ना के भाव में और सरसों की फसल पर एम.एस.पी. दी जाती है उसी तरह से हरियाणा सरकार हमारे प्रदेश के किसानों को लिखित में आश्वासन दे और उन किसानों को किसी प्रकार का कोई भय न हो। उन किसानों को यह बात महसूस हो जाये कि हरियाणा प्रदेश में उनकी हर फसल एम.एस.पी. पर खरीदी जायेगी। मेरा यह भी मानना है कि तब हरियाणा प्रदेश के किसान सरकार की जय जयकार के नारे भी लगाने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के साथ लगते हुए और भी राज्य हैं। हरियाणा सरकार उन राज्यों का अनुसरण करे क्योंकि वहां के राज्यों में हरियाणा प्रदेश जैसे हालात नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में हो, उनको किसान अपने घरों में आने से रोकता हो। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पंजाब प्रांत के बारे में तो मान लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां के किसान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को किसी भी कार्यक्रम या गांव में आने से नहीं रोकते हैं। मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार यह न सोचे। इसमें सरकार का फर्ज बनता है क्योंकि सरकार के विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं और सरकार के पदाधिकारी भी हैं। वे प्रदेश के गांवों में क्या मुंह लेकर जायें? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि एक ऐसा कानून बनाया जाये जिससे सत्ता पक्ष के सदस्य प्रदेश के गांवों में भय मुक्त होकर अपने भाई बंधुओं से मिल सके क्योंकि कोई भी भाई बंधु किसी को भी गलत नहीं बोलता है, यह हकीकत है। यह तो कबूतर वाली बात हो गई जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेती है कि बिल्ली इसे नहीं देख पायेगी। चाहे आंखें मूंदी जायें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस महान सदन में यह मांग करता हूं कि एम.एस.पी. पर केन्द्र सरकार चाहे जो भी कानून बना लें लेकिन हरियाणा सरकार को अपना कृषि कानून बनाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के से संबंधित विकास के मुद्दों पर भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण में नहरी और पीने के पानी के बचाव करने के बारे में कहा गया है। हरियाणा प्रदेश में नहरी पानी के लिए पक्के नालों का कार्यकाल 20 साल का है। इन नालों के द्वारा ही खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी दिया जाता है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अपने घर की टंकी को 20 साल तक सुरक्षित नहीं रख सकता है जबकि व्यक्ति उस टंकी की देखभाल स्वयं करता है। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि पक्के नालों का कार्यकाल 20 साल की बजाए 15 साल कर दिया जाये और हर 5 साल में उनकी मैंटीनेंस भी की जाये। हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश के समय बाढ़ आने का खतरा पैदा हो जाता है जबकि हर साल ड्रेनों की सफाई की जाती है और इनकी सफाई के लिए सरकार का बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है लेकिन अच्छी तरह से इनकी सफाई भी नहीं हो पाती है। इस विषय से संबंधित मेरा यह कहना है कि हरियाणा प्रदेश में जितनी भी ड्रेनें हैं, उनको पक्का करने का काम किया जाये। सारी विधान सभाओं के किसानों के बारे में तो मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन मेरे हल्के के प्रत्येक गांव में 50 परसैंट किसान खेतों में रहता है। इन खेतों में बिजली के कनेक्शन तो दे दिये जाते हैं लेकिन खेतों में लगे ट्रांसफार्मर जब ओवरलोडिड हो जाते हैं तो उनको बदलने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जाता जबकि ट्रांसफार्मर्ज ओवरलोडिड होने पर उनको बदलने का काम हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत आता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गांव के अंदर ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड होने पर उसको बदलने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है उसी प्रकार ढाणियों में भी रहने वाले लोगों से भी ट्रांसफार्मर बदलने की कीमत न वसूली जाये क्योंकि यह सुविधा मूलभूत सुविधाओं में आती है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं अपने हल्के की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनती है उसी प्रकार से मेरे हल्के की समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैंने पिछले सैशन में भी इस बारे में आवाज उठाई थी कि मेरे हल्के में बरवाला शहर में जल्दी से जल्दी बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जाये। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बार–बार रिकवैस्ट लिखकर दे चुका हूं। बरवाला का बस स्टैंड पूरी तरह से जर्जर हालत में है। बरसात के मौसम में उसके अंदर तीन–तीन फुट पानी भर जाता है। बस स्टैण्ड में पानी भर जाने के कारण बसों को बस स्टैण्ड से बाहर रूकना पड़ता है जिस कारण रोड पर जाम लग जाता है।

मेरे द्वारा बार–बार लिखकर देने के उपरांत भी बरवाला शहर के बस स्टैण्ड के निर्माण के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। मेरी पुनः परिवहन मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि मेरे बरवाला शहर में जल्दी से जल्दी नये बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जाये। इसी प्रकार से मेरे बरवाला शहर की नगर पालिका की बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। वह कभी भी गिर सकती है। बरसात के मौसम में तो नगर पालिका के कार्यालय को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे शहर बरवाला में जल्दी से जल्दी नगर पालिका की बिल्डिंग भी नई बनाई जाये। अब मैं शिक्षा के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। मेरे हल्के के साथ शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर शायद ही कोई ऐसा विधान सभा क्षेत्र होगा जिसके अंदर कोई महिला कॉलेज न हो और जिसके अंदर कोई आरोही स्कूल न हो। अगर कहीं पर कोई महिला कॉलेज नहीं होगा तो भी उसके 20 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई महिला कॉलेज अवश्य होगा। मेरे हल्के से 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई महिला कॉलेज नहीं है। मेरे हल्के से महिला कॉलेज की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर है। जहां तक आरोही स्कूल की बात है। हिसार जिले में सात ब्लॉक हैं। इन सात ब्लॉक्स में से 6 ब्लॉक्स में आरोही स्कूल हैं लेकिन मेरा हल्का आरोही स्कूल से भी वंचित है इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि आरोही स्कूल भी मेरे हल्के के अंदर शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाये। शिक्षा के क्षेत्र में यह मेरी सरकार से मांग है। मेरे हल्के में महिला कॉलेज और आरोही स्कूल दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। आरोही स्कूल के लिए सैक्टर– 14, बरवाला में जमीन थी लेकिन वहां पर आरोही स्कूल नहीं बना। मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां पर आरोही स्कूल बना दिया जाये ताकि आरोही स्कूल हमारे हल्के में भी आ जाये और हमारे ब्लॉक में भी आ जाये। मेरे बरवाला शहर के अंदर पीने के पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसके अंदर तीसरे दिन पानी दिया जाता होगा। मेरे बरवाला शहर की 60 हजार की आबादी है। वहां पर तीसरे दिन पानी दिया जाता है। गर्मी के सीजन में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा सहज में ही लगाया जा सकता है। मैंने मेरे बरवाला शहर के लिए एक टैंक की मांग की थी लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मेरे बरवाला शहर में 60 हजार की आबादी के अंदर सिर्फ तीन बूस्टिंग स्टेशन हैं जोकि निर्धारित पैरामीटर्ज के हिसाब से नौ होने चाहिएं। उपाध्यक्ष जी,

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे शहर के अंदर जल्दी से जल्दी वॉटर टैंक का निर्माण करवाया जाये और तीन नये बूस्टिंग स्टेशंज भी लगाये जायें। मेरे हल्के के चार गांव सरसौद, बिचपड़ी, झेवरा और ढ़ाणी मिरदाल ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा गम्भीर है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन चारों गांवों की पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्दी से जल्दी पाइप लाइन डाली जाये। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि डॉ. कमल गुप्ता जी के प्रयासों से हिसार के अंदर एयरपोर्ट बन गया। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजैक्ट से किसी को फायदा होता है और किसी को नुक्सान भी होता है। हिसार एयरपोर्ट का मेरे हल्के को सबसे ज्यादा नुक्सान होने जा रहा है क्योंकि हिसार एयरपोर्ट की वजह से बरवाला का रास्ता बंद होने जा रहा है। इसी प्रकार से मेरे हल्के में एक तलवंड़ी गांव है उसका भी रास्ता बंद होने जा रहा है। अभी तलवंड़ी गांव की बरवाला से दूरी मात्र सात किलोमीटर है जो एयरपोर्ट के कारण रास्ता बंद हो जाने के कारण 18 किलोमीटर हो जायेगी। मेरा माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से अनुरोध है कि तलवंड़ी गांव का रास्ता बंद करने से पहले वहां पर कोई वैकल्पिक रास्ता दिया जाये। पहले वहां पर वैकल्पिक रोड बनाया जाये उसके बाद ही उस गांव के रास्ते को बंद किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बरवाला शहर की इस समय हिसार से दूरी 30 किलोमीटर है और अगर यह एयरपोर्ट बन जायेगा तो वह रास्ता बंद हो जायेगा और जो दूसरा रास्ता मिलेगा वह 40 किलोमीटर लम्बा पड़ता है। इन दोनों रास्तों का मैंने विकल्प सुझाया है जिसमें सरकार को कोई जमीन भी एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इन दोनों रास्तों की प्रोपोजल बना कर माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को दी है। इस बारे में मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन रास्तों को बंद करने से पहले वैकल्पिक रास्ते जरूर तैयार कर दिये जायें ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। अंत में मेरी यही प्रार्थना मैंने किसान आंदोलन के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार गौर करे ताकि किसान आंदोलन समाप्त करके इज्जत से अपने घर जा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

13:00 बजे

श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो तीन बातें हैं मैं उन पर चर्चा

करना चाहूंगा। गुरूग्राम में 24 घंटे बिजली देने के लिए एक स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट चल रहा है जिसके लिए 4 टैंडर निकाले गये थे जिसके तहत 200 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। इन चार टैंडर में से टाटा को दो टैंडर दिये गये थे जिनमें से टाटा का एक प्रोजैक्ट बहुत डिले चल रहा है। इस प्रोजैक्ट को पूरा करने का टारगेट 2022 तक था लेकिन एम.सी.जी., फौरेस्ट और पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एन.ओ.सी. न मिलने के चक्कर में अभी तक इस काम में प्रगति नहीं हुई है। इसी वजह से लग रहा है कि यह काम 2025 तक पूरा हो पायेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एम.सी.जी., फौरेस्ट और पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस मामले में शीघ्रता करवा कर इस प्रोजैक्ट को जल्दी पूरा करवाया जाये ताकि लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से काफी समय पहले नैशनल मीडिया में एक बार गुरूग्राम में जलभराव के कारण लगने वाले जाम को दिखाया गया था। वाटर लौगिंग गुरूग्राम में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण पूरा का पूरा नैशनल हाईवे जाम हो गया था। इस बार भी हीरो हौंडा चौक और अंडरपास पूरी तरह से जाम हो गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एम. सी.जी. रेन वाटर हारवेस्टिंग की पिट को एक बार क्लियर कर दे जिससे हम आने वाली बारिश के लिए तैयार हो जाएं। इसके अतिरिक्त मैं शिक्षा के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। यहां हाउस में चर्चा हो रही थी कि लड़कियों के लिए 20 किलोमीटर के अन्दर कॉलेज खोले जायेंगे। इस व्यवस्था के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में माकड़ौला गांव लगता है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माकड़ौला में लड़कियों के लिए कॉलेज खोला जाए। अब मैं जो बात करना चाहता हूं वह एक अलग ही कांसैप्ट है लेकिन मैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजिज से कंसल्ट करके यह बात मैं सदन में लेकर आया हूं। श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. की 250 सीट हैं। अगर हम उसको दो शिफ्ट में चलाएं तो वे 250 सीटें 500 हो जायेंगी। इनफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमें केवल रहने की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मैं एफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के बारे अपनी बात रखना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिवैल्पमैंट, भारत सरकार की रिकमंडेशन्ज के अनुसार अगर एफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग की स्टैम्प ड्यूटी को मध्यप्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर कर दिया जाये तो लोगों को बहुत अधिक राहत मिलेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र का ज्यादातर इलाका देहात का है। इसी बात को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र

में फरूखनगर में 25 एकड़ जमीन खेल के लिए उपलब्ध है। यहां पर खेल मंत्री जी भी बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर फरूखनगर में 25 एकड़ में एक स्पोर्टस कॉम्पलैक्स बना दिया जाये तो वहां पर बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे समय में से दो मिनट का समय गौंदर जी को दे दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : राकेश जी, उनका बाद में नम्बर आएगा। ये पहले बोल चुके हैं। राकेश जी, ऐसे नहीं होता है। धन्यवाद राकेश जी।

श्री धर्मपाल गौंदर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए दो बार पर्ची भेजी है।

श्री उपाध्यक्ष : गौंदर जी, आप कल बोल चुके हो।

श्री धर्मपाल गौंदर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो ही प्वॉयंट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गौंदर जी, आपको बोलने के लिए बाद में समय दे देंगे।

श्री जगदीश नायर (होडल) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर साहब के अभिभषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बदलाव के कदम उठाए हैं। मैंने वर्ष 1996 से विधान सभा देखी है। मैं इस विधान सभा के अन्दर वर्ष 1996 में आया था। मैंने बहुत से साथी ऐसे देखे जो मेरे से बाद में आए हैं लेकिन वह कई बार बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात कर जाते हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। मैं सभी विधायक साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि हमने अपने कर्म को सही निष्ठा से निभाना है और देश और प्रदेश में बदलाव लाना है तो हमें अपनी नीयत को बदलना पड़ेगा। हम केवल हल्ला–गुल्ला–शोर मचाने को अपना कर्तव्य मानकर यहां से चले जाते हैं और इसी को अपना कर्म मान लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज बदलाव की जरूरत है। सरकार ने बहुत बदलाव भी किये हैं जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। मैं वर्ष 1996 से सदस्यों की बातों को सुनता आ रहा हूं। मैंने वे सरकारें भी देखी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना काल एक महामारी काल आया था। सारे देश की दुनिया इससे घबरा गई थी। हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी की सरकार ने हमारे देश और प्रदेश को बचाने के लिए किस तरीके से कार्य किया उनमें सबसे पहले मैं उन डॉक्टर्ज का धन्यवाद करता हूं, अपने उन सफाई कर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया है। मैं उन सफाई कर्मियों का और उन समाज सेवी

कार्यकर्ताओं का जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, कोरोना काल के समय में जब मोदी जी अपने भाषण में यह कह रहे थे कि यदि किसी ने एक कदम भी घर से बाहर रख दिया तो वह मौत की तरफ जाएगा। उस समय बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर रह कर लोगों की मदद की, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) हमने लोगों की मदद की है। आप चाहे तो मैं वह वीडियो आपको दिखा देता हूं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बात है जब कोविड फैल रहा था और उसके संक्रमण की दर 4.8 प्रतिशत पर आ गई थी। हमारे डॉक्टर्ज ने मृत्यु दर को 1.1 प्रतिशत पर ला दिया था और रिकवरी दर को 98.4 प्रतिशत पर ला दिया था। आज अध्यक्ष महोदय व मंत्री जी बैठे हुए हैं उन कर्मचारियों को इनाम देना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने कोरोना के भयंकर काल में काम किया था। आप लोग उन लोगों की बात नहीं करते हैं। आप लोग तो केवल अपनी–अपनी पार्टियों को चमकाने की बात करते हैं। वह ऐसा टाईम था कि कोई पैसे से भी दूसरे की मदद नहीं करना चाहता था लेकिन उन लोगों ने मदद की है। आज मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देकर उन गरीब घरों में अनाज पहुंचाया था। उन गरीबों के घरों में सामान पहुंचाया था जो यह इंतजार कर रहे थे कि हम खाना कहां से खाएं? एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि सभी के घरों में खाना निवरने लगा था। सरकार ने सार्वजनिक व वितरण प्रणाली शुरू करके हर घर में अनाज पहुंचाने का काम किया है जो चीजें सरकार में लिस्टिड थी। जैसे दाल, चीनी, चावल, गेहूं, भेजकर सरकार ने उन लोगों का जीवन यापन चलाया। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। ऐसी संकट की घड़ी में लोगों को साथ लेना। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन की खोज करना यह कोई छोटी चीज नहीं है। दुनिया में त्राही–त्राही मच रही थी। उस समय पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश को संभाला इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने कभी रामायण सुनी होगी रामायण में आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी वहां बूटी लेकर आए थे। वही बूटी लेकर हमारे प्रधान मंत्री जी सारी दुनिया में बांट कर आए हैं । मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज वैक्सीन की खोज हो चुकी है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का ही यह परिणाम है कि आज टीकाकरण अभियान को पूरे जोर–शोर से चलाया जा रहा है। लोगों के दिल में एक वहम था कि कोरोना महामारी के कारण अब वे

नहीं बचेंगे लेकिन टीका लगने के बाद आज लोगों के दिल में एक विश्वास पैदा हुआ है। यह दुनिया विश्वास पर चलती है। हरियाणा सरकार द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। यह छोटा बदलाव नहीं है। यह बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों की भलाई के लिए तथा मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाया और लोगों के जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस कोष से 17 लाख परिवारों को 730 करोड़ रुपये की मदद की गई जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहेदिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8 लाख 76 हजार लोगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 270 करोड़ रूपये, 250 करोड़ रूपये तथा 175 करोड़ रूपये देकर सरकार ने लोगों के जीवन यापन को सुधारने के लिए मदद दी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल की बात बताता हूँ। उस समय मजदूर भाइयों में बहुत भय का वातावरण बन चुका था। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ और अगर झूठ बोलूं तो भगवान मुझे इस सदन में कभी भी न आने दे, मेरे घरवाले तक मुझे कहने लगे थे कि कोरोना फैल रहा है तू घर में कोरोना लेकर आयेगा, उस समय की बात बताता हूँ, हमने स्वयं मजदूरों के बीच में जाकर उनको उनके गंतव्य तक जाने वाली गाड़ियों में चढ़वाने का काम किया, उनको खाने के पैकेट बांटने का काम किया। मजदूरों का विश्वास टूट चुका था कि अब कोरोना काल में कौन उनकी मदद करेगा लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी हरियाणा सरकार ने उन गरीब मजदूरों का पेट भरने का काम किया और उनको उनके गंतव्य तक ले जाने वाली गाड़ियों में बिठाकर घर भेजने का काम किया। यह हरियाणा सरकार का एक अनोखा कदम था। आज हरियाणा में बिजली, पानी, शिक्षा व रेल लाइन बिछाने के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। बिजली के बारे में हम वर्ष 1996 में सुना करते थे कि 24 घंटे बिजली आयेगी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद वर्ष 2005 से लेकर 2009 तथा उसके बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और यह लगातार कहते रहे कि 24 घंटे बिजली देने का काम किया जायेगा लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया लेकिन आज बिजली के क्षेत्र में नया बदलाव लाया गया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तथा गठबंधन सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के 50 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम पूर्ण हो चुका है और जल्द ही हरियाणा में दूसरी

जगहों पर भी यह काम पूर्ण होता दिखाई देगा। यही नहीं हरियाणा में 61 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का काम किया गया है। 550 करोड़ रुपये की लागत से 1217 किलोमीटर लंबाई वाली नई सड़कें बना दी गई हैं। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है? कांग्रेस पार्टी के लोग शोर मचाकर हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जहां तक घोटालों की बात है, क्या कांग्रेस पार्टी के भाई 2009 से 2014 के बीच हुए सी.एल.यू. घोटाले को भूल गए है? किंगडम ड्रीम की रिपोर्ट निकालकर दे सकता हूँ जिसमें दिखाया गया है कि यह 3000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ था। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो मैं इस विषय पर प्रस्ताव लेकर आ सकता हूँ? यह जमीन कांग्रेस पार्टी के लोगों के नाम है। अध्यक्ष महोदय, इनके शासन काल में जमीनी घोटाला हुआ, नौकरियों में भर्ती घोटाला हुआ और न जाने कौन–कौन से घोटाले हुए। यह लोग मजदूरों के मसीहा बनने की बात करते हैं। मैं इनकी सच्चाई बयान करता हूँ। इन लोगों ने तो वर्गों को बांटने तक का काम किया था। एस.सी.(ए) वर्ग को खत्म करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, गुरूग्राम में मजदूरों पर लाठी बरसाने का काम किसने किया था, इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। गोहाना के अंदर किसने कांड किया था, इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। इनको उस समय को नहीं भूलना चाहिए। उस समय की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के समय में शिक्षा का भट्ठा बैठ गया था। पैसे से डिग्रियां बिका करती थी, नौकरियां बिका करती थी और आज यह लोग सुझाव दे रहे हैं? यह देखकर बड़ा दुख होता है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के सरकार के नए कदमों व नए बदलावों की सराहना करनी चाहिए। अब मैं अपने किसान भाइयों की बात करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छोक्करः अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि नागरिक अस्पतालों में एक्सरे तक की मशीनें नहीं है और अगर कहीं हैं तो खराब पड़ी हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री जगदीश नायर जी, प्लीज आप जल्दी वाइंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में नागरिक अस्पतालों और शिक्षा की क्या दुर्दशा है, यह सभी को पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन गीता जी, कृपया करके आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप लोग हाउस को चलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, अपने बोलने के समय में ही बोले लेकिन दूसरे माननीय सदस्य के समय में बीच–बीच में टोका–टाकी न करे। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि सरकार के कामों में ये–ये कमियां हैं और सत्ता पक्ष के सदस्य कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासन काल में इस तरह के भ्रष्टाचार के काम हुआ करते थे। (शोर एवं व्यवधान) कोई भी सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य के बीच में न बोले केवल और केवल अपने समय में ही बोले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सच्ची किसान हितैषी है और किसानों की भलाई के लिए ही सोचती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि किसानों को बहकाना बंद कीजिए और उनकी भलाई के बारे में सोचिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी पर पुल बनाने की घोषणा पिछली बार हुई थी, मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि लाखों श्रद्धालु ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा करने के लिये आते हैं, इसलिए यह पुल बनाना बड़ा ही जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव गढ़ी में रैगुलेटर बनाया जाता है तो कई गांवों की सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त हो सकती है। इसके साथ–साथ मेरे हसनपुर में नया बस स्टैण्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, इसलिए इस नये बस स्टैण्ड को भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहुत सारे सदस्यों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाने बाकी हैं और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान भी होना है, इसलिए यदि सदन की सहमति हो तो आज सदन की दूसरी बैठक दोपहर बाद 2:35 बजे से शुरू कर ली जाये।

आवाजें: ठीक है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आज सदन की दूसरी बैठक मध्याह्न पश्चात् 2:35 बजे आरम्भ होगी। बत्तरा जी, अब आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखें।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका अति आभारी हूं । माननीय सदस्य श्री जोगी राम सिहाग ने एम.एस.पी. और कृषि बिल का जिक्र किया है । जब यह बिल सदन में पेश हुआ तो इसको हाइपर टैक्नीकल करके टैक्नीकल ग्राउंड पर जो किया गया वह लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल ठीक नहीं हुआ । वह बिल सभी धाराओं पर खरा उतरता था और बिजनेस रूल्ज के मुताबिक सैक्रेटरी, लॉ डिपार्टमैंट की ओपीनियन के बाद उसको इस सदन में आना चाहिए था । इस बात का जे.जे.पी. भी सपोर्ट करती है कि यह बिल सदन में आना चाहिए था । स्पीकर सर, अब मैं सिर्फ समराइज करता हूं कि सैक्रेटरी, लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन है कि – The subject matter of the proposed legislation is relatable to the . . .

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अभी आप जो कह रहे हैं वह आप पहले भी कई बार कह चुके हैं । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी, लॉ डिपार्टमैंट का यह ओपीनियन बाद में आया है । (विघ्न) अब मैं समराइज करता हूं । यह बिल सैक्रेटरी, लॉ डिपार्टमैंट के ओपीनियन के बाद सदन में पेश होना चाहिए था । इसमें संविधान से संबंधित भी कोई अड़चन नहीं थी । अगर सदन इस बिल को पास करता तो फिर इसको ऑनरेबल प्रैजीडैंट के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता । सिर्फ इतनी–सी बात थी । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि Speaker Sir, you are the custodian of the House. अगर आपको किसी चीज से ऐतराज था तो आपको इस बिल को रिजैक्ट करना चाहिए था और हमसे कहना चाहिए था कि आप इस बिल को अमैंड कर दीजिए । That is a proper procedure.

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप हमारे पास कोई बिल भेजो तो उसे टैक्नीकली आस्पैक्ट्स से चैक करके भेजा करो । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय पर बोलता हूं अदरवाइज मेरा समय समाप्त हो जाएगा । जहां तक एम.एस.पी. की बात है मैं सदन में कहना

चाहता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार के समय में कांट्रैक्ट फॉर्मिंग का लॉ हरियाणा में आ चुका था । आज केन्द्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं । मेरा कहना है कि ए.पी.एम.सी. और एम.एस.पी. आदि सब चीजें हमारी ज्यूरीडिक्शन में थी । चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सैक्शन 8'ए'1' को उसके अन्दर लेकर आये थे । Speaker Sir, section 8(a)(1) of The Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 says that-

(1) Any contract farming sponsor shall register himself with the Committee.

सैंटर के लॉज के अनुसार अब कोई भी ए.पी.एम.सी. के अंडर आने को तैयार नहीं है । उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने वर्ष 2008 में कांट्रैक्ट फार्मिंग को डिफाइन करवाया था । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे नहीं हैं । मैं इस समय कांट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित बेसिक प्वॉयंट बता रहा हूं । इसमें बेसिक प्वॉयंट यह था कि प्राइवेट प्लेयर्स को किसान को एम.एस.पी. देनी पड़ेगी और साथ ही साथ ए.पी.एम.सी. में अपने आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा । मैं आपको रूल–16 एक पढ़कर सुनात हूं । Rule 16A of The Punjab Agricultural Produce Markets (General) Rules, 1962 says:-

"16A. Registration of contract farming

(1) Any Contract farming sponsor intending to register himself under section 8A of the Act shall apply in Form A-I to the Secretary of the concerned Market Committee."

मेरा कहना है कि हमारे यहां पर पहले से ही यह कानून था और हमने सिर्फ उसी कानून को फॉर्टीफाई करने के लिए और आगे ले जाने के लिए यह प्रावधान रखा था कि जहां पर वॉयलेशन हो वहां पर पनिशमैंट दी जाए । एम.एस.पी. को तो सरकार ने ऑलरेडी अपने एग्रीमैंट में अनाउंस किया हुआ है । आदरणीय हुड्डा साहब के समय में पहले बैंक गारण्टी की भी बात थी और उस ऐग्रीमैंट के रजिस्टर करने की भी बात थी । स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से कांट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमैंट को पढ़ता हूं । इसमें एग्रीमैंट का प्वॉयंट 16A का सीरियल नं. 6 कहता है –

(6) The Contract farming agreement between the contract farming sponsor and contract farming producer shall be in Farm C-I and it shall be got registered with the District Marketing Enforcement Officer concerned in the presence of both the parties. The agreed rate/contract rate shall not be less than minimum support price of the preceding year.

यह हरियाणा सरकार का कानून है और हम इसी कानून को सप्लीमैंट कर रहे हैं।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब सरकार एम.एस.पी. पर फसलें खरीद रही है तो कोई भी किसान अपनी फसल दूसरे राज्यों में ले जाकर क्यों बेचेगा ? इस कानून की आवश्यकता ही नही थी।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार तो यह कानून लेकर आयी थी कि एम.एस.पी. की वॉयलेशन करने पर पनिशमेंट होगी।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब हरियाणा सरकार एम.एस.पी. पर किसानों की फसलें खरीद रही है तो आप बाहर वालों के लिए कानून बना रहे कि अगर कोई एम.एस.पी. से नीचे फसल खरीदेगा तो उसको सजा देंगे। आप करना क्या चाह रहे थे ? आप इस बात को क्लीयर कर दें कि आप क्या करना चाहते थे ? जब सरकार एम.एस.पी. पर फसल खरीद रही है तो इस कानून की क्या जरूरत है ?

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से रिकवेस्ट करना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ0 साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री भारत भूषण बतराः Speaker Sir, I will request Dr. Abhe Singh Yadav to seek time to speak from the Chair. He should not speak in between. It is not fair. He should address to the Chair. He can't question me directly.

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह कानून है ?

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यह कानून एट प्रजैंट है। हम यही कह रहे हैं कि आप उस एक्ट को पनिशेबल बनाएं, परन्तु किसी ने उस एक्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं की। इसमें प्रावधान यह है कि एम.एस.पी. से कम रेट पर कोई फसलें नहीं खरीदेगा और कोई खरीदता है तो उसकी सजा होगी। सिर्फ यही कानून था। (विघ्न) Let me say. My time is running. Speaker Sir, please protect me.

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बता दें कि क्या इनकी सरकार के 10 सालों के समय में किसी के ऊपर कार्रवाई की गयी थी ?

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 मई, 2016 को इसी रूल को अमैंड करके जो पहले 15 प्रतिशत बैंक गारंटी थी, उसको कम करके 5 प्रतिशत कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आज भी कानून के मुताबिक प्राईवेट प्लेयर को मार्केट कमेटी के एक्ट में आना पड़ेगा और वह एम.एस.पी. से नीचे फसलें नहीं खरीद सकता। हम चाहते हैं कि इसको पनिशेबल ऑफैंस बनाया जाए। यह बहुत ही क्लीयर बात थी, परन्तु इसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। इसके अतिरिक्त मैं एक लाइन सैंट्रल एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि यह एम.एस.पी. के सारे प्रॉविजन को नलिफाई कर रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि उसमें अलग यार्ड, स्टोरेज आदि की व्यवस्था की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री जोगी राम सिहाग जी को कहना चाहूंगा कि वे अपनी पार्टी को कहें कि इस कानून को लेकर लाएं और इसको पनिशेबल ऑफैंस बनाएं। अभी माननीय सदस्य किसानों की भलाई की बात कर रहे थे। माननीय सदस्य इस गठबंधन की सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें इस बात को रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला प्वॉयंट यह है कि आपने विधान सभा के परिसर के अन्दर गीता का अनावरण किया है। क्या सरकार गीता के प्रिंसिप्लज को फॉलो करती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गीता का पहला शब्द 'धर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे' है। उस धर्म का मतलब हिन्दू धर्म नहीं है बल्कि उस धर्म का मतलब राजधर्म है। सरकार कैसे चलेगी और लोग किस प्रकार से सुखी होंगे। किस प्रकार से मुकद्दमें चलाये जाएंगे और किस प्रकार से न्याय किया जाएगा ? यह बात गीता के उपदेश की पहली लाइन है। यह भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। मैं यह बात कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि यह घोटालों की सरकार है। इसमें छात्रवृति घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, अमरुत स्कीम घोटाला, स्वच्छ भारत मिशन घोटाला, शुगर मिल घोटाला हुआ है। ये इतने घोटालों की सरकार है कि कहा नहीं जा सकता। यह सरकार गीता के उपदेश और मान्यताओं को मानने वाली कहां से है ? हम इस गीता को नमस्कार करके ही हाउस में एंटर करते हैं और हमें हाउस में घोटालों की सरकार बैठी मिलती है। इसके बाद एक मेन बात और कहना चाहूंगा और उसके बारे में कम प्वॉयंट्स पर ही चर्चा करूंगा।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपके बोलने के लिए एक मिनट का ही समय बचा हुआ है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, मैंने यह टाईम लिखा हुआ है। आपसे पहले वाले माननीय सदस्य ने 1:18 बजे अपनी बात खत्म की थी और आपने 1:20 बजे बोलना शुरू किया था।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में से 4 मिनट तो माननीय मंत्री जी ही बोले हैं। (विध्न)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

————————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि जो आजकल नौकरियां देने के लिए कमीशन बना रखा है, उसने पूरे प्रदेश के युवाओं का भट्ठा बैठा दिया है। पंचकूला पुलिस स्टेशन में पैसों से रिलेटिड एफ.आई.आर. नम्बर 189 दर्ज हुई जिसमें कई अधिकारी और पदाधिकारी शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि यह बहुत बड़ा स्कैम है। मैं माननीय हाई कोर्ट की एक जजमैंट को सदन में पढ़ना चाहता था लेकिन उसमें सदन का काफी समय लग जाता। रिक्रूटमैंट बोर्ड की जो फंक्शनिंग है, उसको क्यों स्पेयर किया गया? मेरी मांग है कि इसकी सी.बी.आई. इन्क्वायरी होनी चाहिए। इस बात से साबित हो जाता है कि यह कितना सक्षम है। सरकार ने पी.टी.आई. टीचर के ऊपर कितनी ज्यादती की है क्योंकि सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में ढंग से अपना पक्ष नहीं रखा। इस सरकार ने उनका कैरियर बर्बाद करके रख दिया है। वर्ष 2015 में टी.जी.टी. इंग्लिश की ऐडवर्टाइमैंट की गई थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर इसकी कम्पीटेंसी कहां पर गई? माननीय हाई कोर्ट में इसके लिए 5–5 साल तक मुकद्दमे

चलते रहते हैं और जब आखिरी दिन माननीय हाई कोर्ट ने फैसला देना होता है तब सरकार एक दिन पहले इन पोस्टों को विदड्रा करने का काम करती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों ने आखिर क्या कसूर कर दिया? उन बेचारे बच्चों ने पहले फार्म भरा और उसके बाद टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद इन्टरव्यू भी पास किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसी तरह से 1035 इंग्लिश टीचर का भी यही हाल किया और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का भी यही हाल कर दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में उन स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा? आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि सरकार कहां पर एक्सपैरीमैंट करती है, बीच में ही अमैंडमैंट करते हैं और बीच में ही कॉरिजेन्डम डाल देते हैं और अंत में जाकर उसको रिवर्स कर दिया जाता है। यह कमीशन की वर्किंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि इतनी खामियां होने के बाद भी इस महीने के अंदर 1700 पोस्टें विदड्रा की गई हैं। वे पोस्टें किस कारण से पोस्टें विदड्रा की गई हैं? मैंने इसके लिए एक कॉलिंग अटैंशन मोशन भी दिया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस कॉलिंग अटैंशन मोशन को मंजूर करवा देंगे तो प्रदेश की जनता के सामने सभी बातें शीशे की तरह साफ हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक ही डिमांड रखूंगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। हमारे यहां पर एक काठमंडी है। सरकार उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रही है। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 95 करोड़ रुपये की लागत से 112 एकड़ जमीन का एक्विजीशन हुआ था। सरकार ने जो अनुमानित डाटा दिया है उसमें 22 करोड़ रुपये के लगभग खर्च दिखाया गया है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी और मैंने इस मामले के बारे में पूरी जानकारी भी दी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप अपनी बात जल्दी से जल्दी सम–अप करें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो काठमंडी को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है तो वहां पर जमीन का रिजर्व प्राइज 30 हजार रुपये से 34 हजार रुपये के बीच रखा गया है जबकि वास्तव में उसका मार्केट रेट 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता भी है और उन्होंने मुझे इस बारे में आश्वासन भी दिया था परन्तु उस आश्वासन का कोई अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दिया है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि

अगर सरकार वह 30 हजार रुपये से 34 हजार रुपये के बीच में बेचना चाहती है तो वहां पर कोई भी आदमी रहने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वहां पर न तो इतना ज्यादा रेट है। जहां तक काठमंडी को और उसके साथ में लगते हुए ऑटो मार्केट को शिफ्ट किया जा रहा है उस जमीन का रेट 10 हजार रुपये के हिसाब से निश्चित किया जाये तो बेहतर रहेगा।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन दिनांक 9 मार्च, 2021 दोपहर 2.35 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*13:35 बजे

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 दोपहर बाद 2.35 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)